

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा**

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

20.03.2026/1100/RKS/AG-1

**अध्यक्ष :** प्रश्नकाल आरंभ।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब, आप अपना विषय प्रश्नकाल के बाद उठा लेना। ...(Interruption)।  
I will give you time. ...(व्यवधान) ऐसा है न प्रेसिडेंट गलत हो जाएगा। ...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी हमारे ही लगे हुए हैं परंतु यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब, प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण है। सभी माननीय सदस्य मेरे चैम्बर में आकर मुझे प्रश्न काल चलाने के लिए कहते हैं। जब उनके प्रश्न नहीं लगते हैं तो वे मेरे पास रिजेंडमेंट भी शो करते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर :** सर, मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में रखूंगा। ...(व्यवधान) आज सारी अखबारें भरी पड़ी हैं कि 'नशा तस्करों को पकड़ने वाले खुद गिरफ्तार'। आखिरकार यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या : 3538, ठाकुर साहब कृपया बैठ जाइए। आप अपना विषय प्रश्नकाल के बाद उठा लेना। I will give you time. ...(व्यवधान) मैं आपको प्रश्न काल के बाद इस विषय को उठाने का समय दूंगा। ...(व्यवधान) आपके विषय का जवाब सरकार देगी। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, अभी आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। ...(व्यवधान) पहला प्रश्न माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का है और ये मुझसे बहुत नाराज थे कि मेरे प्रश्न नहीं लग रहे हैं। ...(व्यवधान) Please, please. I am not allowing you. ...(व्यवधान) मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का समय दूंगा। अगर आप इस विषय पर कोई विशेष डिस्कशन लाना चाहेंगे तो मैं उसकी भी इजाजत दूंगा। ...(व्यवधान) आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर फिर से आगे चर्चा होनी है और उस चर्चा में

ये सारे रेफरेंसिज आ सकते हैं। ...(व्यवधान) ये प्रेसिडेंस ठीक नहीं है। विधान सभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसको deviate नहीं किया जा सकता।  
...(व्यवधान)

20.03.2026/1100/RKS/AG-2

**(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)**

कृपया आप सब बैठ जाइए। ठाकुर साहब, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का समय दूंगा। ...(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। Please, please. No, no. Order in the House please. Please take your seats. ...(व्यवधान) I am not allowing it. ...(व्यवधान) I will allow you after the Question Hour. ...(व्यवधान) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. Order in the House please. Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) ठाकुर साहब मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

**(कांग्रेस विधायक दल के कुछ सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)**

ठाकुर साहब, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का पर्याप्त समय दूंगा।...(व्यवधान) आप सब बैठ जाइए। ...(व्यवधान) परमार जी, आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और आपको मालूम है कि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान माननीय सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है इसलिए आप प्रश्नकाल के बाद अपना विषय रख लेना। मैं आपको बाद में बोलने का पूरा समय दूंगा। ...(व्यवधान) मैं आपको समय देने के लिए इंकार नहीं कर रहा हूँ। I will give you time. अगर आपके अलावा कोई और सदस्य इ विषय में बोलना चाहेगा तो मैं उनको

भी बाद में बोलने का समय दूंगा। I will allow all of you after the Question Hour.  
...(व्यवधान)...(व्यवधान) This is a wrong precedent. ...(व्यवधान)

श्री बी०एस० द्वारा जारी.....

20.03.2025/1105/बी.एस./ए.जी.-1

अध्यक्ष जारी...

यदि कोई ऐसा कोई मोशन है तब तो मैं मानता हूँ, कोई ऐसा मोशन है जिसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं, आप कोई इशू रेफर करना चाह रहे हैं तो that is not within the purview of the rules, but still I will use my discretion in your favour. Please bear with me. मैं आपसे कह रहा हूँ कि I will use my discretion with you, yet there is no provision in any of the rules.

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, क्या हमें शून्य काल में अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा?

**अध्यक्ष :** हां, मैं शून्य काल में आपको समय दूंगा। कृपया प्रश्नकाल शुरू होने दें।

20.03.2025/1105/बी.एस./ए.जी.-2

### **स्थगित प्रश्न संख्या 3583**

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना है इसमें थोड़ा और फेक्चुअल करेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि यह सूचना में थोड़े और तथ्य रह गए हैं। अभी विधान सभा का जो अगला सत्र होगा तो उसमें दोबारा से इसको प्रस्तुत कर देंगे।

**अध्यक्ष :** यानी जो सूचना दी गई है इसे और अमेंडिड कर सूचना दी जाएगी।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, और अमेंडिड सूचना प्रदान की जाएगी।

**श्री सतपाल सिंह सत्ती :** अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने यहां किया है इस बारे में अनेकों बार यहां पर चर्चा भी हुई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे अनेकों भवन हैं जो करोड़ों और अरबों रुपये से बनाए गए हैं। परंतु आज की तारीख में वे खाली पड़े हैं या गलत जगह पर बना दिए गए हैं, जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसे भवनों को चिन्हित करके उन भवनों का क्या उपयोग हो सकता है? एक तो उस दिशा में हम लोगों को जाना चाहिए और दूसरा विषय ऐसा भी ध्यान में आता है कि कई बार ऐसे स्थानों के ऊपर ऐसे भवन बना दिए जाते हैं। उसके लिए जो अथॉरिटी जिम्मेदार रहती है, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा तो यह भी मानना है कि उसमें पॉलिटिकल आदमी भी कोई इन्वॉल्व रहता है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उस आदमी को क्या पता नहीं है कि यह भवन 2-5-10 करोड़ रुपये का बन रहा है और इसका उपयोग कोई नहीं होगा। आने वाले टाइम में भी जब भवन बनेंगे तो क्या उसकी कोई गाइडलाइन जारी करेंगे? यदि ये तथ्य पूरे करते हों तब जाकर के उन भावनाओं का निर्माण होगा? वरना अरबों रुपया लोगों का, गरीब लोगों का खर्च हो रहा है। जो आज हमारी आर्थिक दशा बिगड़ी है, उसमें ऐसी चीज जिम्मेवार है।

दूसरा, इसमें एक और विषय आता है, मुख्य मंत्री जी, क्योंकि भवन बन रहे हैं हमारे लोअर हिमाचल में भी अनेकों भवन बन रहे हैं। मैं देखता हूं जहां लेंटर पड़ा है, आम आदमी लेटर के ऊपर टीन नहीं डाल रहा है। लेकिन हमारे जो सरकारी भवनों के एस्टीमेट्स जा रहे हैं, उनके साथ ऊपर टीन का प्रावधान है। मैंने अपने एरिया के अंदर अनेकों भावनाओं के ऊपर टीन के प्रावधान को रुकवाया कि जब लोअर हिमाचल के अंदर

20.03.2025/1105/बी.एस./ए.जी.-3

इस लेवल की बारिश नहीं होती है। मान लीजिए शिमला, अपर शिमला है, कांगड़ा का ऊपर का एरिया है, मण्डी है, कुल्लू है, कुछ इलाके हिमाचल के ऐसे हैं जहां टीन भी डालनी पड़ती है। तो उसके ऊपर 40-40 और 50-50 लाख रुपये की टीन और बड़े-बड़े मोटे एंगल्स किसके कहने पर डाले जा रहे हैं? क्या इसके बारे में भी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करेंगे? मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे विचार और सुझाव दिए हैं। और इन सुझावों पर हमारी सरकार विचार करेगी और माननीय सदस्य ने सही कहा कि कई जगह ऐसे भवन बन जाते हैं जिनकी कभी जरूरत नहीं होती। पॉलिटिकल दबाव भी बहुत होता है। यह सब चीजें विचार करने की हैं। आने वाले समय पर इन सब चीजों पर विचार किया जाएगा। जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिए और जहां कुछ करने का होगा उसे उस दृष्टिकोण से करेंगे

20.03.2025/1105/बी.एस./ए.जी.-4

**स्थगित प्रश्न संख्या 3583**

**श्री विक्रम सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि सरकार अभी सूचना एकत्रित कर रही है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, सूचना दे दी गई है। आप अपना पोर्टल ध्यान से नहीं देखते हैं।

**श्री विक्रम सिंह :** अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मुझे पता नहीं चला। मैं इसको पढ़ कर फिर दोबारा टाइम लूंगा और नियम-61 में फिर से प्रश्न करूंगा। कृपया मुझे तब समय देने की कृपा करें।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.03.2026/1110/DT/AS-1

**प्रश्न संख्या 3946**

**डॉ० जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उस सूचना के "ख" भाग में लिखा गया है कि यह भी सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 8 घंटे की ड्यूटी हेतु 15000/- रुपये इन-हैंड वेतन देने के आदेश पारित किए गये हैं: यदि हां, तो क्या इनको यह वेतन दिया जा रहा है; यदि नहीं, तो कारण? और जवाब में लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 15000/- टेक-होम वेतन प्रदान करने का निर्देश

दिया था और यह निर्देश कंपनी के संदर्भ में दिया गया था। वर्तमान में दूसरी कंपनी आ गई है उनको उनकी शर्तों के अनुसार भुगतान करने के बारे लिखा गया लेकिन यह सारा विषय याचिका नम्बर सी0डब्ल्यू0पी0 2094/2021 से माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में लंबित है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

**डॉ0 जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं एक अनुपूरक प्रश्न भी सरकार से पूछना चाहूंगा कि जो लोग पिछले पन्द्रह सालों से हिमाचल प्रदेश में बीमार, घायल, गर्भवती महिलाओं की जान बचाने का काम कर रहे हैं क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी या इस सदन में यह आश्वासन देगी की जो कर्मचारी 108 या 102 एम्बुलेंस सेवा में काम कर रहे हैं उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की जिम्मेवारी यह सरकार उठाने के लिए तैयार है?

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, नेशनल हैल्थ मिशन के द्वारा संचालित दोनों सेवाएं के संदर्भ में जो माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है, वे बातें जनहित से जुड़ी हैं। मैं स्वयं भी बीच-बीच में 108 व 102 के कर्मचारियों और संचालकों की बैठक बुलाता रहता हूं। यह बैठक संचालन और रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए की जाती है। जो माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं that they are being paid 15000/- per month और यह इनकी टेक-अवे होम सैलरी है। चूंकि पहले वाली कंपनी जी0वी0के0 ई0एम0आर0आई0 अब प्रदेश से चली गई है और अब दूसरी संस्था प्रदेश में कार्य कर रही है जिसका नाम Medswan Foundation है, उनके द्वारा इस पर संतुष्टि न जाहिर करते हुए they have gone to the Court and as per the orders passed by the Labour Court that how to employee these people, they were not happy so this thing is now उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 26 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई है। न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश सरकार को दिए जाएंगे हम उसका पालन करेंगे।

20.03.2026/1110/DT/AS-2

प्रश्न संख्या 3947

**श्री राकेश कालिया** : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते हैं कि केंद्र का सहयोग न होने के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति में कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अपने उत्तर में जो 16 लाख रुपया दिखाया गया है यह पैसा विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था और इस पैसे को विद्धा भी कर लिया गया था। प्रदेश की ऐसी वित्तीय स्थिति में भी माननीय मुख्य मंत्री जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मैं उनके कार्य की सराहना करता हूं। लेकिन जो पैसा विभाग को वापिस हुआ था यह पैसा जिस संस्थान के लिए आबंटित हुआ था वह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है और यहां पर एंटी रेबीज इंजेक्शन, स्नेक बाइट के इंजेक्शन और पैरालाइजिसिस के इंजेक्शन की आवश्यकता रहती है और इन सभी इंजेक्शन को लगभग 2 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। लेकिन उस संस्थान में जनरेटर न होने के कारण लोगों इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा देने में असर पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यही आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप इस जनरेटर के लिए पैसा पुनः सेंक्शन कर देंगे और जनरेटर क्रय करने के आर्डर भी कर दें।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, जो चिंता माननीय सदस्य द्वारा अपनी विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान के संबंध में जताई गई है I am fully agree with him. हमें जनरेटर के लिए 16,36,500/- रुपये का एसटिमेंट प्राप्त हुआ था और इसे 9 मार्च, 2026 को वापिस सेंक्शन कर दिया गया है and I assure the Hon'ble Member कि जनरेटर की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

20.03.2026/1115/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-3947.....जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पश्चात..... जारी

**श्री राकेश कालिया** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी कहा कि यह एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है और इसमें अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा। यह संस्थान बोर्डर ऐरिया में है और लोग समझते हैं कि यहां पर सभी पद भरे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि यहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सभी सात पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एम0डी0 मेडिसन, गायनेकोलॉजिस्ट आदि जैसे जरूरी डॉक्टर्स की नियुक्ति वहां पर अवश्य कर देंगे ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री के अथक प्रयासों से हेल्थ सैक्टर में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि चिकित्सकों के 232 पदों को भरने की रिक्विजिशन दे दी गई है। इसके अलावा 150 स्टाफ नर्सिस की भी रिक्विजिशन दे दी गई है। Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation Limited को भी 500 रोगी मित्रों को भर्ती करने की रिक्विजिशन दे दी गई है। फार्मासिस्ट के 62 पदों और रेडियोग्राफर के 30 पदों की भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। ओ0टी0ए0 के 145 पदों को भरने की रिक्विजिशन राज्य चयन आयोग को भेज दी गई है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य की स्टाफ को लेकर चिंता बिल्कुल वाजिफ़ है। **I assure him that I shall personally look into it and they are given.**

20.03.2026/1115/ए.एस.-एन.जी./2

**प्रश्न संख्या - 3948**

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके व इस माननीय सदन के माध्यम से दरंग विधान सभा क्षेत्र की जनता की पीड़ा, चिंता व आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। मुझे दरंग विधान सभा क्षेत्र की आम जनता के लिए खुशी है कि केन्द्र सरकार के

माध्यम से फोरलेन का कार्य चला हुआ है और उस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मैं लोक निर्माण मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि कितने मकानों, दुकानों अथवा अन्य निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। इसका जवाब आया है कि 244 मकानों/दुकानों/निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 2044 परिवारों को अभी तक कुल 441.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 30.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी उसका पैसा तो आपने उनको दे दिया है लेकिन बहुत खेद की बात है कि इस फोरलेन के कारण 80-90 मीटर ऊंचाई तक कटिंग की गई है। जहां पर मकान नजदीक थे वहां पर 4-5 मीटर अधिक कटिंग की गई है। उन परिवारों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप क्या जानना चाहते हैं?

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जिनकी जमीन जा रही है या चली गई है और जिनका मुआवजा नहीं मिला है, उनका मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा? मैं स्वयं मौके पर गया था और वहां पर तहसीलदार भी आए थे।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपका प्रश्न आ गया है।

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, कृपया बोलने दीजिए। वहां पर तहसीलदार और एन0एच0ए0आई0 के अधिकारी आए थे।  
श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

20.03.2026/1120/ए.पी./डी.सी./01

प्रश्न संख्या 3948 जारी .....श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जारी.....

वे आश्वासन के इलावा कुछ नहीं करते हैं। काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इनमें ऐसे भी घर हैं जिन घरों के साथ में ही सड़क बनी है और वहां पर कच्ची दीवारें लगाई जा रही हैं। आपने देखा ही है कि वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में किस तरह से प्रदेश में त्रासदी आई है।

**अध्यक्ष :** माननीय ठाकुर साहब आपका कनसर्न आ गया है।

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, उन घरों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

**लोक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जी काफी लम्बे समय के बाद विधान सभा में आये हैं तो सारी-की-सारी कसर इसी प्रश्न में निकालना चाहते हैं, अच्छी बात है। मसला तो वैसे एन0एच0ए0आई0 का है मगर फिर भी यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि प्रदेश में यह कार्य हो रहा है और एन0एच0ए0आई0 के कार्यों का निरक्षण लगातार हमारी सरकार पूरे मजबूती से कर रही है। जिस मसले के बारे में माननीय ठाकुर साहब ने जिक्र किया है, इसके बारे में जो एन0एच0ए0आई0 का क्षेत्रिय कार्यालय है उन्होंने हमें जानकारी दी है और माननीय सदस्य ने भी कहा है कि यह सड़क जो मंडी-पठानकोट सैक्शन का मंडी-नारला फोरलेन सड़क है उसके निर्माण कार्य के दौरान कुल 2044 परिवार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं Right of Way के बाहर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन और शिकायतों के जांच के आधार पर कुल 32 स्ट्रक्चर्स/भवनों क्षति हुई है और इसमें से एक भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा 31 स्ट्रक्चर्स/भवनों को नुकसान हुआ है या होने का अंदेशा है। एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रदेश के फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान Right of Way से बाहर प्रभावित लोगों की क्षतिग्रस्त भूमि स्ट्रक्चर्स/भवनों आदि मसलों बारे मुद्दे के निवारण हेतु सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.06.2020 के द्वारा संबंधित जिलाधीश की

20.03.2026/1120/ए.पी./डी.सी./02

अध्यक्षता में समिति को गठन के लिए भेज दिया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रभावित परिवारों के लिए मु0 475 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 2.5 प्रतिशत contingency charges भी इसमें शामिल है। कुल स्वीकृत राशि में मु0 441.88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है तथा मु0 30.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना शेष है, जोकि न्यायपालिका की वजह से रूका है और इसका भुगतान आने वाले समय में करवा दिया जाएगा। ठाकुर साहब इसके अलावा भी आपका कोई कनर्सन होगा तो आप हमें उस बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम एन0एच0ए0आई0 के रीजनल ऑफिसर और मंडी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से हम इस विषय को टेक अप करेंगे। डैमेज कई जगहों पर हुआ है और हम इसे स्वीकार करते हैं। लगातार हम जनप्रतिनिधियों की आवाज से इस विषय को जीलाधीश के माध्यम से और हमारे कार्यालय के माध्यम से एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों के सामने रख रहे हैं और एन0एच0ए0आई0 प्रदेश में अच्छा काम भी कर रही है इसमें कोई दोराहे नहीं है। मगर फिर भी जहां-जहां पर क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो रहा है या क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं उन्हें समय से मुआवजा राशि मिले और उनके घरों में जो दरारे आई है या जो घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन लोगों को सही समय पर मुआवजा मिले। हमारी यही प्राथमिकता सरकार की ओर से रहेगी।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब सब कुछ तो बोल दिया। अगर इसके अलावा भी अन्य विषय होंगे, तो आप माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से बात करें और माननीय मंत्री जी एन0एच0ए0आई0 के ऑफिसियल को डायरेक्शन देंगे। अब इससे ज्यादा आपने क्या पूछना है।

20.03.2026/1120/ए.पी./डी.सी./03

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो कहा है मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि जिनका नुकसान हुआ है उन परिवारों का आकलन किया जा रहा है और उनको मुआवजा दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ जिनके

घरों को नुकसान हुआ है। नागेन्द्र कुमार, गांव राक्कड, ग्राम पंचायत पाली, जिनका दो मंजिला मकान है। उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च किये थे और उनके मकान के साथ ही लगता फोरलेन है और उनके घर के पीछे कच्ची दीवार लगाई जा रही है। माननीय मंत्री जी मैं आपको यही कहूंगा कि या तो इस मकान को एक्वायर किया जाए या फिर वहां पर पक्की दीवार लगाई जाए। ये आप आदेश करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है

श्री ए०टी० द्वारा जारी....

**20.03.2026/1125/AT/DC/01**

**प्रश्न संख्या 3948 जारी .....श्री पूर्ण चंद ठाकुर जारी..**

वरना बरसात में लोगों का नुकसान होगा और लोगों की जान जाएगी। उसकी फिर भरपाई कौन करेगा? दूसरा मामला सूरजमणि, पुत्र लालू, गांव मेहड़, वह बहुत बीमार है। उसे हर हफ्ते जोनल हॉस्पिटल मंडी ले जाना पड़ता है। वहां तक जाने के लिए पंचायत के माध्यम से और अपने पैसे लगाकर उन्होंने सड़क बनाई थी लेकिन वह सड़क बरसात में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अब उन्हें पालकी पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस सड़क को NHA के द्वारा ठीक करवाया जाए। वह एक छोटा सा लिंक रोड है, ताकि यह बीमार आदमी आसानी से जा सके।

एक और बात कहना चाहूंगा अनिल मणि, पुत्र लाल चंद, खसरा नंबर 295, जिसके घर में दरारें आ चुकी हैं। हम वहां पर गए हैं। वहां सीधी कटिंग हुई है और प्रोटेक्शन वॉल भी केवल आधे तक लगी हुई है। उसे ऊपर तक लगाया जाए या उन मकानों को अधिग्रहित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि फोर लेन की गलत कटिंग के कारण यह सब हो रहा है। उनको चाहे कुछ भी कहें पर उनके अधिकारी बात नहीं मानते। हम जिलाधीश के पास 100 बार गए हैं लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को

सरकार से बहुत आशाएं होती हैं। गरीब आदमी अपनी आवाज आप लोगों के सामने रखता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात बताना चाहूंगा जो नुकसान हुआ है उसमें खसरा नंबर 285/1, 285/2, 286/3, 288/1, 294/1 पर लगभग 8-10 मीटर तक कटिंग हुई है जिससे भारी नुकसान हुआ है। इन्हें जल्दी प्रोटेक्ट किया जाए या फिर अधिग्रहित किया जाए क्योंकि कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपये हैं फिर भी यह सबको लूट रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है।

**20.03.2026/1125/AT/DC/02**

**अध्यक्ष :** बस-बस ठाकुर साहब, हो गया। आप कृपया बैठ जाइए। काफी हो गया, आपको बोलते हुए 9 मिनट हो गए हैं। ठाकुर साहब, बैठिए। आपने जो अभी भाषण देना है, उसमें आपने बोल देना। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी।

**लोक निर्माण मंत्री :** आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। आपके हर मसले पर मैं यह कह सकता हूँ कि तथास्तु आपके सभी कार्य हो जाएंगे। आप चिंता न करें। हम एक-एक करके सभी मामले NHA के साथ उठाएंगे और उन्हें पूरा करेंगे

**20.03.2026/1125/AT/DC/03**

**प्रश्न संख्या 3949**

**श्री किशोरी लाल :** अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें सिविल हॉस्पिटल चढ़ियार में 53 पद स्वीकृत हैं। 16 पद भरे हुए हैं और 37 पद रिक्त हैं। आदरणीय मंत्री जी बैजनाथ के दौरे पर गए थे तो चढ़ियार की जनता ने उनके सामने अपनी मांगें रखी थी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सभी पद भरे जाएंगे। लेकिन वर्तमान में चढ़ियार में 6 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं। पहले 2 पद खाली थे और अब 2 डॉक्टर एम0डी0 करने के लिए चले गए हैं और एक ने अपना तबादला कर लिया है। अब केवल एक डॉक्टर

के सहारे चढ़ियार हॉस्पिटल चल रहा है। मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री से भी कई बार आग्रह किया है कि वहां एक एम0डी0 डॉक्टर नियुक्त किया जाए लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

भाग (ख) में बैजनाथ हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है लेकिन वहां ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। कृपया सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहां ऑपरेशन कब तक शुरू होंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

20.03.2026/1130/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या 3949 जारी...

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हूँ। I had personally visited this hospital. **I promise to the Hon'ble Member that the staff will be given back to them.** जो ये दो डॉक्टर अभी एस0आर0 की वजह से करियर प्रोग्रेशन के लिए चले गए हैं, इससे थोड़ी असुविधा तो ज़रूर हुई है but **I assure the Member that the doctors will also be posted there soon.** On my previous answer I had given the detail. I don't want to repeat it. But I assure the Member इनकी दो चीजें हैं। एक तो स्टाफ की कमी और दूसरी, बैजनाथ हॉस्पिटल में ठीक से मेजर ऑपरेशन ना होने की व्यवस्था को पूरा करना and **in a very-very short time स्टाफ की कमी पूरी कर दी जाएगी.** We are trying to see that in all the civil hospitals of the State we will provide them all their dues. Secondly, Sir, the shortfall of instruments/basic infrastructure for conducting major operation like anaesthesia, workstation, OT table और दूसरे उपकरण, इसके लिए हमारी हाई पावर्ड पर्चेज़ कमेटी ने मेरे सामने सिफारिशें रखी थीं और वहां की रिक्वायरमेंट प्रोक्योर

की जा रही हैं और शीघ्र ही इनके पास मेजर ऑप्शन की भी सुविधा होगी और स्टाफ की कमी भी पूरी हो जाएगी।

**श्री किशोरी लाल :** अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री बैजनाथ दौरे पर गए थे और चढियार की जनता को इन्होंने आश्वस्त किया था कि स्टाफ पूरा किया जाएगा उसके बावजूद वहां से दो डॉक्टर एम0डी0 करने के लिए चले गए और एक ने तबादला करवा लिया। अब एक डॉक्टर के सहारे वह पूरा हॉस्पिटल है और चढियार क्षेत्र की काफी जनसंख्या है। 1500 तो वहां पर पोलिंग बूथ ही हैं। कृपया सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर कब तक स्टाफ भेज दिया जाएगा? ...(व्यवधान)

**Speaker :** Please maintain Order in the House. ...(Interruption) Please don't disturb. मंत्री जी, 57 में से 37 पोस्टें खाली हैं।

20.03.2026/1130/केएस/एचके/2

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जो चिंता माननीय सदस्य ने जताई है, बैजनाथ हॉस्पिटल में विशेष रूप से दोनों डॉक्टर अप्वाइंट किए जा रहे हैं and soon they will report and all other shortfall जो इनकी मेजर ऑप्शन के लिए कमी है, उन उपकरणों को भी हाई टेक्नोलॉजी के जैसे मुख्य मंत्री जी के निर्देश हैं, उसके अनुसार लिए जा रहे हैं और soon they will be equipped and they will give all the facility and doctor will also be posted there.

20.03.2026/1130/केएस/एचके/3

**प्रश्न संख्या : 3950**

**श्री सुधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कुल कितने आवेदन किए गए, आवेदकों के नाम, पिता/पति का नाम, जाति, पंचायत तथा विकास खंड सहित ब्यौरा मांगा था। प्रश्न के "क" भाग की जानकारी नहीं आई है। मैं

आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सत्र में क्या यह पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी?

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमने डिटेल्ड जवाब दिया है लेकिन माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है कि वर्ष 2025 के सर्वे में जिला कांगड़ा से प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कुल कितने आवेदन किए गए, आवेदकों के नाम, पिता/पति का नाम, जाति, पंचायत तथा विकास खंड सहित ब्यौरा दिया जाए, यह बहुत लम्बा रिप्लाय है और केवल मात्र कांगड़ा में ही वर्ष 2025 में लगभग 50,641 आवासहीन परिवारों का पंजीकरण किया गया है। उसका डाटा हमारे पास तैयार है। इसी सत्र में सी0डी0 या पैन ड्राइव के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे क्योंकि फिजिकली तो उससे पूरा टेबल भर जाएगा। Physically, we will provide, no issue.

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में--

**20.03.2026/1135/av/hk/1**

**प्रश्न संख्या : 3951**

**कुमारी अनुराधा राणा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर देने हेतु मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करती हूं। मैं यह अनुपूरक प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या इसमें वे किसान भी शामिल हैं जिनकी वर्ष 2025 की आपदा में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ था। वर्ष 2025 की आपदा के दौरान कुल्लू-मनाली में सड़कें टूट जाने की वजह से पीक सीजन में हमारे किसानों-बागवानों की फसलें मण्डियों तक नहीं पहुंच पाई थी जिसके कारण उनकी 70 से 80 प्रतिशत फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गई थी। क्या इसमें वे किसान और गांव भी शामिल हैं क्योंकि आपके द्वारा दी गई सूचना में कई गांव शामिल नहीं हैं। इसलिए मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या उन किसानों को भी निश्चित समयावधि के अंदर राहत पैकेज के तहत सहायता प्रदान की जाएगी?

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, डिटेल्ड रिपोर्ट में सभी प्रकार की आपदाएं शामिल हैं। उसमें चाहे पशु धन की बात की जाए या किसानों के बारे में; इसमें सभी के बारे में दिया गया है। अभी तक हमारे ध्यान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है जिसको कि यह राशि प्रदान नहीं की गई है। अब तो इस आपदा को दो वर्ष का समय हो चुका है। वैसे तो यह ऑनलाइन चलता है परंतु फिर भी कोई अगर इस प्रकार का स्पेसिफिक केस है तो हमारे ध्यान में लाया जाए।

**श्री संजय रत्न :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के डिजास्टर के दौरान गांवों में जो घर गिर गए क्योंकि मैंने इस संदर्भ में पिछली बार भी प्रश्न किया था कि आपने इसमें क्या पूरा हिमाचल प्रदेश शामिल किया है। लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है, कांगड़ा जिला में अभी तक केवल दो सब-डिवीजन्ज ही नोटिफाई की गई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 23 घर गिर गए और लैण्ड डिस्ट्रॉय हो गई। उस लैण्ड पर अब घर नहीं बन सकते। उनके पास अब न लैण्ड है और न ही घर है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसको भी नोटिफाई करेंगे?

20.03.2026/1135/av/hk/2

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, यह जिला लाहौल-स्पिति से संबंधित प्रश्न है, इसके बारे में अगर अलग से प्रश्न आएगा तो जवाब दे दूंगा। ...(व्यवधान) वैसे तो यह प्रश्न नहीं बनता परंतु मैं फिर भी जवाब दे देता हूं। प्राकृतिक आपदाओं के तहत हमने पूरी स्टेट को आपदा प्रभावित घोषित किया है। इसलिए उनको भी किया जाएगा।

20.03.2026/1135/केएस/एचके/4

**प्रश्न संख्या : 3952**

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न को पूछने का तात्पर्य कुछ और था क्योंकि इस राज्य में संसाधनों की कमी पर चर्चा होती है जबकि इस प्रश्न का जवाब 'मिलियन यूनिट्स' टाइप में दिया है। संसाधनों की इम्प्रूवमेंट की बात है या प्रोडक्शन, हाइड्रो स्टेट और टूरिज्म के अंतर्गत इस स्टेट के रिसोर्सिज में इम्प्रूवमेंट लाने की बात होती है। परंतु यह मेरे हिसाब से कुछ 'बाबू टाइप' जवाब दे दिया है। मैंने मुख्य मंत्री के स्तर का प्रश्न पूछा था। मुख्य मंत्री जी, इस स्टेट के बारे में इनको यूनिट्स काउंट नहीं करवानी चाहिए थी। इनको यह पूछना चाहिए था कि क्या आपने कोई प्रोजैक्ट्स लगाए या आपके रिसोर्सिज में कोई इम्प्रूवमेंट हुई? आपने जो वर्ष 2025-26 के तहत '39209.7 मिलियन यूनिट्स' जवाब दिया है; इस प्रकार से तो ऑफिस में जो फाइलज चलती हैं यह उस तरह का उत्तर है। इस सदन के अंदर जो बात होनी चाहिए वह यह है कि इस स्टेट के लिए क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है और क्या होनी चाहिए। उन्होंने दिए गए उत्तर के माध्यम से घुमा तो दिया है परंतु इसको आपको देखना चाहिए था। मैं तो इसको दोबारा भी पूछ लूंगा। वैसे मेरा पहली बार प्रश्न लगा परंतु वह भी घूम गया। पहले तो मेरे प्रश्न 27वें और 35वें नम्बर पर लगते आए हैं।

**टी सी द्वारा जारी**

20.03.2026/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

**प्रश्न संख्या : 3952... क्रमागत श्री जीत राम कटवाल.... जारी**

मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि एस0के0 प्रोजैक्ट को छोड़कर कोई मेगावाट कपैसिटी इंस्टाल हुई है जैसे वे 12-13 हजार के करीब बताते हैं क्योंकि प्रोडक्शन भी वैसी ही होगी जैसे कपैसिटी होगी। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंटरी पूछें, आप क्या जानना चाहते हैं?

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष प्वाइंट पर आ रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न ही हिल गया है इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ।

**अध्यक्ष :** यह प्रश्न हिला नहीं है आपने पूछा ही ऐसा है। आपने ऊर्जा उत्पादन के बारे में पूछा है, रेवेन्यू के बारे में नहीं पूछा है।

**श्री जीत राम कटवाल :** मैंने नियम-61 में भी लिखकर दिया है उससे भी मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। मैं उसको भी चैक कर लूंगा।

**अध्यक्ष :** आपने इसमें रेवेन्यू जनरेशन के बारे में नहीं पूछा है, आपने उत्पादन के बारे में ही पूछा है।

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, यह मेगावाट कैपेसिटी की बात हो सकती है।

**अध्यक्ष :** ठीक है इसलिए आप पूछें कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है?

**श्री जीत राम :** अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ रहा हूँ।

**अध्यक्ष :** लेकिन मैं अलॉउ तभी करूंगा जब प्रश्न रेलेवंट होगा।

**श्री जीत राम :** अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में वर्ष 2024 के बजट में मुख्य मंत्री जी ने पेखूबेला का 600 मेगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट दिया है। इन सबको मिला कर यह दो वर्षों में 76 या 78 मेगावाट हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार का कोई टारगेट होता है, स्टेट का कोई इंटररेस्ट होता है, इस हाउस का कोई इंटररेस्ट होता है और मुख्य मंत्री महोदय का भी ऑरा होता है कि इन्होंने यह प्रोजेक्ट किया है।

**20.03.2026/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है? अगर इस तरीके की कोई सूचना है तो मुख्य मंत्री जी आप बता दीजिए।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रश्न पूछेंगे, वैसा ही जवाब मिलेगा। आप बाबू टाइप सवाल पूछेंगे तो जवाब वैसा ही मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वह गलत है।

हाइड्रो में हमने 22,950 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स आबंटित किए हैं जिसमें से 188 कमीशंड हैं, 54 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 541 अंडर क्लियरेंसिज हैं। 6 इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में हैं और उनमें लीगल डिस्प्यूट है। 6 प्रोजेक्ट्स पर्यावरण की दृष्टि से संभव नहीं हैं। आप यह पूछना चाह रहे थे लेकिन आपने अपना सवाल बाबू स्टाइल में पूछा तो बाबू स्टाइल में जवाब आ गया।

मैं आपको बताना चाहता हूँ 12,436 मेगावाट लगभग 13,000 मेगावाट के करीब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली जनरेट करते हैं। कई बार जैसे लारजी प्रोजेक्ट डैमेज हो गया था तो उस समय 6 महीने उत्पादन कम हुआ। इसलिए सिल्ट के कारण जरनेश कम भी हो सकता है और सिल्ट निकालने के बाद बढ़ भी सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने प्रदेश का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में 32 मेगावाट का पेखूबेला में लगाया। इसके अलावा ऊना जिला में और भी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि जब से हमने सोलर पावर में अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। तब से हमने प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में 24-25 में 188 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की है और हम वर्ष 2025-2026 में 209 मेगावाट और सोलर पावर जनरेट करेंगे। यह किसी सरकार में पहली बार हुआ है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऊना के पेखूबेला में

### **20.03.2026/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0-3**

लगा। इसके अलावा अगलौर में भी पावर प्रोजेक्ट लग रहा है यानी ऊना जिला में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं।

इसके अलावा हमने एक और पॉलिसी बनाई है। अगर कोई व्यक्ति 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और ट्राइबल एरिया में लगाना चाहता है तो उसको 5 प्रतिशत इंटररेस्ट सबवेंशन मिलेगा और रूलर एरिया में लगाएगा तो 4 प्रतिशत इंटररेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इसका लाभ यह होगा कि आने वाले समय में मार्च,

2026 तक तकरीबन 209 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। इसके अलावा हम पवन ऊर्जा और जियो थर्मल एनर्जी की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारा आइसलैंड की एक कम्पनी के साथ समझौता हुआ है और उस दृष्टि से भी हम देख रहे हैं कि

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी**

20-3-2026/1145/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 3952-----क्रमागत मुख्य मंत्री -----जारी

किन्नौर और लाहौल-स्पिति के एरियाज में हम जियो एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकें। दूसरा, सोलर पॉवर के अलावा विंड एनर्जी के लिए भी आर्मी के साथ बातचीत चल रही है। आने वाले समय में हम रिन्यूएबल एनर्जी को और अधिक जनरेट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

**श्री सुख राम चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, हमारे रेनी सीजन पॉवर हाउस तभी चलते हैं जब बर्फ ज्यादा पड़ती है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इनकी एन्युअल मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है? कई बार देखा गया है कि हम इनकी एन्युअल मेंटेनेंस तब करते हैं जब बरसात शुरू होती है। उससे जनरेशन का नुकसान होता है। मेरे हिसाब से गर्मियों में रेनी सीजन पॉवर हाउस की मेंटेनेंस होनी चाहिए और बर्फ वालों की विंटर सीजन में होनी चाहिए। क्या आप इस तरह की गाइडलाइन्ज इश्यू करेंगे कि इनकी एडवांस में एन्युअल मेंटेनेंस की तैयारी हो। जब उत्पादन कम हो तो उस समय इनका शेड्यूल तय करके एन्युअल मेंटेनेंस की जाए।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमें अच्छा सुझाव दिया है। पॉवर हाउस की मेंटेनेंस आवश्यकता अनुसार की जाती है। **आपने सुझाव दिया है कि एन्युअल मेंटेनेंस रेनी सीजन में न करके गर्मियों में की जाए तो हम इस पर विचार करेंगे।**

**डॉ० हंस राज :** अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी सईकोटी हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। वहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों ने जमीनें दी हैं और वहां पर एस0ई0 व एक्सिअन भी बैठ गए हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या आप विभाग को डायरेक्शन देंगे कि इस प्रोजेक्ट के कार्य को स्पीड अप किया जाए ताकि अगले वर्ष अप्रैल में सईकोटी-1

प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए? सईकोटी- II भी तैयार है और उसकी क्लीयरेंस की प्रक्रिया चली हुई है। इसके अतिरिक्त चांजू- III और चांजू- IV के शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किए थे। अभी चांजू- III चल पड़ा था लेकिन दयोथल चांजू हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्या मुख्य मंत्री जी माननीय सदन को आश्वस्त करेंगे की ये दोनों हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट प्रदेश-हित में शीघ्र शुरू हो जाएं?

20-3-2026/1145/NS-YK/2

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न इस माननीय सदन में पूछा है हमने उसका ही जवाब दिया है। अगर ये इसके लिए अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मेरे पास इसकी जानकारी आ जाएगी और मैं इसकी सूचना माननीय सदस्य को बाद में उपलब्ध करवा दूंगा।

20-3-2026/1145/NS-YK/3

**प्रश्न संख्या : 3953**

**श्री इन्द्र दत्त लखनपाल :** अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार वर्षों से हमारे प्रदेश की छात्राएं खेलों में आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन कर रही हैं। वर्ष 2023, वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में केवलमात्र एक महिला कबड्डी खिलाड़ी को सरकारी विभाग में नौकरी मिली है और उसे भारतीय रेलवे में नौकरी मिली है। मेरे प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि अन्य खिलाड़ियों को पात्रता के अनुसार 3 प्रतिशत खेल कोटे से विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये प्रयास कब तक जारी रहेंगे?

**आयुष मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि 3 प्रतिशत कोटे के अनुसार खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास कब तक जारी रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने इसका पूरा डोकेट बना कर रखा है और शीघ्र ही योग्यता के अनुसार खिलाड़ियों को

आर0के0एस0 द्वारा ---जारी

20.03.2026/1150/RKS/AG-1

प्रश्न संख्या: 3953 जारी

आयुष मंत्री जारी....

जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है उन्हें निश्चित रूप से 3 प्रतिशत कोटे के तहत नौकरी प्रदान की जाएगी। हमने 17 और खेलों को शामिल किया है जिनमें खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत कोटे के तहत नौकरी मिलेगी। अभी इसका एक प्रारूप तैयार किया गया है और 2-3 महीने के बाद इनको 3 प्रतिशत कोटे के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी।

**श्री इन्द्र दत्त लखनपाल :** अध्यक्ष महोदय, हमारे जो खिलाड़ी कबड्डी या अन्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर आए हैं, क्या उनको सरकार ने सभी अवार्ड प्रदान कर दिए हैं? उनको जो राशि भुगतान की जानी थी, क्या वह राशि उन्हें दे दी गई है? साथ में, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतने के बाद नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे आगे भी अपना खेल जारी कर सकते हैं? प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलम्पिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं और उनमें से जिन खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड दिये जाते हैं, क्या ऐसे खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन देने का विचार किया जा रहा है? जो स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड, परशुराम इत्यादि हैं वे लगभग 6-7 वर्ष से हमारे प्रदेश में दिए ही नहीं जा रहे हैं जबकि ये अवार्ड हर वर्ष मिलने चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र से श्री विजय कुमार निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक उनको स्टेट अवार्ड नहीं दिया है। क्या माननीय खेल मंत्री जी बताएंगे कि उन्हें कब तक स्टेट अवार्ड दे दिया जाएगा? मैंने जो ये सब प्रश्न पूछे हैं कृपया आप इन सबका जवाब मुझे दीजिए।

**आयुष मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, क्या उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा कैश रिवार्ड दिया गया है? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले महीने यहां एक स्टेट लेवल का फंक्शन किया था जिसकी अध्यक्षता

20.03.2026/1150/RKS/AG-2

माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले यह राशि डायरेक्ट खिलाड़ियों के खाते में जाती थी। जो खिलाड़ी वर्ष 2021, 2022 व वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतकर आए थे हमने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें पूरे प्रदेश के खिलाड़ी मौजूद थे और हमने उन सबके सामने लगभग साढ़े 17 करोड़ रुपये की कैश रिवार्ड राशि खिलाड़ियों को वितरित की थी। **आपने जो अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित खिलाड़ी का जिक्र किया है, मैं उसके बारे में जरूर इन्क्वायरी करवाऊंगा और अपनी योग्यता के अनुसार वे जो मैडल जीतकर आए हैं उसके अनुरूप जो उनका कैश रिवार्ड बनता होगा, उसको सरकार अपनी ओर से देगी।**

**श्री विनोद कुमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीत कर आते हैं उनकी प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। आपने यह भी कहा कि वर्ष 2023 तक जिन खिलाड़ियों ने पदक जीत कर लाए हैं उन्हें आपने प्रोत्साहन राशि दी है। हमारी महिला टीम ने अभी विश्व कप जीतकर पूरे देश में हिमाचल का नाम भी रोशन किया है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उन हिमाचल प्रदेश की बेटियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई है? प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि 'कोशिश की जा रही है' लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यह राशि देने का प्रावधान है तो कोशिश क्यों की जा रही है? मेरा आग्रह है कि आपने जो भी प्रोत्साहन राशि तय की है वह राशि जल्द इन बेटियों को दी जाए।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

20.03.2025/1155/बी.एस./.....-1

प्रश्न संख्या: 3953 क्रमांगत....श्री विनोद कुमार के उपरांत ...

**आयुष मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य ने रखी है, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अभी हाल ही में जो वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप हुआ था जिसमें सिरमौर जिले के हमारे तीन खिलाड़ी श्रीमती रितु नेगी, कुमारी साक्षी शर्मा, कुमारी पुष्पा राणा, चम्बा जिला से कुमारी चंपा ठाकुर, मंडी जिला से कुमारी भावना ठाकुर है, जिन्होंने इस खेल में हिस्सा लिया था और निश्चित रूप से हिमाचल का नाम रोशन किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जो कैश रीवार्ड इनका बनता है, क्योंकि यह जो गेम्स हैं, जो कबड्डी गेम है, यह बेसिकली एशियन गेम है, ओलंपिक गेम में एनरोलमेंट नहीं है और मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश किया है कि हिमाचल का खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आपने देखा होगा कि पिछले सरकार की तुलना में हमारी सरकार ने हर ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, लगभग 100-150 प्रतिशत धनराशि को बढ़ाया है, जो सम्मान राशि है उसे बढ़ाया है, जो प्रदेश के लिए अवार्ड लेकर आता है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जीत कर आता है। यहां जो अपने खिलाड़ियों का नाम लिये हैं, इनका नाम भी हमने लिस्ट में रखा है और जल्द ही इनको भी धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।

**श्री नीरज नैय्यर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एशियन और ओलंपिक नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स हैं जैसे शूटिंग और बॉक्सिंग हैं। क्या उन बच्चों के लिए उसके अंदर भी सरकार कोई प्रावधान करेगी? जो इंटरनेशनल लेवल के मेडल जीत कर लाते हैं।

मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करूं, तो हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक लड़का है फरहान मिर्जा और उसने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोरिया के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैंने उसके टिकट के लिए पैसे दिए, मैंने पैसे दिए और एन0एच0पी0सी0 से मांग रखी और एन0एच0पी0सी0 ने बोला, अगर मेडल जीत जाएगा

20.03.2025/1155/बी.एस./.....-2

तो हम स्पॉन्सर करेंगे। तो उसके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं थी और वह ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया। अभी पिछले हफ्ते वह फिर मेरे पास आया। एक वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट हो रहा था, उसके अंदर वह जाना चाहता था। उसने मेरे से फिर 3 लाख रुपये की मांग रखी। मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया, तो कहीं से हम उसको पैसा नहीं दे सके और वह टूर्नामेंट उसने मिस कर दिया।

ऐसे हमारे यहां बहुत बच्चे हैं। कुछ प्रावधान डी0सी0 के पास या किसी के पास होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे की किसी इंटरनेशनल लेवल के अंदर सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे पास कोई प्रावधान ही नहीं है। तुरंत उनको एक हफ्ता पहले पता लगता है कि उनकी सिलेक्शन हुई है और एक डेट या दो हफ्ते का उनको मौका मिलता है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहूंगा कि 10-15 लाख रुपया डिप्टी कमिश्नर या किसी अन्य माध्यम से कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर होना चाहिए कि अगर बच्चा कहीं इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट होता है, तो कम-से-कम उसकी टिकट का खर्चा, उसका रहने-खाने का खर्चा निकल जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने तो एक के लिए ट्राई किया, वह जीत के आया और कई अन्य भी मेरे पास अच्छे आते हैं। एक हमारी लड़की सीमा है, वह भी मुझे यू0एस0ए0 से फोन करती रहती है और बोलती है कि मेरे को कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी सरकार को ध्यानपूर्वक तरीके से विचार करना चाहिए।

**आयुष मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात रखी है कि कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को भी बताना चाहूंगा और माननीय सदस्य को भी बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने पीछे ही यह आदेश किए थे कि हमारा जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाएगा, उसको भी हम रेलवे में Three-tier AC (3AC) फैसिलिटी में भेजेंगे और एयरवेज की अगर जरूरत होगी तो उस पर भी उसको भेजने के लिए तैयार हैं। इन्होंने बात रखी है कि ऐसा कोई अगर खिलाड़ी आता है, तो वह निश्चित रूप से आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को लिखें और उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।

20.03.2025/1155/बी.एस./.....-3

**श्री राकेश कालिया:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल में देश का सरताज हुआ करता था।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.03.2026/1200/DT/AS-1

**प्रश्न संख्या 3953 जारी**

**श्री राकेश कालिया जारी..**

जब स्वर्गीय श्री राम लाल ठाकुर जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, यह शायद वर्ष 1980 की बात है, तो उस समय हमारे प्रदेश ने वॉलीबाल का नैशनल भी जीता था। कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जब हिमाचल प्रदेश का वॉलीबाल का कोई खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट न करता हो। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि वॉलीबाल में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। हम वॉलीबाल को राज्य का खेल समझते हैं। शिमला और मंडी के खिलाड़ी वॉलीबाल में बहुत बढ़िया माने जाते हैं। इस खेल का नैचुरल टेलेंट यहां के युवाओं में होता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी यह प्रश्न है कि राज्य को पुनः वॉलीबॉल के खेल में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार इस खेल के उत्थान के लिए क्या प्रयास कर रही है? एक समय था जब हम वॉलीबाल में देश भर में बहुत अच्छे माने जाते थे। पंजाब की ओर से भी हमारे प्रदेश के युवा खेलते थे। इस लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्या सरकार इस खेल के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनायेगी जिससे प्रदेश में वॉलीबाल की गरिमा फिर से स्थापित हो?

**आयुष मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि डॉ० यशवंत सिंह परमार मेमोरियल टूर्नामेंट हर साल डॉ० यशवंत सिंह परमार जी की याद में मनाया जाता है। इस टूर्नामेंट में देश की टॉप की 8 टीम को बुलाया जाता है। मैंने विभाग के अधिकारियों से भी बात की है और माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी इस बात को लाया है कि इसका प्रारूप हम चेंज करेंगे और आने वाले समय में हम इस इवेंट को राज्य स्तर का करेंगे ताकि हमारे सभी जिलों से जो वॉलीबाल के अच्छे खिलाड़ी हैं वह इस टूर्नामेंट में अपना टेलेंट दिखा पाएं

और उनकी प्रतिभा प्रदेश और देश के सामने आये। माननीय सदस्य के द्वारा जो बात इस सदन में प्रश्न के माध्यम से रखी गई है कि वॉलीबाल और अन्य खेल जो भी हैं, जो कि राज्य स्तर पर ज्यादा खेले जाते हैं, इसके संदर्भ में उन्हें यही कहूंगा कि खेलों को प्रमोट करने के लिए अभी भारत सरकार ने खेलों इंडिया-2.0 शुरू किया है और निश्चित रूप से इससे प्रदेश की खेल नीति में भी बदलाव आयेगा। जब नई खेल नीति बनेगी, जो माननीय सदस्य द्वारा विचार इस संदर्भ में व्यक्त किए गये हैं, उन पर सरकार विचार करेगी।

### **प्रश्न काल समाप्त**

20.03.2026/1110/DT/AS-1

### **शून्य काल**

**Speaker : Hon'ble Leader of Opposition wants to raise some issue in the Zero Hour.**

**श्री जय राम ठाकुर:** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हालांकि मैंने लिखित रूप में शून्य काल में अपना मामला उठाने के लिए नहीं दिया था फिर भी विषय की गंभीरता को देखते हुए आपने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देव भूमि है लेकिन अब यह प्रदेश चारों तरफ से नशे की चपेट में आ रहा है, यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सिंथेटिक ड्रग का प्रचलन जो आज के दौर में हम देख रहे हैं वह गंभीर है। हमारे प्रदेश के वह जिले जिनकी सिमाएं अन्य जिलों के साथ लगती हैं उन जिलों में इस नशे का प्रभाव ज्यादा देखा जाता था क्योंकि दूसरे राज्य से इन क्षेत्रों में इस ड्रग्स को आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता था। इसलिए उन इलाकों में इसका कुप्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता था। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति यह बन गई है कि जहां दूर-दराज के क्षेत्र में आदमी का पहुंचना भी मुश्किल हुआ करता था अब वहां भी यह ड्रग पहुंच रही है जिसके कारण उन क्षेत्रों में भी नशे की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। स्वाभाविक रूप से यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पिछले कुछ अर्से से मैं देख रहा हूं कि सरकार ने अपनी ओर से इस नशे के विरुद्ध गंभीर होकर कुछ कदम उठाने की कोशिश की है। लेकिन मैं पहले दिन से ही इस बात को कह रहा हूं कि सरकार गंभीर है यह केवल दिखने के लिए ही नहीं

करना है इस दिशा में व्यावहारिक रूप से और गंभीरता के साथ प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

इस समय हिमाचल प्रदेश में इस नशे के विरुद्ध वॉकथान के आयोजन किए जा रहे हैं। यहां स्कूल के बच्चों को लाकर खड़ा किया जा रहा है उनसे नारे लगवाये जा रहे हैं। उन बच्चों के माध्यम से आप प्रोसेशन निकाल रहे हैं। कलाकारों को बुलाकर वहां पर उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं।

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी..**

**20.03.2026/1205/ए.एस.-एन.जी./1**

**श्री जय राम ठाकुर ..... जारी**

अवेयरनेस की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि इसकी आवश्यकता रहती है लेकिन जो बड़े आयोजन हो रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ इवेंट की शोप से अधिक कुछ नहीं हैं। मुझे लगता है कि समाज का कुल मिलाकर यह पूरा जनरल ओपिनियन है कि मुख्य मंत्री जी को कुछ अधिकारी खुश करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों/वॉकथोन का आयोजन करते हैं, जहां पर मुख्य मंत्री जी बड़ी भीड़ देखकर बहुत उत्साहित होते हैं और उनको लगता है कि हमने नशा समाप्त कर दिया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि चलो आपने उस दिशा में प्रयास किया और यह अवेयरनेस का एक हिस्सा हो सकता है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि नशा आदमी के लिए खराब है, समाज व देश के लिए खराब है, इस बात को लेकर इस प्रकार के बड़े आयोजनों के माध्यम से आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे हटकर आप कुछ कर रहे हैं? वह नहीं दिख रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म और चिंता की बात है कि पुलिस जैसे एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था और इसके साथ-साथ ऐसे एंटी-सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने व उन्हें सजा दिलाने की है और खास तौर पर इस चिट्ठे के अभियान में तथा नशे के अभियान में उनकी

भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम शर्मसार हो गए हैं कि जब अखबारों की सारी हेडलाइंस पुलिस के विरुद्ध भरी पड़ी हैं। 'हिमाचल दस्तक' में खबर लगी है कि 'एल0एस0डी0 तस्करी मामले में कुल्लू एस0टी0एफ0 के चार जवान गिरफ्तार'। जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है, वही इसमें शामिल हो रहे हैं। 'दैनिक जागरण' में खबर लगी है कि 'एक करोड़ की एल0एस0डी0 तस्करी में एस0टी0एफ0 के चार जवान गिरफ्तार। मैं बहुत सारी खबरें ला नहीं पाया हूं।

**20.03.2026/1205/ए.एस.-एन.जी./2**

'अमर उजाला' में खबर लगी है कि 'एल0एस0डी0 तस्करी के मामले में लापरवाही पर एस0टी0एफ0 के चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कुल्लू में एल0एस0डी0 के साथ पकड़े जाने के बाद छोड़ दिए थे आरोपी'। यह कितना गंभीर विषय है? 'दिव्य हिमाचल' में खबर लगी है कि 'नशा तस्करी को पकड़ने वाले खुद गिरफ्तार, एल0एस0डी0 तस्करी में एस0टी0एफ0 भी हुई दागदार, चार कर्मी अरेस्ट, सवालों के घेरे में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली'। अध्यक्ष महोदय, जाए तो जाए कहां? यह परिस्थिति सच में बहुत ही चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए बना हुआ है।

अध्यक्ष महादेय, हम यह देख रहे थे कि पहले नशा शराब का होता था, नशा भांग का होता था और उस नशे से, ठीक है नशा तो सबके लिए खराब है लेकिन उसके बावजूद उस नशे के कारण ऐसी परिस्थिति नहीं आती थी कि आदमी उसमें एडिक्शन के लेवल तक इतनी तेजी से पहुंच जाए। उसमें वक्त लगता था।...(घण्टी)... यहां तो जो चिट्टे का प्रचलन होता है, अगर दो बार कोई ले लेता है तो तीसरी बार वह पूरी तरह एडिक्शन की तरफ चला जाता है। हम खबरें देख रहे हैं कि एक बच्चा जेल के अंदर है और उसकी मां चिट्टा लेकर उसकी जिंदगी बचाने के लिए, मेरे बच्चे को पीड़ा हो रही है, वह उसके बिना नहीं रह सकता तो वह उसे चिट्टा उपलब्ध कराने की बात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह एल0एस0डी0 का और भी ज्यादा गंभीर विषय है। एल0एस0डी0 का नशा — यह नया नशा नहीं बल्कि पुराना है लेकिन उसके बावजूद हम

देख रहे हैं कि इस नशे की चर्चा आजकल बहुत तेजी से हो रही है। अभी जो जानकारियां मिल रही हैं कि कुल्लू में कुछ लोग इस नशे के साथ पकड़े गए थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया। फिर वे शिमला में पकड़े गए। जब शिमला में पकड़े गए तो कड़ी जुड़ी और उसके बाद मालूम पड़ा कि कुल्लू में जो पकड़े गए थे, उनको छोड़ा गया था। इन सारे विषयों के कारण जो जानकारी मिली कि कुल्लू में जो दो करोड़ रुपये की खेप पकड़ी गई थी, जिसमें दो कांस्टेबल और दो हेड कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर यह खेप तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की थी। ऐसे में, अध्यक्ष महोदय

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**20.03.2026/1210/ए.पी./डी.सी./01**

**शून्यकाल जारी .....श्री जय राम ठाकुर जारी .....**

जो यह नशा है, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि यह नशा बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। जिसके कारण आदमी के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हैलुसीनेशन यानी मति-भ्रम इस नशे से हो जाता है। व्यक्ति के सोचने-समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वे व्यक्ति अपराध की दिशा में आगे बढ़ता है। इस नशे से जो इम्पैक्ट आएंगे, वे चिंता का विषय हैं। लेकिन सदन में इस विषय को उठाने का मेरा औचित्य सिर्फ यही है कि क्या आप इसी बात को लेकर आनंदित महसूस कर रहे हैं कि हमने बड़े-बड़े वॉकथॉन आयोजित किये? क्या आपका कैम्पेन सुपरफिशियल था? आपके इस कैम्पेन की जमीनी हकीकत कतेई भी ठीक नहीं है। आपको अगर नशे पर गंभीर प्रयत्न करने हैं तो कार्रवाई एक पार्ट है। लेकिन आपको उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस धंधे में शामिल हैं। इस समय कार्रवाई सिर्फ उन लोगों पर हो रही है जो नशे का सेवन कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो इस नशे के धंधे में शामिल हैं। वे लोग जो नशे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इस नशे से खुद को अमीर बनाने का साधन बना चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। खासतौर पर एस0डी0एफ0 की नियुक्तियों पर भी सवाल उठते हैं। किन लोगों को, किसके कहने पर रखा गया? क्या उनकी इंटीग्रिटी की पहले जांच नहीं की गई? यदि किसी नेता के कहने पर नियुक्ति हुई है

तो जबाबदेही उनकी भी होनी चाहिए। पुलिस को अपने विवेक से काम करना चाहिए न कि नेताओं के निर्देशों पर। प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को रखा गया है, उन्हें वे काम करना चाहिए। आज के समय में पुलिस नेताओं पर निगरानी रखने का काम कर रही है कि कौन-सा नेता कहाँ जा रहा है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, नेता क्या बात कर रहा है, उनके फोन को ट्रेप किया जा रहा है। आजकल पुलिस का यह धंधा बन गया है। हमें ऐसे इनपुट अनेकों बार मिल चुके हैं। पुलिस इन कामों में लगी है और नशे में संलिप्त जिन लोगों को पकड़ने के लिए एस0डी0एफ0 में शामिल किया गया है, वे नशे के धंधे में स्वयं शामिल हैं। इस तरह से किस अधिकारी द्वारा उन्हें नियुक्ति दी गई है,

**20.03.2026/1210/ए.पी./डी.सी./02**

जबाबदेही उनकी भी होनी चाहिए और अगर किसी नेता के कहने पर उन्हें नियुक्त किया गया है तो जबाबदेही उस नेता की भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमें देवभूमि हिमाचल को नशे के चंगुल से बाहर निकालना है। हमने अनेकों बार माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा है कि विपक्ष को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। जब आप वॉकथॉन आयोजित करते हैं तो आपको विपक्ष का कोई भी विधायक मंच पर नहीं चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे-ऐसे (हाथ उठाकर, पक्ष के साथियों की तरफ इशारा करते हुए) करना होता है। आपको नारे लगाने होते हैं। (खाना-पीना आनंद लेना ओ गम्बरीये) इस तरह से नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस फोर्स के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। वहाँ पर बहुत से अधिकारी हैं जोकि इंटिग्रीटी वाले हैं। काम उनको दिये जाए जो इंटिग्रीटी वाले अधिकारी हैं। इसलिए यह एक बहुत ज्यादा चिन्ता का विषय है, मुझे लगा इस विषय पर माननीय सदन में बात होनी चाहिए। आप विपक्ष को ऐसा मानते है कि हम अछूत है और हम इस समाज का हिस्सा ही नहीं हैं। इस प्रदेश से हमारा कोई लेना-देना ही नहीं है, इस तरह से आप हमारे साथ व्यवहार करते हैं। विपक्ष को भी इन सभी कार्यक्रमों में बुलाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे सुझावों से भी आपके इस अभियान को ताकत मिले। आप अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं करते, जिस कारण इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, इन घटनाओं के कारण पूरा प्रदेश चिंतित है। अब प्रश्न यह है कि इतने गंभीर विषय पर आखिरकार हम कर क्या रहे हैं?

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

20.03.2026/1215 /AT/DC /01

श्री जय राम ठाकुर जारी...

यह प्रश्न सरकार के कामकाज और काम करने के तौर-तरीके पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, जिसका जवाब आपको देना होता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इन सभी विषयों को लेकर स्पष्ट करें और पुलिस विभाग का उपयोग करें दुरुपयोग न करें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री महोदय ...(व्यवधान) आ गया आपका इश्यू, आ गया। एक मिनट, मुख्य मंत्री महोदय ...(व्यवधान) एक मिनट। सती साहब आप बैठिए। यह पहले से भी इश्यू आ चुके हैं और अब 10 मिनट बचे हैं। अब अगर आप ही सप्लीमेंट करते रहेंगे तो आपके माननीय सदस्यों के इश्यूज अधिकतम हैं, वह नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं 12:30 बजे पर समाप्त कर दूंगा। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती जी।

**श्री सतपाल सिंह सती :** अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष हमारे नेता जय राम ठाकुर जी ने जो विषय उठाया है, मेरा उसी से संबंध है। क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं और यह बुराई अब दूर-दूर तक फैल गई है। कई बार किन्नौर से, लाहौल से, रोहडू से और रामपुर से भी खबरें आती हैं। बुराई को फैलने में देर नहीं लगती है। लेकिन बॉर्डर एरिया के ऊपर इससे भी ज्यादा हालत खराब हैं। इसलिए मैं इस पर सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय जय राम ठाकुर जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें कोई दोहराय नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। कई बार जब ऐसा विषय आता है तो मैंने देख रहा था कि डी0जी0पी0 साहब भी यहां पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में भी पुलिस अधिकारी भी बैठे होंगे और वे दोनो ही हंस रहे थे। इस तरह से काम नहीं होता। आप लोगों को इस मामले में गंभीर होना चाहिए। अगर फोटो दिखाई जाए तो साफ दिखेगा कि जब जय राम ठाकुर जी बोल रहे थे तब आप हंस रहे थे। इस तरह से विषय नहीं चलता। जिनके 12-12 साल और 20-20 साल के बच्चे मर रहे हैं उनसे

20.03.2026/1215 /AT/DC /02

जाकर पूछिए कि क्या स्थिति है। शिमला में 2 साल पहले एक 22 साल का बच्चा बाथरूम में इंजेक्शन लगाते हुए मर गया था। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि जय राम ठाकुर जी ने एक बहुत ही वेलिड विषय उठाया है कि पुलिस के अंदर किस व्यक्ति की इंटीग्रिटी क्या है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे वह बीजेपी का है, कांग्रेस का है या न्यूट्रल है, किसका है किसका है इसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। जब भी मैं लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बोलता हूँ और ऊना के विषय के बारे में आज भी जरूर बोलूंगा अगर मुझे समय मिलेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं आपके एसआईयू के अंदर, सीआईडी के अंदर और एंटी करप्शन के अंदर जो महाचोर लोग हैं जिन्होंने खनन के अंदर अपनी जेसीबी लगाई हुई है। जिनके जन्मदिनों के ऊपर गैंगवार ऊना में करने वाले लोग उनको केक खिलाते हुए फोटो मैंने इस सदन में प्रस्तुत किए हुए हैं। जो गैंगवार और खनन में लोग इन्वोलव हैं। वे पुलिस के आदमी के जन्मदिन के ऊपर उसको केक खिला रहे हैं। क्या कभी ऐसे वीडियो प्रदेश के अधिकारियों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे आग्रह रहेगा कि आपने अच्छा विषय उठाया है कि आपको प्रदेश के बच्चों के भविष्य की चिंता है। हर परिवार में एक-दो बच्चे हैं। लेकिन इस विषय में हम आपके साथ हैं। भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको भी ईमानदारी से उन्हीं लोगों को लगाना पड़ेगा जो लोग बिल्कुल ठीक है। एक विषय मैंने ऐसा भी देखा है इसके ऊपर मैं एक मिनट लूंगा। एक विषय मैंने और देखा है कि जो लोग पकड़े जाते हैं, मेरा ऊना का अनुभव है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हीं लोगों को बीच में गवाह बना दिया जाता है। फिर वही लोग पुलिस पर आरोप लगा देते हैं, और बाद में उसी पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी हम चोर आदमी को गवाह बना रहे हैं। मान लीजिए हम चार लोग पकड़े गए जैसे A, B, C, D हम कह रहे हैं कि हमसे तो 10 लाख रुपये पकड़ा लेकिन इसके तो 5 लाख रुपये ही शो किया। हम पुलिस के ऊपर पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब भी हो रहा है। हम पुलिस के ऊपर विश्वास भी रखें। दूसरा विषय, पुलिस के ठीक लोगों को काम में लगाए वरना कोई पुलिस वाला ठीक ढंग से कार्रवाई भी नहीं करेगा और एसआईटी के अन्दर जाने से भी डर जाएगा, अगर आप उसके साथ ठीक ढंग से नहीं खड़े तो। पंजाब के अंदर आतंकवाद खत्म हुआ है तो

श्रीमती के०एस०द्वारा जारी .....

20.03.2026/1220/केएस/एचके/1

श्री सतपाल सिंह सती जारी --

बेअंत सिंह और के०पी०एस० गिल पुलिस के पीछे खड़े हो गए थे। यू०पी० के अंदर गुंडों को मारा गया है, सुधारा गया है तो वहां पर योगी आदित्यनाथ पुलिस के पीछे खड़े हुए हैं। तब जा कर वे बड़े-बड़े लोगों को सुधार रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस के सारे लोग खराब हैं लेकिन बहुत से लोगों को सिफारिशी लगाया जाता है। जो उनको लगवाने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के आदमी काम कर रहे हैं, इसलिए वे लगवाते हैं। हमने अपना आदमी क्यों लगाना है? हमारी तरफ से जिसको पकड़ना है, पकड़ो। लगाते वक्त उसका ध्यान रखें, उसकी इंटीग्रिटी को देखें और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें अन्यथा हिमाचल की युवा शक्ति इससे तबाह हो रही है। अध्यक्ष जी, मेरा मुख्य मंत्री जी से इतना ही आग्रह रहेगा। धन्यवाद ।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता हर चीज़ में सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न काल से पहले ये हाथ उठाते हैं फिर 5-10 मिनट प्रश्नकाल के समय भी समय बर्बाद होता है। अध्यक्ष जी, आपने इनको 10 मिनट की बजाय 12 मिनट दिए। ये कहते हैं कि बड़े-बड़े इवेंट करवा रहे हैं, वॉकथॉन करवा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमें भी शामिल नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नशा कोई तीन साल में प्रचलन में नहीं आया। हमारी सरकार तीन साल पहले बनी। नशा गांव-गांव में पहुंच चुका था। हर घर में पहुंचाया जा रहा था। मुझे कई माताएं मिलती थीं कि हमारे बच्चों को नशे से बचा लो। कई परिवार उजड़ गए। यह सरकार तब PITNDPS Act नहीं लाई। मैंने वर्ष 2023 में उसको इम्प्लीमेंट किया। आप हमें नशे के बारे में बोल रहे हैं? जिस पीढ़ी को नशा करने की ये नशाखोर तस्करी करके आदत लगाने की कोशिश करते हैं मैंने उसको जागरुक करने का जिम्मा उठाया। वॉकथॉन का मतलब यह नहीं है, कोई मुख्य मंत्री इतनी दूर पैदल नहीं चलेगा। बच्चों को सिर्फ जागरुक करने का मकसद था। धर्मशाला में विधान सभा के सत्र के दौरान मैंने इनसे कहा कि आप भी वॉकथॉन में आएँ। आपने हमारा साथ दिया। आपने कहा कि हम

सी०एम० की फोटो वाली टी-शर्ट नहीं पहनेंगे। ... (व्यवधान) मैं कहां मुकर रहा हूं? आपने उसमें हमारा साथ दिया। नशे के खिलाफ जो हमारे प्रदेश की पुलिस ने अभियान चलाया, इतिहास में ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया था। मैं पुलिस के

**20.03.2026/1220/केएस/एचके/2**

अधिकारियों को, डी०जी०पी० को, सभी एस०पी० को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि नशे के खिलाफ जितना सख्ती से हम काम कर रहे हैं, उतना किसी ने नहीं किया और इसी का परिणाम है कि इतिहास में पहली बार 11 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 8 दूसरे राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। क्या यह कम है? 60 के लगभग लोगों को हम अभी जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। माफिया जिस पर कोई हाथ नहीं डालता था, हम उनको अरेस्ट करके यहां ला रहे हैं। ये जो एल०एस०डी० की बात कर रहे हैं, यह किसने पकड़ी? किसने पुलिस कर्मचारियों को पकड़ा? यह पुलिस वालों ने पकड़ी। जो सी०आई०डी० में लगे हुए थे, उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और कहां से पकड़ा? जब कोई सूत्रधार मिलता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ये कहना कि सरकार सोयी हुई है, गलत है। हमारी सरकार हर युवा को नशे से बचाना चाहती है। ... (व्यवधान) अगर जय राम जी, आप अखबार और इनकी टिप्पणियों पर बात करेंगे, आपको मैं यह कहना चाहता हूं, ... (व्यवधान)

**Speaker** : Shri Jai Ram Thakur ji, please take your seat. Let the Hon'ble Chief Minister state his views. ... (Interruption) ठाकुर साहब, कृपया बैठ जाइए।

**मुख्य मंत्री** : लिखने में कई बार अखबार के एक शब्द को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन चार पुलिस वालों को किसने पकड़ा? पुलिस वालों ने पकड़ा और अध्यक्ष महोदय, ये अपना ध्यान अखबारों के माध्यम से आगे लाना चाहते हैं। आप लाएं लेकिन इस तरह की बात करके नशे में संलिप्त लोगों को संरक्षण प्रदान करने की बात नहीं करनी चाहिए। ... (व्यवधान) हम लोगों ने कोई संरक्षण नहीं दिया है और मैं इस बात से भी सहमत हूं, सती जी ने कहा है कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे, नशे के खिलाफ

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी--

20.03.2026/1225/av/hk/1

**मुख्य मंत्री ----- जारी**

हमने युद्ध शुरू किया है। हम मई-जून के महीने में मण्डी जा रहे हैं और चाहेंगे कि आप (श्री जय राम ठाकुर) भी वहां आइए। उसके बाद ऊना में रखेंगे यानी हमारी सरकार हर युवा को बचाने के लिए कृतसंकल्प है। उसमें वॉकथॉन (walkathon) भी करेंगे और पंचायतों में चिट्ठा मुक्त रैलियां भी करेंगे। हमने स्पेशल पंचायत बुलाई और पहली बार मैपिंग भी की है। क्या यह नशा कोई हमारे तीन वर्षों के कार्यकाल में आया, आप पिछले 5 वर्षों में क्या करते रहे? आप उस समय सोये रहे। हर गांव में चिट्ठा पहुंचा। ...(व्यवधान) नहीं चलेगा तो न चले, परंतु हमें बोलने तो दीजिए। आपके समय में गांव-गांव में चिट्ठा पहुंचा और आप सभी लोग जो उस समय सत्ता में थे, उसके लिए दोषी हैं। ...(व्यवधान) आप सभी लोग दोषी हैं। ...(व्यवधान) आप क्या यह सोचते हैं कि गांवों में चिट्ठा हमारे तीन वर्षों के कार्यकाल में आया?

**Speaker** : Please take your seats. ...(Interruption) Let him complete his statement. ..(Interruption) Let him complete his statement. Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats. आप लोग बैठ जाइए।

(विपक्ष के सभी सदस्यगण सदन से बाहर गए)

(कुछ क्षण पश्चात सर्वश्री विपिन सिंह परमार, बिक्रम सिंह, त्रिलोक जम्वाल और श्रीमती रीना कश्यप सदन में वापिस आए।)

**Nothing is going on record, no slogan shouting, there is no eventuality for any slogan shouting.** Proper time has been given to both the sections.

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग दोषी होते हैं वे इस तरह से भागते हैं। पिछली वर्ष 2017 से 2022 की सरकार प्रदेश के हर जिला और गांवों तक चिट्ठा पहुंचा कर गई है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के हर परिवार को बचाने की

**20.03.2026/1225/av/hk/2**

कोशिश कर रहे हैं। पंचायतों में मैपिंग कर रहे हैं। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं किसी राजनैतिक लाभ के लिए यह वॉकथॉन नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रदेश की युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूँ ताकि कल को किसी माँ की कोख नशे के कारण न उजड़े; हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार, आप बैठे रहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ देने की जगह ये लोग राजनैतिक रोटियां सेंक रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री सतपाल सिंह सती जी ने हमें अच्छा सुझाव दिया है और **हम उस सुझाव पर गौर करेंगे**। विपक्ष की माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप भी यहां बैठी हैं क्योंकि ये जानती हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें यह लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। आज एल0एस0डी0 पकड़ी गई और पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। विपक्ष वाले दोष इसलिए लगा रहे हैं ताकि इनके हौसले कम किए जा सकें। अधिकारियों पर दोष लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। पुलिस के साथ हमारा पूरा मंत्रिमण्डल और विधायक दल खड़ा है। इसमें जो भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ हम कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खड़े हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि चिट्टे के खिलाफ हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बारे में लिस्ट तैयार की जा रही है और हमने कहा है कि इसके संदर्भ में कोई बड़ा नेता भी फोन नहीं कर सकता। हमारे विधायक चिट्टे के खिलाफ हरेक पंचायत में जाकर जन-जागरण अभियान चला रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता परंतु इनके समय तो सुन्दरनगर में जहरीली शराब के कारण 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं विपक्ष के नेता का बहुत आदर करता हूँ। वे विपक्ष के नेता हैं तथा प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आगे से उनके लिए यहां पानी के गिलास में आइस क्यूब डालकर रखा कीजिए। अभी मैं बोल ही रहा था कि वे

उठ गए। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार, आप भी उन्हें थोड़ा शांत रहना सिखाइए, वे मेरे बाद बोल लेते।

टी सी द्वारा जारी

20.03.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

शून्य काल ... जारी मुख्य मंत्री.... जारी

...(व्यवधान) उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें भी बुला लेना चाहिए था। मैंने कहा अगर विरोध करना है तो आप बताइये आप कहना क्या चाहते हैं? वह पुलिस बल जिन्होंने कार्रवाई की यानी उन्हें पुलिस वालों ने ही पकड़ा किसी और ने नहीं पकड़ा। अखबार की हेडिंग के बाद बीच में अगर कोई शब्द लिखा जाता है तो उसका गलत मतलब नहीं निकलना चाहिए। अखबार की मंशा देखनी चाहिए कि उन्होंने अच्छी बात रखी है और सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। उसी अखबार ने लिखा है, चाहे अमर उजाला हो या अन्य प्रकाशन कि पुलिस ने पुलिस वालों को पकड़ा। पुलिस के कर्मियों को पद से हटाने वाले पुलिस के डी0जी0पी0 साहब हैं। हमारी सरकार ने होम सेक्रेटरी साहब को कार्रवाई करने की इजाजत दी और उन्होंने नियमानुसार अपनी कार्रवाई की।

अगर हम चिट्टे को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह ठीक है कि आपकी कुर्सी के पीछे कुछ लोग पड़े हैं क्योंकि जो लोग हमने भेजे हैं हम उनके स्वभाव को जानते हैं। हमने 10 लोग भेजे हैं और वे इनके स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वे इन्हें जीने नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि इनको पांच गुटों में डिवाइड कर दिया। वे अपने-आप भी कुछ-न-कुछ बनना चाह रहे हैं लेकिन वे तब बनेंगे जब वर्ष 2027 में जनता अपना फैसला देगी। अभी तो हमें काम करने दीजिए। चिट्टे के खिलाफ मैं विपक्ष, सत्ता पक्ष, समाज के सभी वर्ग और जनता से चाहूंगा कि हमने इन्फॉर्मेशन के लिए 112 नंबर जारी किया है। जो भी चिट्टे की जानकारी देगा उसको प्राइज मिलेगा। हमारी सरकार और मंत्रिमंडल के सदस्य चिट्टे के खिलाफ पूरी तरह कमिटेड हैं और आने वाले समय में और भी वॉकथॉन करेंगे। कुछ चीजें आपको आगे आने वाले समय में नजर आएंगी। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद और आपने

बहुत अच्छा कहा कि यह विपक्ष का वॉकआउट नहीं है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने इन्हें स्पेशल टाइम दिया। हमारे विधायक आपसे नाराज रहते हैं कि उन्हें बोलने के लिए कम समय नहीं मिलता है। विपक्ष को हर बार जब विधान सभा कनक्लूड होती है तो उसमें सबसे ज्यादा समय विपक्ष को दिया होता है। यह अच्छी परंपरा है। लोकतंत्र में विपक्ष बोलेगा तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा और हम उनमें सुधार करेंगे। धन्यवाद ।

**20.03.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

**अध्यक्ष :** शून्य काल समाप्त। आज लगभग 9 विषय शून्य काल में विधान सभा सचिवालय के पास आए थे जो कल के लिए प्रायोरिटी लिस्ट पर होंगे। अब हम आज का बिजनेस करेंगे।

### **कागज़ात सभा पटल पर**

**अध्यक्ष :** अब मुख्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

**अध्यक्ष :** अब लोक निर्माण मंत्री (प्राधिकृत) कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**लोक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

**अध्यक्ष :** अब कृषि मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**कृषि मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 55क के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एग्र0-बी0-ए0 (3)-2/2025, दिनांक द्वारा 06.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 24.01.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

20.03.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

### **विधायी कार्य**

#### **सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना**

**अध्यक्ष** : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

#### **अध्यक्ष श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी**

20-3-2026/1235/NS-YK/1

**अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

**प्रस्ताव स्वीकार  
अनुमति दी गई।**

अब मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूं।

**अध्यक्ष :** हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

**20-3-2026/1235/NS-YK/2**

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

**राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी**

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। अभी मेरे पास 12 माननीय सदस्यों के नाम आ चुके हैं जिनमें से 5 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हैं और 7 माननीय सदस्य भाजपा के हैं। आज मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर भी देंगे यानी चर्चा समाप्त होगी। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि 10-12 मिनट्स में अपनी-अपनी बात समाप्त करें। जो बातें हो चुकी हैं उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कल अंतिम वक्ता भारतीय जनता पार्टी से थे और आज इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष से होगी। अब मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा का आगे बढ़ाएं।

**कृषि मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16 फरवरी, 2026 को राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी ने इस माननीय सदन में अभिभाषण रखा है। यहां पर परम्परा रही है कि कोई भी अभिभाषण कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद राज्यपाल महोदय को जाता है। हमारे संविधान में भी यही बताया गया है कि जो पॉपुलर सरकार चुनी जाती है तो राज्यपाल

महोदय कैबिनेट की aid & advise के ऊपर काम करते हैं। मैं राज्यपाल महोदय के दायित्व के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि संविधान में राज्यपाल का दर्जा बहुत उच्च है। राज्यपाल महोदय ने कुछ टिप्पणियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं और वर्तमान सरकार के बारे में कहा कि कामकाज ठीक नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हिमाचल की सरकार को उत्तराखंड से सीखना चाहिए। उत्तराखंड में कौन-सी सरकार का मॉडल है? उत्तराखंड में सरकार का वह मॉडल है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वहां पर माइनोंरिटी के एक बाबा जी का ढाबा था और वे कुछ सामान बेचते थे। वहां पर शिव सेना के कुछ लोग गए और कहा कि बाबा जी आप अपने ढाबे का नाम बाबा जी मत रखें क्योंकि वहां पर साथ ही मैं एक मंदिर था और उसके साधु का नाम भी बाबा था। उसने कहा कि मेरी दुकान सदियों से यहां पर है और मैं बाबा जी के नाम से ही यहां पर चीजें बेचता हूँ तथा लोग आते हैं कि हम बाबा जी के ढाबे में जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप

**20-3-2026/1235/NS-YK/3**

इस दुकान को 15 दिनों के भीतर बंद कर दें। वहां पर एक नौजवान उसके रेस्क्यू के लिए आगे आया कि आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं? यह ढाबा सदियों से यहां पर चल रहा है और लोग यहां से चीजें खरीदते हैं। वहां पर बजरंग दल के लोगों ने उससे लड़ाई-झगड़ा करने की कोशिश की तो वह नौजवान आगे आया। उसने कहा कि आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। इस तरह से उसने उस बाबा जी के ढाबे को वहीं पर रहने दिया और कहा कि यह ढाबा यहीं पर चलेगा। मैं आपको यह घटना इसलिए बताना चाहता हूँ कि क्या वहां पर इस प्रकार का मॉडल है? हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है जहां माइनोंरिटी और मेजोरिटी के लोगों को

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.03.2026/1240/RKS/AG-1

कृषि मंत्री जारी.....

एक समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ही सबसे बढ़िया मॉडल है। लोग अक्सर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड का उदाहरण देते हैं लेकिन वहां मॉब लिंग और अन्य कई घटनाएं होती रहती हैं। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह एक सुनियोजित चाल है कि जहां-जहां विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कर्नाटक में हो या अन्य राज्यों में हो, जहां-जहां कांग्रेस पार्टी या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहां के राज्यपालों ने एक प्रथा बना ली है कि वे इन राज्यों में अपना अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे लेकिन उस पर टिप्पणी करते रहेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इस अभिभाषण में टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? हमारे कई विधायक कह रहे थे कि पेज 2 से 12 तक केंद्र सरकार के प्रति कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के प्रति इसमें कौन-सी टिप्पणी की गई है? इसमें केवल संविधान के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगर मुख्य मंत्री जी ने संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत छोटे और जरूरतमंद राज्यों को राजस्व सहायता प्रदान करने की व्यवस्था का जिक्र किया है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसकी अधिसूचना वर्ष 1952 में हुई थी और उसी उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन किया गया था ताकि प्रत्येक पांच वर्ष में राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके। यह व्यवस्था संविधान के तहत की गई थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा जो पांच वर्षों के लिए अवार्ड जारी किया गया है उसका सबसे अधिक लाभ श्री जयराम ठाकुर की सरकार को मिला है। उस समय प्रदेश को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी। वित्त आयोग ने यह लाभ राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए दिया था। जब वर्ष 1966 में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया तो यह इस आधार पर नहीं हुआ कि हिमाचल समृद्ध राज्य है। उस समय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर पुनर्गठन किया गया। उस समय एक आयोग का गठन किया गया जिसमें तीन सदस्य थे। एक सदस्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और इसकी संस्कृति और सभ्यता बनी रहनी चाहिए। उस समय स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने दो सदस्यों की सिफारिशों को न मानते हुए एक सदस्य की

20.03.2026/1240/RKS/AG-2

सिफारिश को स्वीकार किया ताकि हिमाचल प्रदेश की अपनी पहचान बनी रहे। तभी जाकर हिमाचल एक प्रदेश बना जिसमें पंजाब के बहुत से इलाकों को मिलाया गया। प्रारंभ में यह केंद्र शासित प्रदेश था जहां भारत सरकार के एक डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी इसका प्रशासन देखता था। आज हम खुद मुख्तयार लोग हैं जहां 70 लाख से अधिक की आबादी है। आज हमारा अपना उच्च न्यायालय, सचिवालय और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है। आज हिमाचल प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त है और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के बराबर खड़ा है। हमारे राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया गया है। जहां तक वित्तीय प्रबंधन की बात है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तियोग द्वारा हमें जो अवार्ड दिया जाता था वह इसलिए दिया जाता था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के संसाधन सीमित हैं। जब मैं पूर्व में वन मंत्री था और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी पर्यावरण मंत्री थे तब मैंने यह मुद्दा उठाया था कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 450 करोड़ रुपये की आय वनों से होती है। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए यह हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ट्री फैलिंग को बंद किया जाए।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

20.03.2025/1245/बी.एस./ए.जी.-1

कृषि मंत्री जारी...

इसी से हमारी जो सारी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरमेंट और दूसरी कंडीशनज प्रीजरव होती हैं। इसलिए हम प्रदेश के जंगलों को नहीं काटते हैं। हमने कहा कि अगर हम इनको नहीं काटेंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं हो सकती और हम फाइनेंस जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें ग्रीन बोनस के रूप में कोई-न-कोई मदद मिलनी चाहिए, ताकि हमारी वित्तीय हालत ठीक रहे।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें पहले पता था कि हमारी आर०डी०जी० बंद होनी थी। क्या सरकार को इसके संदर्भ में कोई सूचना दी गई या कोई नोटिफिकेशन हुई? यह जो 16वां वित्त आयोग बैठा इन्होंने कोई स्टेट को कोई ऐसा आदेश दिया कि राज्यों को इस तरह का अवार्ड नहीं मिलेगा? उन्होंने बहुत सी स्टेटों का जिक्र किया है, जिनकी इनकम जेनरेशन अच्छी है। हमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ है।

जब हिमाचल प्रदेश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया हिमाचल प्रदेश न प्रॉड्यूसर स्टेट है और न ही यह कंज्यूमर स्टेट है। क्योंकि हमारी आबादी 70 लाख के बीच में है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा, यू०पी० हैं, उनके एक शहर की आबादी के बराबर हमारी जनसंख्या है। आप चंडीगढ़ को देख लीजिए यहां कितनी आबादी है। जो आदमी पेट्रोल डाल करके पंजाब से आएगा, वह एक-दो दिन यहां रहेगा उसके बाद पंजाब में जा करके पेट्रोल डालेगा। यहां पर पेट्रोल की खपत कहां है? हमारी खपत डिजल और पेट्रोल की बहुत कम है।

दूसरी जो चीजें जिन्हें हम प्रॉड्यूस करते हैं, उसकी सारी मार्केटिंग बाहर होती है। इनमें चाहे हम दवाइयां तैयार करते हैं या दूसरी चीजें तैयार करते हैं। चाहे परवाणू है, चाहे नालागढ़ है, यहां तैयार दवाइयों की मार्केटिंग बाहर होते हैं। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कमी थी उसको भी वर्ष 2025-26 में बंद कर दिया गया।

20.03.2025/1245/बी.एस./ए.जी.-2

तो यह सारी चीजें हमें युद्ध स्तर पर भारत सरकार के साथ उठानी चाहिए थी। यहां कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, हिमाचल का हित सर्वोपरी है, चाहे हम सत्तापक्ष में हों या विपक्ष में, सभी का दायित्व बनता है कि हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को बनाए रखें। आप क्या चाहते हैं कि हम माइनिंग करते जाएं, जंगलों को काटते जाएं, एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते जाएं। हमारी हालत भी वही होगी जो राजस्थान की है और बार-बार कोर्ट में जाकर के जवाब देने पड़ते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, वह चाहते हैं कि हमारे स्रोतों का कोई एक्सप्लॉइटेशन न हो। इस तरह से हमारे जीवन में माकूल पानी और

बिजली का अच्छा दोहन हो। हम तो राष्ट्र को भी सर्व करने वाले हैं। अगर हम राष्ट्र को सर्व करेंगे, तो राष्ट्र का भी दायित्व बनता है कि जो हमारी आर्थिक कमी है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर है, उसको रिस्टोर करें। इसलिए हम सब लोग यह चाहते थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर सहमत हो। मुख्य मंत्री की भी यही सोच थी कि हम सब भारत सरकार के साथ जाकर बात करें।

दूसरी बात, यहां पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता और परमार साहब ने भी कहा था कि वर्ष 2004 और 2010 में डॉ० मनमोहन सिंह जी ने हमें कम पैसे दिए। उस समय केंद्र की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, मैं उसका विवरण आपके साथ करना चाहता हूं। वर्ष 2004-2014 में डॉ० मनमोहन सिंह के 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिली थी। जिसमें 10,200 करोड़ रुपये और 7,899 करोड़ रुपये के आसपास अनुदान शामिल है, जो कि विभिन्न वित्त आयोगों के तहत वर्ष 2004-14 के दौरान मिला। इसके साथ-साथ डॉ० मनमोहन सिंह जी ने अंतिम वर्षों में राज्यों को पांच बिजली प्रोजेक्ट्स के लिए 1200 करोड़ रुपये दिये। इस तरह से आई०आई०टी० मंडी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा, और इस तरह से डॉ० मनमोहन सिंह ने उस वक्त आई०आई०एम० पांवटा साहिब, सिरमौर ये प्रमुख संस्थान दिया और उसके लिए पैसे का प्रावधान भी किया।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**20.03.2026/1250/DT/AS-1**

**कृषि मंत्री जारी ..**

जो हमारी आर०डी०जी० थी वह 12वें वित्तायोग में भी 8738 करोड़ और 13वें वित्तायोग हमें 7889 करोड़ रुपये उस वक्त डॉ० मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमें मिला। तत्कालीन प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी ने भी कहा था कि जब भी मैं डॉ० मनमोहन सिंह जी से मिला उन्होंने कहा कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है आपकी जो भी समस्या है वह आप टेलिफोन के माध्यम से बता दें उसका मैं यही से समाधान करूंगा। इन बातों की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। 9 सितम्बर, 2025 को जब देश के माननीय प्रधान मंत्री जी कांगड़ा में आए उस वक्त हम भी वहां पर थे पर वहां हमारी पार्टी के तीन

लोग ही थे। जिनमें हमारे मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री व मैं स्वयं था। लेकिन भाजपा से नेता प्रतिपक्ष श्री जय राहम ठाकुर जी वहां पर थे, प्रदेश के सभी सांसद वहां पर थे, भाजपा का विधायक दल वहां पर था, भाजपा के बहुत से एक्स-एम0एल0ए0 वहां पर थे। इसके अलावा जो कैंडिडेट आगे टिकट लेने के इच्छुक थे वे भी वहां पर खड़े थे। एक लंबी लाइन उन लोगों ने बनाई हुई थी। प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी वहां पर दी गई। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 1500 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत मैं आप को भेज दूंगा। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि वह 1500 करोड़ रुपये कहां है, क्या वह दिल्ली से आ गए? अध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। नेता प्रतिपक्ष तो स्वयं वहां पर थे। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद भी वहां पर थे। वहां पर प्रधान मंत्री जी ने राहत पैकेज की घोषणा की थी। हम मानते हैं कि प्रधान मंत्री जी को बहुत से काम होते हैं शायद वह भूल गये हों, लेकिन प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सांसद वहां पर हैं उनको इस मामले को केंद्र सरकार से टेकअप करना चाहिए था। प्रधान मंत्री जी से बात करनी चाहिए थी। जब आप लोग इतनी लंबी लाइन बना कर प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए थे तो क्या आप केवल उनका स्वागत करने के लिए ही वहां गये थे? हमारी पार्टी की ओर से तो हम केवल तीन ही आदमी वहां पर थे। हां, अध्यक्ष महोदय भी वहां पर थे। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश को नहीं मिली है। मेरा कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है।

यू0पी0ए0-1 के समय में पांच बड़ी-बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। उसमें Right of Employment के अंतर्गत मनरेगा जैसी योजना चलाई गई। जब 2004 में मनरेगा का एक्ट बनाया गया था, उस समय मैं भी सांसद था। संसद में सभी दलों के

### **20.03.2026/1250/DT/AS-2**

सदस्यों के द्वारा ध्वनीमत से इसे पारित किया गया था। इस एक्ट का सुझाव देने वाला व्यक्ति ज्यां ट्रेज था जो बहुत ही अच्छा अर्थशास्त्री था। उसने कहा था कि देश की महिलाओं की 52 प्रतिशत जनसंख्या गांव में है और उन्हें कोई भी फाइनेंशियल बनेफिट नहीं मिलता। इसलिए ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे गांव की महिलाएं भी कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उन्हें वित्तीय लाभ हो। इस योजना का नाम बाद में महात्मा गांधी

रोजगार गारंटी योजना रखा गया। गारंटी, यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी। वर्तमान केंद्र सरकार ने इसका नाम ही बदल दिया और अब इसका नाम वी0बी0-जी0आर0ए0एम0 जी0 रख दिया है। इस योजना की गारंटी ही केंद्र सरकार के द्वारा खत्म कर दी गई है। इसमें जो गारंटी थी उसके अनुसार यदि 100 दिन का रोजगार इस एक्ट के अंतर्गत यह भी प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत रोजगार नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को 50 दिन का वेतन सरकार के द्वारा घर बैठे दिया जायेगा। अब जो भी स्कीम पंचायत सत्र पर आयेगी वह पंचायत का प्रधान नहीं बनायेगा। पंचायत का कोई मेम्बर नहीं बनायेगा। वह स्कीम दिल्ली से बनकर आयेगी। दिल्ली से चलकर वह पंचायतों तक पहुंचगी। आप को तो पता ही है हमारे प्रदेश में पंचायतों का क्या आकार है, वहां की क्या समस्याएं हैं। पंचायतों का जो विकास वहां के स्थानीय प्रतिनिधि करना चाहते हैं उसके लिए जो उनके पास शक्तियां हैं, वह तो सारी केंद्र सरकार द्वारा स्नैच कर ली गई हैं। जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी वह भी केंद्र सरकार ने समाप्त कर दी। मनरेगा का शुरू में मजाक उड़ाया जाता था। प्रदेश के वर्तमान प्रधान मंत्री कहते हैं कि मनरेगा में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गड्डे खोदने के लिए कार्य में लगा दिया। केंद्र सरकार कोई नई स्कीम लेकर आती। वी0बी0-जी0आर0ए0एम0 जी0 यह कैसी स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है। आप को तो महात्मा गांधी जी से भी नफरत है।

**श्री एन0जी0द्वारा जारी..**

**20.03.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./1**

**कृषि मंत्री..... जारी**

इसलिए आपने इस योजना का नाम बदलकर बीच में 'राम जी' लगा दिया। हमारी अगली योजना राइट ऑफ हैल्थ की थी। उसमें 102 नम्बर व 108 नम्बर की गाड़ियां चलती हैं। यह भी उसी वक्त यानी के हमारी केन्द्र सरकार के समय में कानून बना था जिसका नाम राइट टू हैल्थ है। आप लोग कहते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को चलाया है लेकिन आपने इसके लिए सिर्फ 40 करोड़ रुपये दिए। क्या 40 करोड़ रुपये से हिमाचल प्रदेश के लोगों की हैल्थ सुधर जाएगी? जब मुख्य मंत्री जी ने इसकी एक कमेटी बनाई और उसके बाद हमने देखा कि 450 करोड़ की लाइबिलिटी है और आप की पूर्व

सरकार ने तो सिर्फ 40 करोड़ रुपये दे थे। आप लोग इसी प्रकार से वाह-वाही लूट रहे हैं। उसके बाद आपने यहां पर नई स्कीम शुरू कर दी और जितने आपने पैनल में हॉस्पिटल लिए, उनको फायदा दिया, जिससे सरकार को नुकसान हुआ।... (घण्टी)... आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी बदल दिया। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, उसकी भी आपने धज्जियां उड़ा दीं और उसको भी बदल दिया। राइट टू फूड एक्ट के तहत हमने कहा कि गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए। एक आदमी को 20 किलोग्राम राशन मिलता था। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी तीन प्रकार की दालें देती थी। आपने राइट टू फूड को बदलकर श्री नरेन्द्र मोदी जी की फोटो वाला एक बैग लगा दिया। डॉ० मनमोहन सिंह जी ने बैग तो दिया नहीं लेकिन उन्होंने लोगों के लिए एक कानून जरूर बनाया। डॉ० मनमोहन सिंह जी भी अपनी फोटो वाला बैग लोगों को दे सकते थे। आपकी केन्द्र सरकार ने फोटो वाला बैग देकर लोगों को बताया कि हम सस्ता राशन दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सारा पैसा भारत सरकार के माध्यम से आ रहा है। हमारे चौपाल से माननीय विधायक श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने भी कहा कि केन्द्र सरकार से सारा पैसा आ रहा है।

**20.03.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./2**

मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा आज से या 15 साल से नहीं आ रहा है। मैं भी मंत्री व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं। भारत सरकार 90-10 के अनुपात में कुछ परियोजनाएं देती है और कुछ को 80-20 के अनुपात में देती है। जैसे आपका RIDF (Rural Infrastructure Development Fund) है जिसका शायद 15वां या 16वां संस्करण चला हुआ है। यह भी भारत सरकार की योजना है। राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना को पहले चम्बा व सिरमौर में शुरू किया गया था और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली के सुधार के लिए इस योजना के तहत पैसा दिया जाता है। ये नई बातें नहीं हैं। आप बार-बार कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करो। क्या पहले, जब ये योजनाएं चल रही थीं, कोई प्रधान मंत्री नहीं

था? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक, क्या हम सभी प्रधानमंत्रियों का धन्यवाद करते रहें? क्या हम आपके प्रधान मंत्री के लिए घंटी बजाते रहें? यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हर चीज़ के लिए केंद्र से पैसा आता है, जैसे पानी के लिए, सड़कों के लिए और दूसरी योजनाओं के लिए पैसा आता है। आप कहते हैं कि श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करो, किस चीज़ के लिए धन्यवाद करें? क्या अन्य प्रदेशों में नेशनल हाईवे नहीं बन रहे हैं? क्या हमारा ही राज्य धन्यवाद करने के लिए है? क्या शेष राज्य धन्यवाद करने के लिए नहीं है?... (व्यवधान) एक काम के लिए पैसा आता है तो विपक्ष के लोग धन्यवाद करने की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि density of road is so high. एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 80 से 90 प्रतिशत क्षेत्र सड़कों से जुड़े हैं। आज प्रदेश के दूर-दूर के गांवों तक बिजली पहुंची हुई है। क्या वह बिजली केवल 15 साल में हर गांव तक पहुंची है?... (घण्टी)...

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने नए-नए कानून भी बना दिए हैं। जैसे Citizenship (Amendment) Act, फिजूल का काम इससे क्या होगा? उसके बाद आपने Special Intensive Revision (SIR) का कानून बना दिया

**20.03.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./3**

मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे कितने घुसपैटिए निकले? आपने इसे बिहार में किया, कितने घुसपैटिए निकले? क्या कोई रिपोर्ट आई? आपने मध्य प्रदेश में इसे लागू किया। आपने हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में कौन-से घुसपैटिये हैं? क्या आप लोगों के गांवों में कोई घुसपैटिया पकड़ा गया? आप लोगों को किस ओर लेकर जा रहे हैं?

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**20.03.2026/1300/ए.पी./डी.सी./01**

कृषि मंत्री जारी .....

आपने एक और नया कानून बना दिया (\*\*\*) इस प्रकार के बेतुका कानून बना दिये गये हैं। इस तरह के कानून आपने बनाए हैं।...(व्यवधान) आप सुनिये ...(व्यवधान)

**Speaker** : No interruption please.

**कृषि मंत्री** : मेरी बात सुनो क्या आपने Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 को क्या कभी पढ़ा है? जो मितव्ययिता आपने अपने समय में की थी, उस मितव्ययिता में Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 में इनेक्ट हुआ था कि जो हमारे साधनों के लिए पैसा आता है उसका हम सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे। आपने अपने समय में धर्मशाला में एक इंडस्ट्रियल मीट ऑर्गेनाइज की और वहां पर देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था। आपने माननीय प्रधानमंत्री के सूट और वहां पर लगाये गये टैटों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। लगभग 30 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ होगा। आप मुझे यह बताइये की उस इंडस्ट्रियल मीट में कौन आया था? धर्मशाला के कैंटोनमेंट एरिया के कुछ लाले थे, जो इस इंडस्ट्रियल मीट में आये थे। अब आप ही बताओ की वे लाले वहां पर क्या कर रहे थे। उनको वहां पर पूछा गया कि आपने कौन-सी इंडस्ट्री लगाई है, जिसमें आप काम कर रहे हैं। वह कहने लगे मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मेरी तो एक जूते बेचने की दुकान है। मुझे इन्होंने बुलाया और मैं यहां आकर बैठ गया हूं। आप ही सोचो आपकी क्या हालत है? माननीय जय राम जी आप बताइये की आपको नौजवानी में मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला था। उस समय अगर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री प्रो० प्रेम कुमार धुमल जी जीत गये होते तो आपको भी मेरे वाला महकमा मिलना था। अगर माननीय प्रो० प्रेम कुमार धुमल जी जीतते तो आप कभी प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं बन सकते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में मितव्ययिता की है। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने सीमित साधनों के होते हुए भी, रेवन्यू जनरेट करने की कोशिश

(\*\*\*)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

20.03.2026/1300/ए.पी./डी.सी./02

की है। तीन वर्षों में हमने 3300 करोड़ रुपये गैर राजस्व लगभग 166 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। हमने कुछ-न-कुछ तो अपने साधनों से रेवन्यू जनरेट किया है, चाहे सैस या अपने साधनों को एक्सप्लोर करके पैसा जनरेट किया है। हमने छोटे-मोटे भी लगाए जिससे हमने पैसा जनरेट किया। आपने अपने पांच सालों में क्या किया यह आप हमें बताएं? आपको सरकार से 55,000/- करोड़ रुपये मिले, जिसकी आपने मितव्ययिता की। आप तो यह भी कहते थे कि मिशन रिपीट होगा। मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ आपका मिशन रिपीट? आपका मिशन तो डिफीट हो गया। हमने अपनी सरकार के समय कोई भी सरकारी कर्मचारी को नहीं बदला है। आप देख लीजिए, वे सभी आपके सामने ही हैं। ये अधिकारी क्या राय देते थे आपको। आप जितना मर्जी खर्च करते जाओ और आपकी सरकार रिपीट होगी। फिजूलखर्ची करके सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, बल्कि ग्राउंड पर काम करने से सरकारें रिपीट होती हैं। लोगों की भलाई की स्कीमों से सरकारें रिपीट होती है। मैं तो वर्तमान मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों में भी उन्होंने सरकार को अच्छी तरह से चलाया है। आप की सोच यह है कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय आपात स्थिति लगाकर के सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन आपके मनसूबे कामयाब नहीं होंगे। आपकी यह मंशा कभी भी कामयाब नहीं होगी। ... (व्यवधान) मेरी बात तो सुनों ... (व्यवधान) आपने ... (व्यवधान)।

**अध्यक्ष :** बैठे-बैठे ना बोलें कोई भी।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

20.03.2026/1305/AT/DC /01

**अध्यक्ष :**....(व्यवधान)। No interruption please. ....(व्यवधान)। जम्वाल जी प्लीज बैठे-बैठे ना बोलें कोई भी, I am not allowing this. बैठिए, बैठिए। Order in the House. बैठिए बैठिए अपनी-अपनी जगह बैठिए, त्रिलोक जी बैठिए, बैठिए I have not allowed

anybody to speak. बैटिए, बैटिए Take your seats please. चलिए चंद्र जी कन्क्लूड करिए, बैटिए, बैटिए ....(व्यवधान)। Please take your seats. त्रिलोक जी बैठो बैठो take your seats. आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई जरूरी इंटरवेंशन चाहिए होगी तो मैं समय दूंगा ....(व्यवधान) चंद्र जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। Let the Hon'ble Minister complete his speech. ....(Interruption). The senior most Member of the House is speaking. He has experience of more than fifty years in Legislature as a Minister, Member of Parliament and Member of Legislative Assembly and in Organization. ....(Interruption). He is senior most Member and this much respect he requires. Please take your seats. ....(Interruption). यह बहुत प्यार से बोल रहे हैं, बहुत प्यार से सुना रहे हैं। बैटिए बैटिए ठाकुर साहब बैटिए, please take your seat. बैठो तो सही उनको कम्प्लीट करने दो ना, यह बहुत अच्छा बोल रहे हैं ये। अब इसके बाद परमार साहब बोलेंगे तो वह जवाब दे देंगे।...(व्यवधान) सीनियर मोस्ट मेंबर बोल रहे हैं...(व्यवधान) तो थोड़ा बहुत तो एक्सेप्शन तो देना पड़ता है, चलिए चंद्र जी complete your statemet. चंद्र जी आप अपना भाषण पढ़ो।

**कृषि मंत्री** : अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

**अध्यक्ष**: हर्षवर्धन चौहान जी बैठ जाइए।...(व्यवधान) सारे बैठ जाओ। I am requesting everybody to sit down. ....(Interruption). आप सारे नहीं मान रहे, चंद्र जी के अलावा बाकी सभी बैठ जाओ। Please take your seats. ...(Interruption). चंद्र जी को खत्म करने दो, उसके बाद मैं आपको भी चांस दूंगा, he is finishing his speech. माननीय मंत्री जी को स्पीच खत्म करने दो...(व्यवधान) आप भी बैठ जाओ।...(व्यवधान) बैठो, आप सभी बैठो प्लीज। ठाकुर साहब बैठो, ठाकुर साहब बैठो तो सही आप। इनको खत्म करने दो, फिर मैं देता हूं चांस। ...(व्यवधान)

**20.03.2026/1305/AT/DC /02**

**कृषि मंत्री**: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पिछली बार भी लोटस ऑपरेशन किया था... ..(व्यवधान) उस समय लोटस ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ...(व्यवधान)

श्रीमती के०एस०द्वारा जारी .....

20.03.2026/1310/केएस/एचके/1

कृषि मंत्री जारी ---

अध्यक्ष महोदय, हम दोबारा लोगों के दरबार में गए और लोगों ने हमें दोबारा समर्थन दे कर हमारे 40 विधायक पूरे हुए और हम ठीक ढंग से सरकार चला रहे हैं। ... (व्यवधान) जय राम ठाकुर जी, आपकी सरकार जाती दफ़ा बहुत से ऑफिस खोल कर गई। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी कई ऑफिस खोले गए। हमारे चुनाव क्षेत्र में उस वक्त आपकी पार्टी से विधायक था। हमारा एक सीनियर सैकंडरी स्कूल कोटला है। उसने वहां पर 5 फट्टे लगा दिए और लिख दिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ... (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लो। बिल्डिंग के ऊपर वहां चार प्लेटें लगा दीं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटला, फिर लिख दिया गवर्नमेंट आई०टी०आई० कोटला, फिर एक और ऑफिस का नाम लिख दिया तो मैंने कहा कि जाती बार वैटरनरी भी लिख देना था। फट्टे लगाने से कुछ नहीं होता। जब कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो उसके लिए बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, फाइनेंशियल अप्रूवल होती है, पैसा आने के बाद उसको आप चलाओ, बनाओ और लोगों को हैंडओवर करो। मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। आज हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल्ज़ में, चाहे फतेहपुर है, चाहे नूरपुर, इंदौरा या ज्वाली है, आज सुपर स्पेशलिटी के 6 से 7 डॉक्टर वहां बैठते हैं। ... (व्यवधान) मेरी बात सुन तो लो। आज वे संस्थान सबसे बढ़िया चल रहे हैं। एजुकेशन में हमने डे-बोर्डिंग स्कूल का काम शुरू किया है। आज हमने सी०बी०एस०ई० का सिलेबस 3-3, 4-4 स्कूलों में, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनमें शुरू किया है। मुख्य मंत्री जी ने एक और अच्छा कार्य किया है। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती में एम०एस०पी०, 60 किलो रुपये गंदम, 40 रुपये किलो मक्की और 90 रुपये किलो हल्दी ली है। मैंने अपनी गंदम 2400 रुपये क्विंटल बेची और 24 रुपये किलो बेची है और अब हम 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पहली स्टेट है जिसने इस प्रकार के एग्रेरियन रिफॉर्मज़ लाए हैं। हमारी इकोनॉमी दूध के साथ जुड़ी है, पशुधन के साथ जुड़ी

है। हम पढ़ते थे कि agriculture is a bioculture. यह हम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते थे और आज देखिए हमने भैंस का दूध 60 रुपये किलो और गाय का दूध 50 रुपये किलो कर दिया है। सितम्बर में हमारा डगवार में सबसे बड़ा कारखाना बनने जा रहा है जिसके ऊपर लगभग 117 करोड़ रुपये आज

**20.03.2026/1310/केएस/एचके/2**

तक हमने खर्च कर दिए हैं। दूध का इस वक्त 180 करोड़ रुपये के लगभग सैस हमें आ रहा है और वह सारा का सारा पैसा किसानों को जा रहा है। इससे अच्छी इकोनॉमी और क्या हो सकती है? मुख्य मंत्री जी की सोच है कि चलो गांव की ओर। गांव की व्यवस्था अच्छा होगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। हमारे लोग अच्छे होंगे और हम समृद्ध हिमाचल बनाएंगे। अध्यक्ष जी, समय हो रहा है और आप घंटी भी बजा रहे हैं लेकिन अभी कहने को बहुत सी बातें हैं। रेवन्यू डिपार्टमेंट में कितने मामले फंसे रहते थे। समय पर निशानदेही नहीं होती थी, इंतकाल नहीं होते थे। आज हमने सारी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। हम 65 करोड़ रुपये का चिन्तपुरनी में एक आलू का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**20.03.2026/1315/av/hk/1**

**कृषि मंत्री----- जारी**

ये सारी कृषि के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कहना चाहता हूं कि हम इस स्टेट को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से चलाएं। हम चाहते हैं कि आप हमारी आलोचना करें लेकिन आलोचना के साथ-साथ अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि रोज़ गाली निकालो या हल्ला-गुल्ला करो। ऐसा करने से सरकारें नहीं चलती। पक्ष और प्रतिपक्ष बहुत जरूरी है इसलिए हम सब मिलकर इसे वृहत हिमाचल बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश हेतु 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

**20.03.2026/1415/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.15 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)**

**अध्यक्ष :** अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी भाग लेंगे।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जो माननीय राज्यपाल जी द्वारा इस सदन में दिनांक 16 फरवरी, 2026 को अभिभाषण के रूप में एक वर्ष की जानकारियां रखी गईं, मैं उस चर्चा में अपने आप को शामिल करता हूं।

वैसे तो मैं यह कह सकता हूं कि जो अभिभाषण है, वह एक वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। हिमाचल प्रदेश को हम कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से नए इनोवेटिव आइडियाज के रूप में एक वर्ष में क्या कुछ नया किया गया, वह इस अभिभाषण में होता है। इनके क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल शक्ति इत्यादि। परंतु जब मैंने इसे गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा और जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल जी ने भी किया कि मैं कुछ पैराग्राफ को छोड़ रहा हूं, उनको पढ़ा हुआ समझा जाए। यहां पर भी सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों और अन्य नेतागणों ने अपने-अपने विचार रखे, उन्होंने भी आर0डी0जी0 के बारे में चर्चा की। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सदन में बोलिए, आपको अधिकार है। आप तथ्यों के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं।

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी**

20-3-2026/1420/NS-YK/1

श्री विपिन सिंह परमार-----जारी

परन्तु सरकारें समन्वय, तालमेल और संवाद के आधार पर चलती हैं। हम कभी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं या गांव में कहीं जाते हैं तो वहां पर सुधार सभाएं होती हैं और अन्य कई प्रकार की संस्थाएं बनी होती हैं तथा उनका सोचना अलग प्रकार का रहता है। अगर यहां पर जिस पार्टी को प्रदेश चलाने की जिम्मेवारी दी गई हो तो वहां पर उनका नज़रिया प्रदेश के परिपेक्ष में होना चाहिए और हमें वह दिख नहीं रहा है। शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, यह तो हमारा हक है। फिर सत्ता पक्ष की तरफ से हमें यह कहा जाता है कि आप आर0डी0जी0 के ऊपर अपना रूख बताइए। हम कहते हैं कि हमारा रूख तो यही है कि हम अपने संसाधनों को किस प्रकार से अधिकाधिक कर सकते हैं। अधिकाधिक का मतलब है कि हम उनको जनरेट कर सकते हैं। मुझे यह भी जानकारी है कि यहां पर कैबिनेट की एक सब-कमेटी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए बनी थी। उसका इस दस्तावेज में अगर हवाला आता और अगर विपक्ष के सदस्यों को भी उस कमेटी में जोड़ा जाता कि हिमाचल प्रदेश को हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं तो अच्छा होता लेकिन इस दस्तावेज में उन बातों का कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां पर अभिभाषण के ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। यह कहा जा रहा है कि पिछले तीन वर्षों में जितना भी डिजास्टर आया है उसमें बी0जे0पी0 कहीं-न-कहीं शामिल है यानी आपमें बी0जे0पी0 का खौफ पैदा हो गया है। ऐसा तो होगा भी क्योंकि अब तो सरकार के केवल 16 से 17 महीनों का ही कार्यकाल शेष है। जनता और समाज का रूख क्या है इसको हम और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज का रूख क्या है? आपदा आए तो कहा जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया और फाइनेंशियल डिजास्टर आता है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। यहां पर एक खौफ लोटस ऑपरेशन का भी है। यहां पर कहा गया कि आपके पार्टी में 6 लोग आ गए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम उनको पकड़

कर जाए? पूरा देश कमलम हो रहा है तो उसमें हम क्या कहें। आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। जो आए थे वे चोरी-छिपे नहीं आए। वे बिल्कुल सामने आए और उनको

20-3-2026/1420/NS-YK/2

लगा कि जहां से हम जीत कर आए हैं वहां पर हमारी आवाज़ और आत्मा को दबाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हमारे से भी कुछ लोग सम्पर्क कर रहे थे और कह रहे थे कि परमार साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपके पार्लियामेंट क्षेत्र से एक नया व्यक्ति आ गया। हमने कहा कि आ गया तो आ गया, ठीक है।

आर०के०एस० द्वारा -----जारी

20.03.2026/1425/RKS/AG-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी..

यानी बैजनाथ से एक नया व्यक्ति आ गया और आप कुछ कीजिए। हमने उन्हें कहा कि हम एक नीति या दिशा के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं। हम लोटस ओपेशन में विश्वास नहीं करते। हम अपने विचार को जन-जन तक पहुंचाने वाले लोग हैं। ...(व्यवधान) कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का परिदृश्य और हालात बदल रहे हैं लेकिन वित्तीय अनुशासन तो आपको स्वयं बनाना होगा। मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले समाज को बताने के लिए यह लीपापोती की कि जो हमने कैबिनेट स्तर के चेयरमैन बनाए हैं उन्हें कैबिनेट रैंक से हटा दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं परंतु मुख्य मंत्री जी इस वक्त यहां उपस्थित नहीं है। हमारी बात रिकॉर्ड में आ रही होगी इसलिए आप इस बात को बाद में सुन लेना। आपने केवल सात लोगों को ही कैबिनेट रैंक में नहीं बिठाए था बल्कि ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्हें आपको पदमुक्त करना चाहिए। आप इसके लिए साहसिक निर्णय लीजिए। आपने तो Chief Parliament Secretary भी बनाए थे। ...(व्यवधान) अवस्थी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बाद में

बोल लेना। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आपने जो हाई कोर्ट में जो वकीलों की बड़ी फौज बिठाई है उसके लिए सरकार के खजाने से हर केस के हिसाब से करोड़ों रुपये जा रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब आया है कि वहां पर वकीलों को एक पेशी के करोड़ों रुपये दिये जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी के पास वित्त विभाग भी है और आपको इस दिशा में सही कदम उठाने चाहिए। अगर आप विपक्ष से सलाह लेने की मंशा रखते होंगे तो हम इसके लिए तैयार हैं। आपने कई एडवाइजर, ओ0एस0डी और चेयरमैन बना दिए हैं। आपको यह जानकारी थी कि Chief Parliament Secretary का पद ऑफिस ऑफ प्रोफिट में आता है लेकिन इसके बावजूद भी आपने 6 लोगों को मुख्य संसदीय सचिव बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कभी-न-कभी गाज गिर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी वैचारिक आदमी हैं और हम भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि

20.03.2026/1425/RKS/AG-2

28 प्रदेशों में से 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकारें सत्तासीन हैं। ये सरकारें हवा के झोंकों से नहीं बनी हैं। इन सरकारों को बनाने के लिए करोड़ों मतदाताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का श्रम लगा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहां पर हमारी सरकारें सत्ता में हैं वहां समाज को लोक लुभावने नारे और गारंटियां नहीं दी गई हैं। यानी बेस्ट परफोर्मेंस और ट्रांसपेरेंट आधार पर गुड गवर्नेंस के रूप में हमारी सरकारों ने काम किया है जिसके बलबूते ये सरकारें पूरे देश में आई हैं। लोग यहां पर भी सरकार बदलने का इंतजार कर रहे हैं। मेघ बरस रहे हैं, बादल है, सूर्य का उदय होगा और यहां पर भी कमलम खिलेगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि RDG बंद हो गई है। ...(व्यवधान) श्री संजय रत्न जी आप मेरी बात सुनिए। ज्वालामुखी और सुलह विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल नजदीक है। हमारा रास्ता वहीं से होकर आगे जाता है। यह ज्वाला पूरे हिमाचल में और जिला कांगड़ा के हर विधान सभा क्षेत्र में फटेगी। ये कह

रहे हैं कि श्री जय राम ठाकुर जी को 89 हजार करोड़ रुपये मिले। यह अच्छी बात है। जो हैड ऑफ द स्टेट होते हैं उन्हें केंद्र सरकार से अपनी पैरवी और अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। मैं 14वें तथा 15वें वित्तायोग की सिफारिशों पर बात कर रहा हूँ। मुख्य मंत्री जी मैं जिस विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ उस पर चर्चा करने के लिए आपने पिछले महीने 16 से 18 मार्च, 2026 तक यहां सदन आयोजित करवाया था।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

20.03.2025/1430/बी.एस./ए.जी.-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

मैं जिस पर अपने विचार रख रहा हूँ, पिछले महीने 16 से 18 तारीख के बीच मैं अपने यहां पर अधिवेशन बुलाया या सेशन बुलाया और नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनी। हम स्पष्टीकरण चाहते थे परंतु वह नहीं मिला तो हम वैल में गए। आप तो चाहते थे कि हम बाहर चले जाएं ताकि यह खबर बन जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल जितना प्यारा आपको है, उससे कहीं ज्यादा प्यारा हिमाचल हमारे लिए है। आप दिल्ली प्रस्ताव लेकर के गए और मंत्री भी गए। हमें तो कहते हैं कि हमारे साथ चलेंगे। आप दिल्ली में कहां-कहां घूमते रहे। आप कनाॅट प्लेस घूमते रहे या पालिका बाजार घूमते रहे या फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास फोटो खिंचवाते रहे। अच्छा होता आप देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लेते, फाइनेंस मिनिस्टर समय लेते। प्रदेश के और बड़े नेताओं से समय लेते और वहां पर अपना पक्ष रखते। परंतु वहां पर क्या नया काम करके आ गए। हिमाचल प्रदेश की छवि को खराब करके आ गए। कई बार हमारा व्यवहार भी बोलना है। हमने उसको कैसे तार-तार कर दिया। वहां पर पूरी दुनिया के राष्ट्रा अध्यक्ष और ए0आई0 से संबंधित लोग आए थे। आपने कपड़े उतार करके वहां पर उसका विरोध किया। जो पार्टी पहले ही अर्धनग्न है और कितनी नंगी होगी? पूरी नंगी है।

इनके एक नेता ने कहा, मेरे बब्बर शेर। बब्बर शेर कैसे होते हैं? नंगे तो होते ही हैं परंतु वहां पर कृत्य करने के बाद जो हिमाचल भवन और सदन है, वहां कई बार हमारे

जैसे इलेक्टेड लोगों को जगह नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक रिपोर्ट मंगवाना चाहते हैं। वहां पर क्या-क्या हो रहा है? वहां पर एक शरण स्थली बनी हुई है। अपने कैडर के या अपने नेताओं के परिवारों को या शुभचिंतकों को वहां पर सहारा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि मुझे एक बार हिमाचल भवन दिल्ली में जद्दोजहद करनी पड़ी तब जा करके कमरा मिला। ऐसे विविन परमार अकेला नहीं है, ऐसे दर्जनों विधायक हैं, जी०ए०डी० की ओर से यह सब कुछ किया जा रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं। आर०डी०जी० का सदुपयोग कैसे होता है? मुख्य मंत्री सुला विधान सभा क्षेत्र में भी गए थे। वहां पर उन योजनाओं का उद्घाटन करके आ गए जो मुझे याद है कि वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के बीच में जब हमारी सरकार थी एन०डी०बी० प्रोजेक्ट में हमने लगभग 32 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया था। अभी उसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई, पाइपें

20.03.2025/1430/बी.एस./ए.जी.-2

भी फट रही हैं। आदरणीय गोमा साहब, आप भी उस सभा में थे। मैंने फोटो में देखा आप भी बड़ी तालियां बजा रहे थे और साथ में बैठे हुए थे। वहां पर मुझे याद है, उस समय की योजना श्री जय राम ठाकुर जी के माध्यम से स्वीकृत हुई थी। एक नवोदित नेता है, अपना फोटो चिपका दिया और फटा लगा दिया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नेम प्लेट के साथ फोटो लगाया जा रहे हैं और हमारा कहीं नाम ही नहीं है। खैर, हमारे नाम की जरूरत नहीं, हम लोकतंत्र में लोगों पर विश्वास करते हैं और लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी बस्ती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अन्य कामों का जिक्र करना चाहता हूं, सुलह विधान सभा क्षेत्र में हाल में ही 10.50 करोड़ रुपये से मिनी सचिवालय बन रहा है। वहां न लिफ्ट लगी है, राजस्व मंत्री महोदय कृपया, आपने रिपोर्ट मंगवा लेना। वहां पर न तो टेबल है न कुर्सियां हैं, न इत्यादि-इत्यादि, एक कार्यालय को चलाने के लिए जो सामान चाहिए वह वहां नहीं है और न उस मिनी सचिवालय तक पहुंचाने के लिए रास्ता है। उसका भी उद्घाटन कर दिया।

एक सिविल हॉस्पिटल धीरा है जिसके लिए 4.50 करोड़ रुपये, एक अस्पताल को चलाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी है वह भी नहीं बना है, वह भी नहीं बना तो क्या जल्दबाजी है? इस जल्दबाजी का कारण क्या है? यह मैं जानना चाहता हूँ? मैं यहां पर यह सारी बातें इसलिए रखना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मुख्य मंत्री जी का दौरा हुआ, उस दौर में नौजवानों को बुलाया गया। सुलह विधान सभा क्षेत्र में पी0टी0सी0 है। वहां पर पासिंग आउट परेड की गई।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**20.03.2026/1435/DT/AS-1**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी...**

और उसकी सूचना वहां के विधायक को नहीं थी। वहां पर युवकों और बच्चों को बुलवाया गया। वहां पर न तो जनप्रतिनिधि और न ही जनता थी। अब आयेगी भी कैसे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब सरकार की जनसभाओं में नहीं जाना, इसलिए नौजवानों को बुलाया गया यानी अब नौजवानों को बुलाकर अपनी जनसभाओं को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। वेल्फेयर स्टेट में एक मुख्य मंत्री और राज्य सरकार को भी जनता के वेल्फेयर के लिए काम करना चाहिए। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान आम जन-जीवन प्रभावित था उस समय भी माननीय प्रधान मंत्री श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा "वसुधैव कुटुंबकम" जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन को आत्मसात करते हुए पूरे विश्व की चिंता की गई थी। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस समय वैक्सीनेशन में अगर कोई प्रदेश देश भर में प्रथम आया था-वह हिमाचल प्रदेश था। आपदा उस समय भी थी लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार उस आपदा में भी एक योद्धा बनकर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही पर सरकार ने वित्त संबंधि कोई रोग नहीं रोया। उस समय विकास के काम भी होते रहे। मानदेय और वेतन भी समय में लोगों को मिलता रहा। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ भी ठीक ढंग से उपलब्ध होती रही।

सहारा योजना आज बंद होने की कगार में है। आयुष्मान योजना भी बंद होने की कगार में है। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जोनल होस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर आपकी इंटरवेंशन चाहता हूँ। रोबोटिक सर्जरी

से संबंधित दस्तोवेजों को इस सदन में रखा जाए। क्योंकि डिवेंसी, जो अमेरिकन कंपनी है, वह 28 करोड़ रुपये की मशीन दे रही है और इंडियन मेड एस0एस0आई0 मंत्रा कंपनी की मशीन 5 करोड़ रुपये की मिल रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अमेरिकन कंपनी की वह मशीन कितनी एडवांस स्तर की है? उससे किस प्रकार की और कितनी प्रकार की बीमारियों का उपचार होता है। और मंत्रा कंपनी की मशीन से नहीं होता? इसकी जानकारी लेने का अधिकार हम सभी का है।

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष गंभीर बीमारियों का उपचार करवाने के लिए बनाया गया कोष था। कुछ छोटी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के खजाने से वह पैसा इस कोष में जाता था और हर वित्त वर्ष में उसमें

**20.03.2026/1435/DT/AS-2**

15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाती थी। ई0डी0एल0 यानी Essential Drugs List के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा। आज की तारीख में हेल्थ सब सेंटर तो छोड़िये बल्कि मेडिकल कॉलेज में भी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए जैसे डोलो, पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन व आयरन की गोलियां तक उपलब्ध नहीं हो रही है। चढ्यार की पी0एच0सी0 को यदि सी0एच0सी0 बनाया है तो वह भाजपा की पूर्व सरकार ने बनाया है। अगर मैं पालमपुर होस्पिटल की बात करूं तो वहां पर भी पीडियाट्रिशियन का पद खाली। इसके अलावा वहां पर एनेस्थेटिस का पद भी खाली पड़ा है। जब सरकार ही बेहोशी में है तो प्रदेश का क्या होगा। अगर वहां पर कोई डाक्टर मैटरनिटी लीव पर है श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**20.03.2026/1440/ए.एस.-एन.जी./1**

**श्री विपिन सिंह परमार..... जारी**

तो व्यवस्था सरकार करे लेकिन सरकार बेहोश है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है। मैं अपनी बात को बहुत लम्बा न करते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ। कल बहुत बड़े आरोप लगाए गए कि श्री जय राम ठाकुर जी...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे आप 5-7 मिनट देंगे तो मैं अपनी बात पूर्ण कर दूंगा।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए हैं और अभी मैंने घंटी भी नहीं बजाई है।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी 33 मिनट बोले हैं। ...(व्यवधान) आप कृषि व पशुपालन मंत्री हैं और मैं स्पीकर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, उस दौरान कहा गया कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, कल आप बड़े एग्रेसशन में थे। बड़े दिनों के बाद आपको गुस्से में देखा। पता नहीं, आपकी क्या सेटिंग हो गई और क्या मामला है? यहां पर यह कहा गया कि तानाशाह का नंगा नाच दिनांक 26 फरवरी, 2021 को इस परिसर में देखा गया। उस समय मैं आसन (अध्यक्ष महोदय के स्थान) पर बैठता था। संविधान के नियमों के अनुसार मैं यह कहना चाहता हूँ कि नियम 175 और 176, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, उसमें राज्यपाल महोदय प्रदेश की विधान सभा को संबोधित करने आ सकते हैं और आते भी हैं। जब वे आसन पर आए, उन्होंने संबोधित किया और वापस जा रहे थे तो बहुत से माननीय सदस्य—जो आज मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं और कुछ आए भी नहीं हैं—उन्होंने बाहर गेट नंबर-1 के ऊपर हाथापाई शुरू कर दी।...(व्यवधान) आप सभी थे आप।...(व्यवधान) गवर्नर साहब से...(व्यवधान)

**20.03.2026/1440/ए.एस.-एन.जी./2**

चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। उस समय रास्ता रोका गया, गाड़ी के आगे लेट गए, गाड़ी को जोर-जोर से मारने की कवायत शुरू कर दी। उनका परिवार उनके साथ था और अशोक चिन्ह के ऊपर पैर रख दिया गया। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं इतना कहना

चाहता हूँ कि तो क्या आपको कोई वीर चक्र दिया जाना चाहिए था? मैं किसी बड़े इनाम की बात नहीं करूँगा लेकिन क्या आप वीर चक्र के हकदार थे? यानि संवैधानिक व्यवस्थाओं में माननीय राज्यपाल के काफिले को रोकना, उनके वाहन के सामने बैठकर व लेटकर अवरुद्ध करना, उनके ए0डी0सी0 के साथ अभद्र व्यवहार करना, पुलिसकर्मियों को रोकना—यह लोकतंत्र की अपमानना थी।

अध्यक्ष महोदय, आप इस पूरे विधान सभा परिसर के नियंत्रक हैं। जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो निर्णय आपको ही लेना पड़ता है। उस समय पुलिस विभाग के माध्यम से एफ0आई0आर0 करवाई गई। क्योंकि राज्यपाल महोदय का रास्ता रोका गया और जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे थे, इस विधान सभा की सुरक्षा में लगे थे—उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। अब यह एफ0आई0आर0 क्यों हुई? मैं कहना चाहता हूँ कि धारा-186, धारा-353 और धारा-341 के तहत जब सरकारी कामों में रुकावट पैदा करने की कोशिश होती है तो पुलिस विभाग के माध्यम से इस प्रकार की एफ0आई0आर0 होती है और वही हुआ।...(व्यवधान) आपके लगभग 6—7 लोगों को निकाला गया। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है...(व्यवधान)

**उप-मुख्य मंत्री :** श्री विपिन सिंह परमार जी, आपने तो सरकार तोड़ दी थी और आप सब लोग जश्न मना रहे थे। श्री जय राम ठाकुर जी ने अनाउंस भी कर दिया था कि "खुदा भी नहीं बचा सकता", तब भी एफ0आई0आर0 नहीं हुई, आप क्या बात करते हैं

20.03.2026/1440/ए.एस.-एन.जी./3

**श्री विपिन सिंह परमार :** श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, चलो मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपके आसन से एक आदेश आता है और 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे और हम भी शामिल थे। उसके बाद हम बहाल हो गए। उसके बाद एक आदेश और पारित होता है।

श्री ए०पी० द्वारा.....जारी

20.03.2026/1445/ए.पी./डी.सी./01

श्री विपिन सिंह परमार जारी .....

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नौ विधायकों के खिलाफ एक शिकायत देते हैं कि इनके द्वारा परंपराओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं और लोकतंत्र का अपमान किया गया है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस पर सुनवाई कीजिए। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि जब नेता प्रतिपक्ष कल इस माननीय सदन में बोल रहे थे, तब कहा गया कि 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया और फिर बहाल भी किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन्हें बाहर भी निकाला जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रतिशोध की भावना से सदन नहीं चलता। यह किसी की जागीर नहीं है। डॉ० वाई.एस. परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को अपने हाथों से बनाया, माननीय राम लाल जी ने इसे सींचा, स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी ने इस प्रदेश को खूबसूरत बनाया, उसके बाद सम्माननीय शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी और श्री जय राम ठाकुर जी आए। लेकिन प्रतिशोध की भावना में यह कहना कि मैं देखता हूँ, कहना उचित नहीं है। खैर हम कानून में विश्वास रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फैसला करना होगा वह गुण-दोष के आधार पर कीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि कानून सभी के लिए है और उसी कानून के अनुसार हम व्यवहार करेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कुछ विधायक यह भी कह रहे हैं कि :

**दम है तुझमे कितना, वो समाज ने देख लिया है, हमने भी देख लिया है।**

**दम है तेरे दामन में कितना, देख लिया है, देखेंगे।**

इस सदन में प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। यह अपने उन लोगों को डरा सकते हैं। मुख्य मंत्री जी के पास सब कामों की कुंजी हो सकती है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से अपमानित करना और धोखा देना निंदनीय है। हमारे चाचा जी (कृषि मंत्री को कहते हुए) ने यहां पर एक बात का जिक्र किया है कि आजकल एस०आई०आर० (मतदाता

सूची का संशोधन) चल रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी होता रहा है। आप तो बड़े पुराने राजनीतिक हैं। यह वर्ष 1952 से चली आ रही है। जब यू0पी0ए0 की सरकार थी तब से चली हुई थी और आज भी एस0आई0आर0 हो रही है। इसमें कोई

**20.03.2026/1445/ए.पी./डी.सी./02**

नई बात तो नहीं है। इसमें 18 साल के मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाता है, मृतकों को हटाया जाता है और स्थानांतरित लोगों को अपडेट किया जाता है। इसलिए इस पर हल्ला मचाना उचित नहीं है। इसके साथ ही कहते हैं कि हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मुझे तो इस बात का भी पता नहीं लग रहा कि आपको वी0बी0-जी0राम0जी0 बिल के नाम से इतनी घृणा क्यों हो रही है। यह तो आपको भी पता है कि जब मरने के बाद कन्धों पर जाते हैं तो राम का नाम ही बोलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत के लिए रोजगार गारंटी योजना भी महत्वपूर्ण है। यह सारी बातें इसलिए मैं इस माननीय सदन में रख रहा हूँ। इसके साथ ही (\*\*\*)मुख्य मंत्री जी ने अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कहा कि जब हैदराबाद में सम्मेलन हुआ तो उन्होंने वहां पर कहा कि वे उस प्रदेश से आए हैं जहां 97-98 प्रतिशत लोग हिंदू रहते हैं। नेताओं को इतना खुश मत करो। उनका विजन क्या है? आपके विचारधारा की ताकत और शक्ति हो सकती है, पर लीडरशिप कैसी है यह मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेताओं के चक्कर में नहीं, आप अपने पक्ष को केंद्रीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री जी,

(\*\*\*)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

**20.03.2026/1450 /AT/DC /01**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी...**

माननीय होम मिनिस्टर साहब के पास, जगत प्रकाश नड्डा जी के पास, सांसदों के पास और मुख्य मंत्री एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, परंतु कहीं पर झुककर भी चलना पड़ता है। निमंत्रण भी देना पड़ता है, बुलाना भी पड़ता है और झुककर उनके दरवाजे पर जाना भी पड़ता है। उनका क्या जाएगा परन्तु आपका तो सब कुछ चला जाएगा। और जब सब कुछ चला जाएगा तो बाद में लोग याद करते हैं। मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान) अभी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 मिनट हुए हैं, बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा।

यह बात मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि वी०बी०-जी० राम जी० के बारे में और धारा-356 के बारे में यहां पर बड़ी उपलब्धियां बताई जा रही थी। यहां धगवार मिल्क प्लांट का जिक्र किया जा रहा था कि इतने-इतने 100 करोड़ रुपये आए लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है माननीय मंत्री महोदय।

हमारे छोटे भाई श्री केवल सिंह पठानिया जी कह रहे हैं अगर आपकी मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत चलती है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था करवाओ। 30 करोड़ रुपये क्यों नहीं देते शिक्षा मंत्री महोदय? यहां जिप लाइन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन मैक्लोडगंज में लग रही है लेकिन मुझे जो उत्तर आया है उसमें जिक्र किया गया है कि वहां कोई जिप लाइन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार की ओर से 196 केंद्र पोषित योजनाओं का पैसा यहां आ रहा है उन योजनाओं के लिए धन्यवाद अवश्य किया जाना चाहिए।

मुझे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के संदर्भ में यह कहना पड़ा क्योंकि उस समय मैं इस आसन पर बैठा हुआ था और आप यहां विपक्ष में थे जबकि श्री जय राम जी पक्ष में थे। उस समय की घटना आज भी मेरी आंखों के सामने चरितार्थ होती है। मुझे लगता है कि उसका जिक्र लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है ... (व्यवधान) और लोटस ऑपरेशन के

**20.03.2026/1450 /AT/DC /02**

बारे में मैंने कहा मियां-बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। यहां मियां-बीवी राजी थे और कुछ अन्य लोग भी राजी थे। बड़े मित्र हैं जो राजी हैं। परंतु प्रभु के चरणों में ताजे फूल ही चढ़ाए जाते हैं। प्रभु जिसको देखकर प्रसन्न हो, अब ये फूल कैसे मुरझाए हुए हैं और अब इन फूलों की कदर कहीं नहीं होगी यही मैं कहना चाहता हूं।

एक अच्छी भावना से माननीय गवर्नर साहब ने अपनी बात रखी ... (व्यवधान) रखेंगे भी कैसे क्योंकि वे मजबूर थे। आपके आधे-अधूरे मंत्रिमंडल ने इस अभिभाषण को तैयार किया था जो सवा तीन सालों में पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं बना सके ... (व्यवधान)

**Speaker :** Conclude please.

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय को पूरा दिन बैठना पड़ता है क्योंकि डिप्टी स्पीकर भी नहीं बना सके। तो वह अभिभाषण कैसा होगा? इनका हर काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है लेकिन आपके चरण कहां है? चरण ही नहीं मिले।

मैं वेटेरनरी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। जिनके पास यह विभाग है वे कह रहे हैं कि नियुक्तियां चरणबद्ध तरीके से होंगी। यह भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि यह सत्र भी चरणबद्ध तरीके से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति बहुत अच्छे थे। आज दूसरे राज्य के राज्यपाल बन गए हैं परंतु उनका भी अपमान करने की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जब भी मौका मिला समाचार पत्रों में उनके खिलाफ बोला गया जैसे कि बहुत बड़ी बहादुरी कर रहे हैं। किसको खुश कर रहे थे ... (व्यवधान) अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण का मैं किसी भी सूरत में समर्थन नहीं कर सकता। और यह भी कहना चाहता हूं कि अब जो कुछ समय बचा है, अगर उसे अच्छा निकालना चाहते हैं तो विपक्ष की भी राय लिया करो। यहां अनुभवी लोग हैं जोकि अच्छी सलाह देंगे। वहां की सलाह अवसरवादी होगी और काम के लिए होगी है, लेकिन यहां की सलाह हिमाचल प्रदेश को बेहतर, खूबसूरत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया। आपका धन्यवाद।

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....**

20.03.2026/1455/केएस/एचके/1

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी भाग लेंगे।

**श्री चंद्र शेखर :** अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मेरे सहयोगी श्री सुरेश कुमार जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लाया है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण में बहुत लम्बी चर्चाएं, बहुत से वक्तव्य, लम्बे भाषण हुए हैं और पैरा 3 से ले कर 16 तक का जो विशेषतौर पर बताया गया है, जिसकी राज्यपाल महोदय ने कोई चर्चा ना करके पढ़ा हुआ समझा जाए, कहा है। यह पहली बार हुआ है कि हम इस पीढ़ी के लोग इस तरह का समय, सरकार का जहां पर विज्ञान, सरकार का जहां पर कार्यक्रम, सरकार का जो उद्घोष है उसको माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में प्रतिबिम्बित किया जाता है लेकिन मजबूरी क्या थी? मजबूरी राजनीतिक नज़र आती है क्योंकि वे दूसरे राज्य में चले गए हैं और यहां से किसी भी तरह का विवाद आगे नहीं ले जाना चाहते होंगे। इस वजह से जिस दौराहे पर आज हिमाचल प्रदेश खड़ा है और जो मौजूदा सरकार का प्रदेश की जनता को बताने का नैतिक कर्तव्य बनता है, मुख्य मंत्री जी द्वारा इस राज्यपाल अभिभाषण से पहले भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाया गया था। एक प्रेजेंटेशन हुई जिसमें सभी विधायकों को सभी मंत्रियों तथा ऑफिसर्स को बुलाया गया तथा विशेष परिस्थितियां जो हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी हुई हैं, जिसमें हमें आ0डी0जी0 के तौर पर जो लगभग 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह वित्तायोग की तरफ से लगा और उसको पूर्णतः ज़ीरो पर लाया गया, उस संदर्भ में आज यह सदन अभिभाषण के बहाने फिर बातचीत कर रहा है।

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए)

सभापति महोदय, दुख इस बात का है कि जिस केंद्र सरकार की पैरवी यहां सामने से हो रही है, कहीं पर भी संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि केंद्र में सरकार है। उल्लेख यह है कि यह यूनियन गवर्नमेंट है जो कि विभिन्न राज्यों के हकों को ले कर, विभिन्न राज्यों

की रिप्रेजेंटेशन को ले कर संविधान में आवश्यक समय पर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संसद में एकत्रित होती है तथा उन सभी राज्यों को

**20.03.2026/1455/केएस/एचके/2**

पूरी तरह से पोषित करती है। जो संघीय ढांचा है वह इसी तरह से कार्य करता है। आज केंद्र ने जिस तरह की इकोनॉमी को डिज़ाइन किया है ये जो आर0डी0जी0 बंद हुई, उससे इस डिज़ाइन को और ज्यादा देखने का मौका मिला है। डिज़ाइन यह है कि इसको यूनियन की बजाय केंद्र समझा जाए और केंद्र को भी एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए। पूरे भारत का पूरा राजस्व एक जगह पर लाया जाए और उसको अपनी भाषा में बांटा जाए और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसका इस्तेमाल हो। हम अकेले नहीं हैं। 17 और राज्य हैं लेकिन हर राज्य की अपनी दास्तां है, अपनी प्रायोरिटी है। आज जिन राज्यों के बूते, जिन राज्यों की आड़ में यह नया आर0डी0जी0 का फॉर्मूला जिसमें हमें पूरी तरह से जीरो पर लाया गया है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**20.03.2026/1500/av/hk/1**

**श्री चंद्र शेखर-----जारी**

इनमें तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य हो सकते हैं जिनका जी0डी0पी0 में बहुत अच्छा योगदान है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्व0 डॉ0 यशवन्त सिंह परमार और अन्य फोरफादर्ज ने जिस हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना की थी वह राजस्व के हिसाब से नहीं की गई थी। हम विशेष दर्जे के राज्यों की श्रेणी में आते थे और हमारे लिए जो अब निर्णय लिए जा रहे हैं उनसे हमारे यहां पर बिल्कुल उलटी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जिस दिन से इस प्रदेश में सत्ता में आए, उसके बारे में माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार ने भी ठीक कहा कि हमारी सरकार ने तीन तरह की आपदाएं झेली हैं। जिसमें दो प्राकृतिक थीं जोकि अभूतपूर्व थी क्योंकि इससे पहले यहां पर कभी भी इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आईं जिसमें 12-15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान

हुआ हो। तीसरी यहां पर राजनैतिक आपदा आई जिसको हमारी पीढ़ी ने इसी सदन के अंदर देखा है।

वित्तायोग अनुच्छेद 275(a) के अंतर्गत क्या सिफारिश कर रहा था? वह हमारे ऑडिट को देख रहा था और हमारे फिस्कल व रेवेन्यू गैप को व्यू कर रहा था। उसके द्वारा जो सिफारिशें की गईं, यह जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार उनको मानें। यह केंद्र सरकार के विवेक के ऊपर था परंतु जिस प्रकार से सिफारिशें की गईं और केंद्र सरकार ने उनको लागू करने की प्रतिबद्धता दिखाई उससे एक बात साफ है कि केंद्र सरकार यह मन बना चुकी थी और वही धोखा आज सामने वाले पक्ष ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। इनको 15 वें वित्तायोग में यह पता लग गया था कि हमें वित्तायोग मैक्सिमम हाइट पर ले जा रहा है। अगर वित्तायोग 70 हजार करोड़ रुपये पर ले जा रहा है और इसको यह तुरंत बंद करेगा तो इसका मतलब था कि सामने वाले नेतृत्व को दिल्ली से यह सिग्नल आ चुका था कि यह बंद होने जा रही है इसलिए अब आप चुप रहिए। वही चुप्पी अब दिख भी रही है। इस चुप्पी की आड़ में अब ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर अब नुकसान हो जाए।

सभापति महोदय, 13 वें वित्तायोग के समय में राज्यों को टोटल टैक्स पूल का 89 प्रतिशत मिलता था। 14वें वित्तायोग के दौरान राज्यों को टोटल टैक्स पूल का

**20.03.2026/1500/av/hk/2**

82 प्रतिशत मिलता था। 15वें वित्तायोग में 78 प्रतिशत मिलता था और 16वें वित्तायोग में हम अब 41 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब हमें केवलमात्र दो हैड्ज से पैसा दिया जाएगा। जिसमें एक डैवोल्यूशन हैड की वजह से 2388 करोड़ रुपये का दिख रहा है तथा दूसरा एक्स्ट्रा ग्रांट जिसमें आपदा भी है, उसके हिसाब से 539 करोड़ रुपये मिलाकर यह कुल 2980 करोड़ रुपये बनते हैं। हमें जो एक वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में मिलते थे अब उसमें केवल एक वार्षिक या पंचवर्षीय घटक के रूप में मात्र 5,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। दूसरी तरफ हैवी स्टेट्स को इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनको इसके अंदर लगभग 10-10 प्रतिशत का फायदा देखने को मिल रहा है। इससे

संवधान के द्वारा बनाए गए वित्तायोग की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। क्या वह भी चुनाव आयोग की तरह कठपुतली बनकर रह गया है या उसने आंकलन करना बंद कर दिया है? उसने प्रदेश में धरातल पर जाकर वहां की परिस्थितियों को समझे बिना एक फ्लैट फॉर्मूला लगा दिया। मजेदार बात तो यह हो रही है कि जिस वक्त दुनिया में युद्ध चल रहा है और हम तेल के पैमाने के आधार पर युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। यह दुनिया इंटरनेट क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। जबकि भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे तथा इमरजेंसी सिचुएशन के नाम पर टोटल टैक्स पूल में 5 प्रतिशत की कटौती कर रही है और इसी आधार पर अब हमें 41 प्रतिशत पर लाया जा रहा है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमें इससे क्या नुकसान होगा। हमें इससे प्रदेश में मनरेगा जैसी योजनाओं को चलाने का नुकसान हो रहा है। मनरेगा जैसी योजनाएं प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र में चल रही है। प्रदेश के 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों के अंदर जो तीन सूत्रीय कार्यक्रम लाए गए हैं कि अब प्रदेश सरकार किसी भी प्रस्तावित ग्राम सभा के द्वारा कार्यों का निपटारा नहीं करेगी।

**टी सी द्वारा जारी**

**20.03.2026/1505/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**श्री चंद्र शेखर ... जारी**

बल्कि इनका निपटारा केंद्र सरकार करेगी।

दूसरी बात, जो सीधा लाभ महिलाओं को दिहाड़ी के आधार पर दिया जाता था, अब उसका आंकलन मौसमी आधार पर किया जाएगा। मौसम का आंकलन दिल्ली में बैठे लोग कैसे करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि बरसात कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई। यह निर्णय भी दिल्ली में बैठकर लिया जाएगा।

मनरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था लेकिन 16 तारीख को रात के 1:30 बजे संसद के अंदर इस नाम को वापिस लिया गया। दिन के उजाले में महात्मा गांधी का नाम वापिस लेने की हिम्मत नहीं हुई। यह देश देख रहा है कि जो महत्वकांक्षी योजनाएं डॉ० मनमोहन सिंह जी के समय में लाई गई थी जिनसे देश की

आर्थिक तरक्की होती, गरीब वर्ग की पर्चेजिंग पावर बढ़ती, इण्डस्ट्रियल सैक्टर पर प्रभाव पड़ता और रोजगार के अवसर पैदा होते, उन योजनाओं की कमर तोड़ दी गई है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी 6 बार दिल्ली गए और 6 की 6 बार न फाइनेंस मिनिस्टर और न फाइनेंस कमीशन ने उन्हें मिलने का समय दिया। क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को आप मुख्य मंत्री नहीं मानते। क्या आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री का सम्मान नहीं करते? अगर आपको इस तरह का धोखा देना था, इस तरह का व्यवहार करना था तो पहले ही बता देते। यह जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है, यह जो बातचीत में कमी आई है और अंधेरे में निर्णय लिए जा रहे हैं, इस तरह देश नहीं चलता। आपने रातों-रात सोनम वांगचुक को उठाया गया और 4 दिन पहले उसको बिना पूरी सुनवाई के छोड़ दिया। आपको अपनी गलती समझ आ गई कि लद्दाख जैसे महत्वकांक्षी केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय नेता के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। अब उन्हें रिहा किया गया जिसका हम स्वागत करते हैं। आज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का सबसे बड़ा प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा। सामने बैठे विपक्ष के माननीय सदस्य मौन हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में आएगा, लेकिन जनता का आने वाले वर्षों में क्या हाल होगा, इस पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि जो 10 हजार करोड़ रुपये हमें नहीं

### **20.03.2026/1505/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

मिले उसका किन-किन पर असर पड़ेगा। इसका प्रभाव स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा। इसका असर सामाजिक दायित्वों पर पड़ेगा जैसे विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि पर इसका असर दिखेगा। उसका असर बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली बस सुविधाओं पर भी पड़ेगा। एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर के प्रमोशन के लिए जो बजट आता है, उस पर असर पड़ेगा। मनरेगा जैसी योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर असर पड़ेगा जिसकी मांग हर विधायक अपने क्षेत्र के लिए करता है। प्रश्न काल के समय सदन में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेकों डिमाण्डें विधायकों की तरफ से अपने क्षेत्र के आधार पर आती हैं और भविष्य में भी आएंगी लेकिन आपको जो स्पोर्ट आती थी वह नहीं मिलेगी। आज सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग 12 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। भारत सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत चाय बनाने को

भी स्टार्टअप योजना के तहत लिया जा रहा है। लेकिन कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने बी०सी०ए० और बी०टेक करने वाले युवा आज रोजगार के इंतजार में हैं। आप भविष्य की ओर बढ़ने के बजाय प्रदेश को पीछे की ओर धकेला जा रहा है। सभापति महोदय, विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है और उसका जीवंत उदाहरण आज माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। हमें पॉपुलेशन, एरिया और फॉरेस्ट कवर के आधार पर जो ग्रांट मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। वर्ष 1980 के बाद से हमारे फॉरेस्ट कवर को ध्यान में रखते हुए जो क्वालिफिकेशन बनती थी, उसे नजरअंदाज किया गया।

एन०एस० द्वारा .... जारी

20-3-2026/1510/NS-YK/1

श्री चंद्र शेखर -----जारी

हमें अफ़सोस है कि हमारे बार-बार कहने के बावजूद भी उन सब बातों को नजरअंदाज किया गया। आज हालत यह है कि हमें आज ऐसे वक्त में बोलना पड़ रहा है जिनके हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 2 से 3 प्रतिशत वोट कम हैं। आधी आबादी का जो प्रतीक हमारा विपक्ष है वह मौन है और चुप है। वे इस मुद्दे से स्किप करना चाहता है। वह चाहता है कि इसके ऊपर चर्चा ही न हो और इसके ऊपर कोई बात ही न हो। विपक्ष चाहता है कि इस प्रदेश को स्कीमों के नाम पर पैकेज आएँ जिस तरह से अब भारत सरकार काम कर रही है। बिहार का चुनाव हुआ तो लगभग 1,000 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये चुनाव आयोग की घोषणा के बाद डाला गया। अभी असम का चुनाव घोषित हुआ तो परसों ही 9,000 रुपये प्रति महिला राशि वहां डाली गई। इस देश में इस तरह की पिछ-लगू राज्य सरकारें भी हैं। जो देश के लिए शहीद हुए और जिन्होंने इस मुल्ख को अपनी जवानियां दीं तो क्या उन्होंने यह सोचा था कि ऐसी यूनियन गवर्नमेंट होगी जो अपनी शर्तों के ऊपर प्रदेश को कटोरे देगी तथा चुनाव को जीता कर अपने पीछे एक ऐसी फौज खड़ी करेगी जो हां से हां करे तथा न करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी? यही हालत इस वक्त हमारे

सामने वाले लोगों की है। आज मेरे विधायक मित्र कह रहे थे कि शिवा प्रोजैक्ट दिल्ली सरकार का है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह प्रोजैक्ट दिल्ली सरकार का नहीं है। यह प्रोजैक्ट जनवरी 2023 से दिसम्बर 2028 तक का प्रोजैक्ट है और इसके ऊपर राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम चल रहा है तथा मैं भी उसमें भागीदार हूँ। इसमें लगभग 1290 करोड़ रुपये प्रदेश की सरकार को मिले हैं जिसमें प्रदेश की सरकार ने 262 करोड़ रुपये अपने डालने हैं। उसी तरह एप्पल इकोनॉमी को ग्री करने के लिए यूनिवर्सल कार्टन जैसी योजनाएं मुख्य मंत्री जी लेकर आए हैं। आलू के प्रसाधन के लिए मुख्य मंत्री जी ने अलग से पैसा दिया। यहां पर कल कहा जा रहा है कि हल्दी मात्र 61 क्विंटल आई है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी मुख्य मंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर काम कर रहे हैं और 48 विधान सभा क्षेत्रों के अंदर सक्सैसफुल तरीके से हल्दी के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें जिला सिरमौर सबसे अग्रणी है। इसमें विशेषकर पांवटा साहिब अग्रणी है। इसमें फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र बेहतरीन काम कर रहा है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व मण्डी में

20-3-2026/1510/NS-YK/2

उस किसान के लिए 90 रुपये मूल्य सोचा गया जो किसान कभी भी एम0एस0पी0 के बारे में नहीं जानता था और एम0एस0पी0 को नहीं समझता था। मुख्य मंत्री जी ने उसको मौका दिया और यह इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अतिरिक्त दूध में ऐतिहासिक तौर पर एम0एस0पी0 मिल्क प्रोडक्शन से हमें मिली है। हैल्थ में रिफॉर्म्स आए हैं। मेडिकल तथा आदर्श अस्पताल आने वाले समय में अपनी कहानी अपने आप लिखेंगे। एजुकेशनल सेक्टर में सी0बी0एस0ई0 स्कूलों की वजह से एक नई क्रांति आई है। प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है जिससे सरकार का बेहतरीन कार्य इसी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में नजर आ रहा है। हायर एजुकेशन में इस वक्त नई डायरेक्शन की जरूरत है ताकि हम जो पढ़े-लिखे नौजवान खड़े कर रहे हैं वे ए0आई0 और ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ पाएं। दुनिया के अंदर जो इण्डस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है तो क्या हिमाचल प्रदेश का नौजवान भी उसमें अपनी कदमताल कर पाएगा? ये मौलिक प्रश्न इस वक्त हमारी सरकार के समक्ष हैं। मैं मानता हूँ कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जरूर कड़वे फैसले हुए हैं

लेकिन उन कड़वे फैसले को लिए बिना ओपीएस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत हमने लागू की है तो उन जैसी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते थे।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह कहा जा रहा है कि नौकरियां कहां दी जा रही हैं? एक अति महत्वपूर्ण कार्य मुख्य मंत्री जी की रहनुमाई में हुआ कि सर्विस सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर को भंग किया गया। उसमें 17 एफआईआरज हुई हैं और विजिलेंस के द्वारा हुई हैं। उस वक्त जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा था तो इस वक्त लगभग 850 बच्चे माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में जद्दोजहद कर रहे हैं।

आरकेएस द्वारा -----जारी

20.03.2026/1515/RKS/AG-1

श्री चंद्र शेखर जारी...

मौजूदा समय में TGT Medical, साढ़े तीन सौ, TGT Non Medical, चार सौ, Arts के साढ़े पांच सौ, JBT के बारह सौ, पटवारी के 645, Assistant Nurses लगभग एक हजार, CBSE स्कूलों के लिए जो इस वक्त अध्यापकों की भर्ती होनी है उसमें लगभग आठ सौ, JE Civil, Radiographer और Paramedical Staff इत्यादि की जो सारी वैकेंसिज है वह अगले 6 महीनों के भीतर भरी जा रही है। इससे पहले स्पेशल डॉक्टर पौने पांच सौ, रेगुलर डॉक्टर 164, पैरा-मेडिकल स्टाफ 200 और 722 भर्तियां स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई हैं। आज तक सीम, इंतकाल और निशानदेही के केस हजारों की तादाद में लंबित हैं। इसलिए जो आज आप कह रहे हैं कि दिशा तय नहीं हुई है उसके लिए आधार खड़ा हो चुका है। यह आधार अढ़ाई से तीन सालों में खड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में हम इस क्राइसिस से पार पाएंगे। हमने डिजास्टर और राजनीतिक आपदा में पार पाया है। अब क्लाइमेट चेंज चल रहा है और इसके लिए हमारे दोनों पक्षों के परामर्श व समावेशी विचार से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की जनता

इस सदन की तरफ देख रही है लेकिन यहां मात्र ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है जिससे हमारे बेरोजगारों व महिलाओं को दिशा नहीं मिल पाएगी। हमें इन चीजों को पूरा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार।

20.03.2026/1515/RKS/AG-2

**सभापति :** अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री सतपाल सिंह सत्ती :** सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो 16 फरवरी, 2026 को इस माननीय सदन के अंदर अभिभाषण दिया था, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हूँ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति हमारा पूरा सम्मान है लेकिन जिस तरह की बातें या जिस तरह के विषय माननीय राज्यपाल द्वारा इस सदन के अंदर रखे गए या उन विषयों के ऊपर सरकार ने अपना विचार उनके माध्यम से जनता के सामने रखवाने की कोशिश की उसके विपरीत यह सरकार काम कर रही है। अगर हम पेज नम्बर-7 पर जाएंगे तो उसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वास्थ्य के बारे में कहा है। पेज नम्बर-7 में लिखा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं और अस्पतालों में नई मशीनरी आ रही हैं। नई मशीनों को खरीदने के लिए तो जोर दिया जा रहा है परंतु उनको चलाने के लिए हमारे पास डॉक्टरों उपलब्ध नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। जब हमने इसके बारे में डॉक्टरों से बात की तो हमारे ध्यान में आया कि इसके लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वे डॉक्टरों को नहीं दी जा रही हैं। मैंने अलग-अलग जगह इस विषय पर डॉक्टरों से बात की है। ठीक है, अच्छी चीजें आनी भी चाहिए मगर उसके लिए सुविधा भी तो होनी चाहिए। अगर हमारे लोगों का इलाज बिना चीरा लगाए हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे संज्ञान में यह बात आ रही है कि इसके माध्यम से इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी ने कहा है कि रोबोटिक सर्जरी पर कितना खर्च आएगा यह देखने की बात है। रोबोटिक सर्जरी के लिए जो उपकरण या सामान खरीदना पड़ेगा उससे मुझे लगता है कि 6-7 व्यक्तियों का मुफ्त में ओपेशन हो

सकता है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ओपेशन करवाने में लगभग 1.20 लाख रुपये को सामान आता है और यह हर मरीज को लाना पड़ेगा। अगर यह सामान सरकार देती है तो क्या सरकार इतना मंहगा सामान देने के काबिल है?

20.03.2026/1515/RKS/AG-3

अगर उस मरीज को ही कहा जाए कि भाई साहब आप 1.20 लाख रुपये का सामान ले आओ तो वह कहेगा मेरा ओपेशन बिना रोबोटिक सर्जरी के ही कर दो। जो डॉक्टर ओपेशन करते हैं उसमें हो सकता है कि किसी ओपेशन में ज्यादा खर्च आ जाए लेकिन छोटे ओपेशन के लिए तो 3-4 हजार रुपये का सामान ही लगता है।

श्री बी०एस० द्वारा जारी.....

20.03.2025/1520/बी.एस./ए.जी.-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

डॉक्टर का कहना है कि चीरफाड़ से जो ऑपरेशन होता है, हमें उसके लिए जो सामान चाहिए वह भी नहीं आ रहा है। यह मैं आपको आई०जी०एम०सी० की रिपोर्ट बता रहा हूं। वहां के डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है, सर्जन ने जो रिपोर्ट दी है। मैं आप से एक साल पुरानी बात कर रहा हूं जिस समय रोबोटिक-रोबोटिक की बात शुरू हुई थी।

सभापति महोदय, दूसरा, ध्यान में यह आया है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने हिम केयर योजना शुरू की थी। केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना केंद्र से शुरू की थी। लेकिन आज उन दोनों योजनाओं की क्या स्थिति है? यह हम लोगों के ध्यान में अखबारों के माध्यम से समय-समय पर आता रहता है। लगभग 6 महीने पहले चम्बा से एक न्यूज़ लगी थी। लगभग एक वर्ष ही हो गया है। इसमें लिखा है कि हिम केयर से नहीं मिला सामान बलियां रखनी पड़ी गिर्वी, महिलाओं को इलाज के लिए अपनी बलियां बेचनी पड़ रही हैं। यह सब अखबारों के अंदर की कटिंगज हैं। आदरणीय विवेक जी यहां नहीं हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र से दिनेश कुमार, सुखदेव सिंह, लिदकोट एक गांव है वहां से बार-बार

फोन आता है कि भाई साहब मैं बैड पर पड़ा हूँ पौने दो लाख रुपये का मेरा पी0जी0आई0 का बिल है लेकिन मेरे घर के अंदर कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं आगे का इलाज नहीं करवा सकता। यह पौने दो लाख रुपये भी मैंने अपने रिश्तेदारों से लिया है। लेकिन आज तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है। इस व्यक्ति की महिला ने फिर मेरे से बातचीत की उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं घर-बार छोड़ करके लुधियाना के अंदर प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने को मजबूर हो गई हूँ। मेरा घर वाला घर के अंदर है, क्योंकि बैड के ऊपर है। मैंने रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं और आज तक यह पैसे मेरे को नहीं आए हैं। आप कल्पना करो, हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है। इनकी आयुष्मान भारत योजना तो लगभग फेल हो गई है। हिम केयर के मेडिकल बिल लोगों के नहीं आ रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से हम लोग जाएंगे तो अलग-अलग लोग बार-बार हम लोगों को फोन करते हैं। यहां

20.03.2025/1520/बी.एस./ए.जी.-2

बार-बार बोला जाता है कि मित्रों की भर्ती बहुत ज्यादा हो रही है। रोगी मित्र, पशु मित्र, वन मित्र और बिजली मित्र। स्वास्थ्य में भी कहते हैं कि 500 रोगी मित्रों की भर्ती होगी। ऐसे मित्रों की बहुत बड़ी भर्ती हो रही है। उन भर्तियों में क्या हो रहा है? मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन टेक्निकल व्यक्ति हेल्थ के अंदर रखें। यह मित्रों की सरकार है, आपने ठीक कहा।

सभापति महोदय, हेल्थ के क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल नुकसान किया है। गवर्नर महोदय के अभिभाषण के माध्यम से बड़ी प्रशंसा की गई है। इसलिए उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि यह पढ़ने योग्य ही नहीं है। मुख्य मंत्री जी बार-बार बोलते हैं कि मेरी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न समाजिक और आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर रखी गई है। उसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऊना जिला की यह न्यूज़ है कि महिलाओं की उम्मीद पर फिरा पानी, मात्र एक बार मिली इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। इसमें 80 हजार

महिलाओं ने आवेदन किया था। मात्र 7280 को मिला पैसा, वह भी एक किस्ता। यह पंजाब केसरी की फ्रंट न्यूज़ है और साथ में पत्रकार लिखते हैं, कार्यालयों में धूल फांक रहे हैं फार्म। इनके कार्यकर्ताओं ने भाग-भाग करके भरे थे जिस कारण हम लोग सत्ता से बाहर हुए। हमारी भी कई महिला थी, जिन्होंने आपको वोट डाल दिया। वे कहती हैं 1500 लगने दो बाद में एम0पी0 के वोट मोदी जी को डाल देंगे। लेकिन उनको भी आज तक नहीं यह पैसा लगा है।

सभापति महोदय, डिसेबिलिटी के बारे में पेज नंबर 13 पर कहा गया है कि हमारी सरकार दिव्यांगजनों के समग्र विकास के उत्थान के लिए एक असीम योजना चला रही है। हमारे सुखविंदर सिंह, दिव्यांग व्यक्ति है। मुख्य मंत्री जी के जिला से है, भोरंज तहसील है। राजन कुमार जी, बाघंटू गांव से हैं उनका कहना यह है कि मेरे पास यूनिक डिसेबिलिटी आई0डी0 कार्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब कहते हैं कि हिमाचल गवर्नमेंट ने हम लोगों को हिम बस कार्ड बनाने के लिए फिर से बोल दिया

20.03.2025/1520/बी.एस./ए.जी.-3

है, जिसमें चार-पांच सौ रुपये लग रहा है और पिछले 10 महीने से उसने कहा, मेरे को सहारा योजना अंतर्गत जो जयराम ठाकुर जी ने सहारा योजना लगाई थी, 3,000 रुपये लोगों को देते थे। 10 महीने से कहते, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है और मैं बेड के ऊपर पड़ा हूं। 100 प्रतिशत उसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है और अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए दिव्यांग लोगों से भी हिम कार्ड बनवाना शुरू कर दिया। अब वह कहता कि मैं 100 प्रतिशत हूं, तो मैं वहां पर कैसे जाऊंगा

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**20.03.2026/1525/DT/AS-1**

**श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...**

100 प्रतिशत उसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। सरकार ने पैसा इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से सक्षम लोगों से भी हिमकार्ड बनावाना शुरू कर दिया। अब वह व्यक्ति कह

रहा कि जब मैं 100 प्रतिशत डिसऐबल्ड हूँ तो मैं वहाँ पर कैसे जाऊंगा? मैं लोक मित्र केंद्र में कैसे पहुंच पाऊंगा? मुझे कौन लेकर जायेगा? इस व्यक्ति का फोन नंबर भी मेरे पास है, इसका नंबर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी दूंगा। वह खुद भी उससे बात कर लें। ऐसी योजनाएं बनाओं इसका सुझाव आपको कौन से अधिकारी देते हैं?

इसी प्रकार श्री गुरुदेव जी भी हैं जो देहलां गांव से संबंधित रखते हैं और यह गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने मुझे तब से फोन करना शुरू कर दिया जब सातवें महीने में भी उनको पेंशन नहीं आई थी। अब हो सकता है कि उनको भी दस महीने पूरे हो गये हों क्योंकि यह तीन-चार महीने पुरानी बात है। वह कह रहे हैं कि मेरी सहारा योजना की पेंशन ही नहीं आ रही। मैं पुरी तरह से बेड रिडन हूँ।

शगुन योजना के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सैंकड़ों महिलाएं को इस योजना के अंतर्गत जो पैसे आने थे वह अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं जबकि उनका विवाह हुए एक साल या डेढ़ साल हो चुका है। पक्ष के हमारे साथियों से भी लोग इस संदर्भ में बात करते होंगे। क्योंकि किसी को भी इस योजना का पैसा नहीं मिल रहा।

इसी तरह से राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है। इस योजना की स्थिति यह हो गई है कि जिन लोग ने सरकार को सामान दिया है उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अब सरकार उनसे और सामान खरीदने से इंकार कर रही है। सरकार कह रही है कि अब आपसे ज्यादा सामान हम नहीं खरीदेंगे।

अगर हम पेज संख्या 19 पर देखें तो उसमें दुग्ध प्रोत्साहन योजना का उल्लेख है। इस योजना में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों से दुध खरीदने का एक रेट फिक्स किया गया था। इसमें गाय का दुध 51 रुपये प्रति लीटर व भैंस का दुध 61 प्रति लीटर खरीदे जाने की बात कही गई है। हमें आज भी सैंकड़ों लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि सरकार हम से दुध नहीं खरीद रही। ऊना के अंदर लोगों के द्वार प्रदर्शन भी किया गया क्योंकि सरकार ने उनसे जो दुध खरीदा उसका पिछले तीन महीने का पैसा अभी उन्हें नहीं मिला है और

**20.03.2026/1525/DT/AS-2**

यही नहीं सरकार ने उनसे अब दुध खरीदने से भी इंकार कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि सरकार की योजना को देखते हुए हमने गाय और भैंसों खरीदी थी। यह सरकार की किसानों को मजबूत करने के लिए एक अच्छी स्कीम है और लोगों को यह योजना अच्छी लगी इसीलिए उन्होंने पशु खरीदे। लेकिन सरकार कह रही है कि हम एक किसान से केवल 20 लीटर दुध ही खरीदेंगे। जिसके पास ज्यादा दुध है वह आदमी उस दुध का क्या करेगा? वह दुध किसको देगा, क्योंकि सरकार की योजना को देखते हुए ही उसने पशु खरीदे हैं। लोग ने इसके लिए प्रदर्शन किया है, अखबारों की कटिंग्स हमारे पास पड़ी है। सरकार कह रही है कि दुग्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हम प्रदेश के लोगों की आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं, पर लोग तो प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

वर्तमान सरकार इस बात को एक अचीवमेंट मान रही है कि हमने टॉल-टैक्स बेरियर के रेट बढ़ायें हैं। 1 73 करोड़ 89 लाख रुपये के हिमाचल प्रदेश के टॉल-टैक्स बेरियर बिके। सरकार इसको भी उपलब्धि मान रही है। हिमाचल में लगभग 33 टॉल-टैक्स बेरियर हैं और इनमें से 11 टॉल-टैक्स बेरियर जिला ऊना में हैं। ऊना के लोगों को मेहतपुर से नंगल रोज आना जाना पड़ता है। नंगल में ए0एफ0एल0 है, वहां पर बी0बी0एम0बी0 है, इसके अतिरिक्त हमारी रिश्तेदारियां भी पंजाब में है। पहले अगर ऊना से किरतपुर को जाना होता था तो 600 या 700 रुपये में टेक्सी मिल जाती थी। यदि आपने आंनदपुर या माता नैनादेवी में माथा टेकने जाना होता था तो 1000 रुपये की टेक्सी मिल जाती थी। लेकिन अब टेक्सी वाले को टॉल-टैक्स का 320 रुपये देना पड़ता है और पहले जिस टेक्सी का किराया 700 रुपये देना पड़ता था अब लोगों को 1020 रुपये देना पड़ रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति मेहतपुर से अपने घर आता है या अपने रिश्तेदारों से मिलने आता है तो उसको अब वहां आने के 170 रुपये देने पड़ेंगे। पूर्व सरकार के समय केवल 40 रुपये लिए जाते थे। पूर्व सरकार ने हिमाचल नंबर की गाड़ी का प्रवेश शुल्क बंद कर दिया था। वर्तमान सरकार ने अब उस का चार्ज बढ़ाकर सीधे 170 रुपये कर दिया है। इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। मैं आने वाली अपनी सरकार से और अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि यह होना ही नहीं चाहिए। मान लिया कि हमारा टॉल-टैक्स माफ है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी के आगे पहले से सही दस गाड़ियां और लाइन में लगी होती हैं जो अन्य

प्रदेशों की हैं। तब हिमाचल प्रदेश की नंबर वाली गाड़ी को 10-15 मिनट तो उस बेरियर में लग ही जाते हैं। यह कोई 40 रुपये की लड़ाई थोड़ी है। हिमाचल नंबर का

**20.03.2026/1525/DT/AS-3**

ट्रक 45 डिग्री के तापमान में जब बदी-बरोटीवाला के बेरियर में खड़ा होता है तो पसीने से उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ट्रक, बस या टैपों में तो ए0सी0 नहीं लगा होता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो टेक्स है वह हिमाचल प्रदेश की पूरी 75 लाख की जनसंख्या में लगाना चाहिए। वर्तमान सरकार ने बार्डर एरियाज के क्षेत्रों पर सारा टेक्स लगा दिया। कल भी ऊना में वहां के व्यापार प्रकोष्ठ और अन्य संस्थाओं ने प्रदर्शन किया और शायद 31 तारीख को वह धरना भी दे रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से और टॉल-टेक्स लगाना शुरू हो जायेगा। इसलिए टॉल-टेक्स जो आपने बढ़ाया है यह ठीक नहीं किया। मैंने इससे संबंधित रिकार्ड देखा। इस रिकार्ड में मैंने देखा कि कई ठेकेदार ऐसे हैं जो हर बार ठेका लेते हैं लेकिन जितने की बोली उन्होंने दी होती है उसका 40 प्रतिशत भी वे जमा नहीं करवाते। हर बार नई कंपनी बनाते हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**20.03.2026/1530/ए.एस.-एन.जी./1**

**श्री सतपाल सिंह सत्ती..... जारी**

और नई कम्पनी बना कर अधिकारियों से मिलकर फिर से ठेका ले लेते हैं। आप लोग इस प्रकार का रिकॉर्ड चैक कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 173 करोड़ रुपये नहीं आएंगे। उनको पहले से पता है कि किस तरह से ठेका लेना है। ये सारी छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन लोगों को तंग करती हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या-32 में कहा गया कि सरकार द्वारा 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' लागू की गई है। श्री राजीव गांधी जी ने वहां आकर क्या करना है? आपके नेताओं ने सारे जंगल तो काट दिए हैं। (किसी अखबार की कतरन दिखाते हुए) ऊना के अंदर देखो, हिमाचल से पंजाब

में 30 ट्रक लकड़ी की तस्करी। यह गोभी के ट्रक नहीं हैं और न मटर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए तीस ट्रक (किसी अखबार की कतरन दिखाते हुए), श्री चंद्र कुमार जी, आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं और कल्पना करो कि 30 ट्रक कितने होते हैं? कहां है, गार्ड? कहां है, आरओ? कहां है, डीओ? कैसे काटे गए, 30 ट्रक? ये एक दिन की कहानी नहीं है, यह रोज़ की कहानी है। (किसी अखबार की कतरन दिखाते हुए) देखो, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, छोटे ट्रक नहीं हैं। यहां से श्री चंद्र शेखर जी बाहर चले गए, वे हमारे पुराने साथी हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम के साथी हैं और वे एसओआई के स्टेट प्रेसिडेंट होते थे। आज तो वे श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे लेकिन उस समय श्री वीरभद्र सिंह जी को कैंपस में भी नहीं घुसने देते थे। एसओआई वालों ने तो कांग्रेस वालों (एनएसयूआई छात्रों) का मर्डर भी कर दिया था। आज तो श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के गुण गा रहे हैं, अच्छी बात है, गाना चाहिए क्योंकि वे उनकी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन जब हम उनके विधान सभा क्षेत्र के अंदर गए, श्री राजेश धर्माणी साहब और सभापति महोदय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी लकड़ी तो आजकल डिपो के अंदर नहीं होती जितनी बहरी और बरोट गांवों के अंदर हमने देखी।

### **20.03.2026/1530/ए.एस.-एन.जी./2**

वहां पर लगभग 10,000 गाड़ियां होंगी। वहां पर लेटेस्ट जेसीबी से मिट्टी के अंदर लकड़ी दबाई गई और व्यास नदी के अंदर लकड़ी की फोटो श्री जय राम ठाकुर जी ने कल दिखाई है। कोई एमएलए है या कोई कुछ और है लेकिन इतनी निर्दयता से काम मत करो। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि बड़े लीडर ऐसे लोगों को स्पोर्ट क्यों करते हैं? यह मेरे दिमाग से बाहर की बात है। किसी पार्टी को सत्ता के अंदर लाना, क्या किसी एक आदमी की औकात है? अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बीजेपी का ही नुकसान कर रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उससे कोई लाभ नहीं होता और उन चीजों से भुगतना सबको पड़ता है। लकड़ी एक काट रहा है और आप सब लोग सुन

रहे हैं। हमारा व्यक्ति गलत करेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री इतने कमजोर होते हैं कि एक व्यक्ति को शैल्टर देना उनकी मजबूरी हो जाती है? फिर ऐसा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के लायक ही नहीं है। मुख्य मंत्री जी को तो कान से पकड़ कर पूछना चाहिए कि तूने ये कैसे किया? कोई भी गवर्नमेंट आती है, वह किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं आती। आपके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की होगी, धरने दिए होंगे, जुलूस निकाले होंगे, रैलियां की होंगी, डोर-टू-डोर गए होंगे, बूथ लगाए होंगे, वोट डलवाए होंगे, तब कांग्रेस सत्ता में आई। किसी एक लीडर के कहने से कांग्रेस नहीं आई और कल को बीजेपी आएगी तो तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण आएगी, चंद नेताओं के कहने से नहीं आएगी। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको सख्ती से काम लेना चाहिए। आप लोग लकड़ी के बारे में बोल रहे हैं। यहां पर एंटी-चिट्टा के बारे में सुबह काफी बातचीत हो गई है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अगर पुलिस के लोग भी उसमें संलिप्त मिल रहे हैं। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आपकी राजनीति बड़ी लंबी है। अभी आप केवल 35 साल के हैं जिस कारण आपकी बहुत लंबी राजनीति है। यहां पर बैठे बहुत से लोगों की लंबी राजनीति है। हमारे यूनिवर्सिटी फैलो की तो 5-10 साल की ही होगी, पता नहीं किसी की बीच में कट जाए तो कट जाए। आप लोगों को देखना है कि हिमाचल प्रदेश को कैसे चलाना है।

**20.03.2026/1530/ए.एस.-एन.जी./3**

ये चिट्टे वाले लोगों के कारण 22-22 साल के बच्चे मर रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे मर रहे हैं। एक बच्चा तीन दिन से गायब था, चौथे दिन उसकी डेड बॉडी बाथरूम के अंदर मिली। वह केवल 18 साल का था। आप कल्पना करो, ये बेईमान लोग कहां तक पहुंच गए हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूं लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया, जिस समय डी0जी0पी0 और उनके साथ एक पट्टा-सा गले में डाल करके बैठे थे, पुलिस के लोग ऐसे-ऐसे हाथ मार रहे थे और हंस रहे थे। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आपकी पुलिस के लोग पकड़े जा रहे

हैं। पुलिस के सारे लोग बेईमान नहीं हैं। आप लोग सोच-समझकर लोगों को लगाओ। चाहे वह बीजेपी के हों या कांग्रेस के, जो काम करके दे सकता है, उसी को लगाना चाहिए।

ऐसे ही एक और योजना है, राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख-कल्याण योजना। आप लोग नेताओं के नाम से योजना चला रहे हो तो लोगों को सुख तो दो। सभापति महोदय, इस योजना के तहत सब दुकानदारों के लाइसेंस बन रहे हैं, चाहे वह 20 रुपये की बीड़ी ही क्यों न बेचता हो, उसके लिए भी 500/- रुपये का लाइसेंस बन रहा है। हर करियाना वाले का लाइसेंस बन रहा है। छोटे-छोटे दुकानदारों के लाइसेंस बन रहे हैं। आपने कुछ लाभ देने के लिए किया होगा लेकिन श्री राजीव गांधी जी की आत्मा को भी शांति मिलनी चाहिए। वे इस देश के बड़े लोकप्रिय नेता थे। उनके समय में ही सबसे ज्यादा सीटें जीती गई थीं। आज तक किसी को उतनी नहीं मिलीं। आप उनके नाम पर योजना चला रहे हो और लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। इस तरह से इसके अंदर जितना भी लिखा गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने करुणामूलक आधार पर लोगों को नौकरी देने की बात की थी। हमारे दोस्त श्री रोहित ठाकुर जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब-कमेटी भी बनाई गई। श्री रोहित ठाकुर जी ने एक चिट्ठा भी दे दिया है। उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है?

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

20.03.2026/1535/ए.पी./डी.सी./01

**श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी .....**

हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास इसके लिए कमेटी भी बनी थी। एक चिट्ठी उन्होंने दे भी दी है, लेकिन उस पत्र में क्या लिखा है, वह पॉलिसी बाहर क्यों नहीं आ रही। माननीय मुख्य मंत्री जी उस पॉलिसी को मान क्यों नहीं रहे हैं? करुणामूलक आधार पर नौकरी लेने के लिए लाखों बेरोजगार युवक धरना दे रहे हैं, उस पॉलिसी को सार्वजनिक करो। सभापति महोदय, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। हमें अगर कोई काम करने को बोलेगा तो हम

कह देंगे कि विपक्ष में कोई काम नहीं हो रहा। हम तो दो मिनट में बच जाएंगे। अगर ज़्यादा ही है तो थोड़ा सरकार के विरोध में भी बोल देते हैं। आपकी तो करुणामूलक आधार पर नौकरी वालों ने जान खा ली होगी। हमारा भी यही हाल था, लेकिन माननीय श्री जय राम ठाकुर जी के समय में उन्होंने 1800 करुणामूलक लोगों को नौकरियां दी थी। लेकिन इस सरकार के समय में मुझे नहीं लगता कि 18 लोगों को भी नौकरी मिली होगी। इसी तरह अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून एवं व्यवस्था देखें, यह मेरा अंतिम विषय है। अगर आप देखेंगे तो चिट्टा, वन कटान आदि सभी विषय कानून एवं व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। सरकार का सबसे बड़ा काम लोगों को सुरक्षा देना होता है, बाकी काम तो हम अपने आप कर लेंगे। हम बिज़नेस और मेहनत दोनों कर लेंगे। अगर आम जनता की सुरक्षा ही नहीं है तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। जो सरकार अपनी जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, उस सरकार से नालायक कोई सरकार हो ही नहीं सकती। देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर और प्रदेश के अंदर सुरक्षा पहुंचाना सरकार का काम है। मैं इन परिस्थितियों को आपके ध्यान में ला रहा हूँ और मैंने इन परिस्थितियों के बारे में कई बार बोला है। हमारे मैहतपुर के अंदर एक एस0आई0यू0 टीम ने रात के 3:30 बजे 5 लाख 47 हजार रुपये एक दुकान से बरामद किए, जो लोग वहाँ पर लॉटरी खेल रहे थे और वह कांग्रेस के एक पदाधिकारी की दुकान है। उस आदमी ने कहा कि हमारे 10 लाख रुपये पुलिस की टोली खा गई जब उन्होंने हमारे ऊपर रेड की और उन्होंने उसकी बात को माना और उस पुलिस की टीम को भंग कर दिया। क्या एक चोर आदमी के कहने पर पुलिस की टीम को भंग कर सकते हैं? क्या उस पुलिस अफसर ने 3:30 बजे रेड पैसे खाने के लिए की होगी? इसके बाद दो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और से आया हुआ मिलिट्री से आया वह डी.एस.पी. था वह फतेहपुर से था उसको रिकांग

**20.03.2026/1535/ए.पी./डी.सी./02**

पियो में डी.एस.पी. लगा दिया। जो 11 लोग पंजाब से आकर मैहतपुर में लॉटरी खेल रहे थे, अब पता नहीं वे अपने साथ चिट्टा या भुक्की लेकर आए होंगे या हथियार बेचने आए होंगे। वे लोग या तो फगवाड़ा, जालंधर, रूपनगर, रोपड़, आनंदपुर साहिब या कोई नंगल के होंगे। अब आप कल्पना करो कि उनकी चिंता नहीं कि अपनी पुलिस की टोली को भंग कर दिया गया। दूसरा विषय यह है कि ऊना में एक व्यवसायी से 5 करोड़ रुपये की फिरौती दिनांक

4 नवंबर, 2025 को माँगी गई। उससे पहले भी लोगों से फिरौतियाँ माँगी गई हैं। सभापति महोदय, इस विषय पर हमने कई बार धरना भी दिया है और कहा कि अच्छे अधिकारियों को लगाया जाए, अच्छे डी.एस.पी., पुलिस कर्मी और एंटी करप्शन सेल, एस.आई.यू. के अंदर अच्छे अधिकारियों को लगाया जाए। लेकिन कुछ नहीं किया गया और हमने 12 नवंबर, 2025 को डी.सी. को मेमोरेंडम भी दिया और पिछले बजट में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला था कि ऊना में गैंगवार होगा। भगवान करे ऐसा न हो लेकिन अगर हुआ तो मैं आपसे पूछूँगा। लेकिन 19 नवंबर को आपके पूर्व विधायक के होटल के अंदर पैसों की बंदरबाँट के चक्कर में दो गुटों की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक आदमी की बाजू तोड़ी गई और उसके बाद बाहर जा कर एक अन्य आदमी को गोली मार दी गई। और दूसरे गुट के लोगों ने सामने वाले गुट पर दराटी से हमला किया और काट दिया। आज ऊना के अंदर लगभग 15-16 परिवारों के बच्चे धारा 302 व 307 में फँस गए हैं। उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। यह सब उसके होटल में हुआ है। ऊना में अनेक होटल हैं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। वहाँ इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर आवारा, डॉन टाइप, ठग और डग टाइप के लोगों की रोज पार्टियाँ होती हैं। रोज वहाँ पर पैसों की बंदरबाँट के चक्कर में लड़ाई हो गई और उसी के चक्कर में व्यक्ति की मौत हो गई। कल्पना करो, आज ऊना के दुकानदार 7 से 8 बजे तक अपनी-अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं। दो महीने तक तो दुकानें सूर्यास्त होने से पहले बंद कर दी गई। घर वाले भी फोन करके कहते थे कि दुकान बंद करके घर पर आ जाओ। यह परिस्थितियाँ ऊना के अंदर कानून एवं व्यवस्था की हैं। पिछले कल की अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो एक गणेशन पेट्रोल पंप है अंब रोड पर। पिछले कल 4:53 मिनट पर शायद पंजाब के दो लोग थे। उन्होंने पेट्रोल भरवाया, जब उनसे पैसे माँगे तो उन्होंने कहा कि दूँ मैं तेरको पैसे, हटदा की नी मोरे ते। वह बेचारा आगे को हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस बंदे ने जब पुलिस को रिपोर्ट दी तो पुलिसवालों ने कहा कि तेरे ऊपर केस बनेगा। पिछले कल

जारी ए0टी0 द्वारा---

**20.03.2026/1540 /AT/DC /01**

**श्री सतपाल सिंह सती जारी...**

तो पुलिस वालों ने कहा कि तेरे ऊपर केस कैसे बनेगा। पिछले कल ऑंकार, जो वहां का रहने वाला है और पेट्रोल पंप का मालिक है, उसे साथ जाना पड़ा। तब जाकर पुलिस वालों ने FIR दर्ज की, वरना तब तक FIR दर्ज नहीं की गई। क्यों? क्या वे तुम्हारी बुआ के लड़के लगते हैं, जो वहां पेट्रोल डालकर चले गए? कम-से-कम FIR तो दर्ज करो, उसकी जांच तो करो। वहां कैमरे लगे हैं, उन्हें देखो, ढूंढो कि वह व्यक्ति कौन है? लेकिन उनके पास कट्टा था, पिस्तौल थी, जो भी उन्होंने दिखाया, वह दिखाकर चले गए। उल्टा उसे कहा गया कि तेरा 200 रुपये का पेट्रोल था, तू क्यों ऐसे पंगे में पड़ रहा है? उल्टा तेरे ऊपर ही केस बन जाएगा। अब स्कूटर में 200 लीटर पेट्रोल तो भरा नहीं जा सकता। दूसरा मामला तीन दिन पहले हुआ, एक ब्लेस माइंड करके हमारे वहां एक अस्पताल है। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी के पास भी यह न्यूज हो। वहां पर एक माइंड ब्लेस अस्पताल है उस अस्पताल के डॉक्टर से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। और पुलिस के पास मिलकर उसने बताया कि जिन्होंने मांगा था पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की गई, तो जब वह 10 लाख रुपये देने गया, तब पुलिस ने नंगल से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आप कल्पना करो हिम्मत कैसे हो रही है 5 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये मांगने की? और ऊना के अंदर यह सब क्यों हो रहा है? लोग किसका नाम लेते हैं? लॉर्ड बिश्नोई का मैं आदमी हूं। लेकिन लॉर्ड बिश्नोई को शायद पता भी नहीं होगा। ये छोटे-छोटे लोग उसका नाम लेकर अपना धंधा चला रहे हैं। अब तो वह आदमी भी पकड़ा गया। लोकल लोगों को भी लगा कि जब इस पुलिस के अंदर और एक पूर्व विधायक के होटल के अंदर जब ये धंधे हो सकते हैं, उसके माइनिंग माफिया के लोग वहां पर करोड़ों रुपये कमा सकते हैं, तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? उन्होंने भी धंधे शुरू कर दिए कहते हैं मैं फलां बोल रहा हूं, मैं कनाडा से बोल रहा हूं। जो हमारे मित्र कनाडा में हैं, उनके नंबर से फोन आता है तो आदमी डर जाता है। पूरा एड्रेस उनके पास होता है। जैसे विनोद कुमार, पेट्रोल पंप बंगाना में उसे भी डराया गया था। माननीय सदस्य श्री विवेक जी को पता होगा। क्या हमने एक भी आदमी ऐसा पकड़ा? क्या एक भी आदमी

**20.03.2026/1540 /AT/DC /02**

को सख्त सजा दी? ऊना के अंदर कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है। मैं पिछले 3 सालों से यह बात कह रहा हूँ। हमें भी लोग कहते हैं कि मत बोला करो, तुम्हारा भी नंबर लगा देंगे। लेकिन हमारा धर्म बनता है कि जहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा होना। इसलिए, सभापति महोदय, हम बार-बार कहते हैं कि अच्छे अधिकारी लगाओ और अच्छे लीडर के ऊपर हाथ रखो। ऐसे मत हेलिकॉप्टर में टके-टके लोगों को घुमाते रहो। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुखू जी उन्हें छोड़ने चले गए ऊना के अंदर जहाज लेकर के। कहते कि मौसम खराब था हमीरपुर में इसलिए मुझे जहाज ऊना में उतारना पड़ा। अगर मौसम खराब था, तो कांग्रेस के 15 कार्यकर्ता पहले कैसे पहुंच गए वहां पर? उन्हें पहले से पता था कि बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री जी यहां आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष भी वहां था, माननीय सदस्य श्री विवेक जी का भी फोटो था, और अन्य दो-चार लोगों के भी फोटो थे। हेलिकॉप्टर 2 मिनट में घूम जाता अगर बिलासपुर चला तो हमीरपुर में उतर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 5-10 कार्यकर्ता पहले पहुंच जाएं तो कैसे होता है। इतने भी कमजोर मत हो कि जिनके होटलों के अंदर बंदे मर रहे हैं और आवारा किस्म के लोग घूम रहे हैं। आपके इलेक्शन के भी वह प्रभारी थे। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुझसे कहा यह तुम्हारा आदमी है कैसे? मैंने कहा कि बंदा तो ठीक है। मेरा ही नाम राशिया है। तो वह कह रहा था कि वह वहां पर क्या कर रहा था, कुछ समान बगेरा वहां पर बांटना था। और लोगों को बोल रहा था कि आपको कितनी पेटियां चाहिए 10, लिखो 10 पेटियां। मैंने उसे दूर जाकर फोन किया और कहा पागल, तेरी वीडियो बन जाएगी, तूने चुनाव हरा देना हमें, अंदर कमरे में जाकर लोगों से शांति से मिलो और उनसे पूछ की क्या चाहिए आपको और क्या नहीं चाहिए आपको। ऐसे तो आपके चुनाव प्रभारी थे? कोई और अच्छा प्रभारी नहीं मिला क्या? धर्माणी जी और विक्रमादित्य और बबलू नहीं अच्छा लगा क्या? क्या इस तरह के चुनाव प्रभारी होते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि कम-से-कम ठीक पोस्चर तो हम लोग दें। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ उनके विरोध में कि वे मेरे प्रतिद्वंदी हैं। सभापति महोदय, उस गांव के लोगों ने तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया कहा कि वह पैसे खा रहा है और जमीन बड़े लोगों के नाम कर रहा है। उन्होंने शहर में प्रदर्शन किया, DC को ज्ञापन दिया और हाई कोर्ट के अंदर केस किया होगा। मैं तो 300 वोट से हारता हूँ, क्योंकि वह उनका गांव है और सब लोग अपने MLA को वोट देते हैं। लेकिन इस बार उसी गांव के लोगों ने विरोध

20.03.2026/1540 /AT/DC /03

किया और पूर्व विधायक से मिलने भी नहीं गए। जिस तहसीलदार की मैं बात कर रहा था, उसे तीन बार एक्सटेंशन दी गई। उसने गरीब लोगों की जमीनें अपने नाम लिखवा ली और लिखवाकर आदरणीय सुक्खू जी कहते हैं कि हमने उसको हटा दिया। लेकिन वह अपना काम तो कर गया। अब लोग SDO, डिवीजनल कमिश्नर और हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। सभापति महोदय, इन सब बातों का व्याख्यान

**श्रीमती के०एस० द्वारा जारी .....**

20.03.2026/1545/केएस/एचके/1

**श्री सतपाल सिंह सती जारी ---**

सभापति महोदय, इन सभी बातों का व्याख्यान भी इस किताब के अंदर होना चाहिए था। राज्यपाल महोदय को जो गलत हो रहा है वह भी और जो ठीक हो रहा है, वह भी लिखकर दो। दोनों का बैलेंस होना चाहिए क्योंकि राज्यपाल महोदय का बहुत सम्मानजनक पद होता है, संवैधानिक पद होता है। उनको जो लिखकर दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। जो भी मैंने बोला है, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को तथ्य चाहिए होंगे तो मैं तथ्यों सहित प्रस्तुत कर दूंगा। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

20.03.2026/1545/केएस/एचके/2

**सभापति :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे।

**श्री आशीष बुटेल :** सभापति महोदय, 16 फरवरी, 2026 को जो माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण हुआ और श्री सुरेश कुमार और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी द्वारा इस प्रस्ताव पर धन्यवाद जाहिर करने के लिए जो संकल्प आया है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, यह 50 पन्नों का अभिभाषण था और केवल 2 या 3 मिनट में खत्म हो गया। यह पहली बार नहीं है जो ऐसा हुआ है। मुझे ध्यान है कि पिछली विधान सभा का भी मैं सदस्य था, उस समय भी जो यहां पर चर्चा हुई कि उस समय एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी, वह किस तरह से हुई थी वह तो सभी जानते हैं लेकिन उस समय भी अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा गया था। ... (व्यवधान) जय राम ठाकुर जी, यह मैं आपके समय की बात कर रहा हूं जब पिछली बार मैं विधान सभा का सदस्य था। जब कल्याण सिंह जी अभिभाषण पढ़ कर गए थे उस समय मेरे पिताजी थे। ... (व्यवधान) माना कि वे अस्वस्थ थे, कोई भी कारण रहा होगा लेकिन पूरा तो नहीं पढ़ा था। महोदय, विपक्ष अपने प्रत्येक भाषण में एक ही बात कह रहा है कि इस अभिभाषण को इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय को यह ठीक नहीं लगा।

सभापति महोदय, मैं इनसे एक गुज़ारिश करना चाहूंगा कि एक बार फिर से वापिस जाएं, ई-विधान के माध्यम से जो आप लोगों ने हमें सुविधा दी है, गवर्नर साहब जो उस आसन से बोलकर गए, वह भी इस पर मौजूद है और मैं कोट भी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पैरा संख्या 3 से ले कर पैरा संख्या 16 तक संवैधानिक संस्था के संदर्भ में टिप्पणियां हैं जिन पर निश्चित रूप से आप सभी गौर करेंगे और मैं नहीं समझता कि मुझे इन्हें पढ़ना चाहिए। आपने यह तो सोच लिया कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता मुझे यह पढ़ना चाहिए लेकिन आप उनकी यह बात नहीं मान रहे हैं कि गौर आप लोगों को भी करना पड़ेगा जो उस संस्था के बारे में वहां पर लिखा है। यह राज्यपाल महोदय के शब्द हैं। उसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा झूठ है? आप एक बात बताएं कि क्या 16वें वित्तायोग का गठन नहीं हुआ। क्या ऐसा नहीं हुआ कि उनकी टीम यहां पर सबको मिलने आई? क्या ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश

### 20.03.2026/1545/केएस/एचके/3

सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स से वे मिले? क्या ऐसा नहीं हुआ कि देश के इतिहास में पहली बार आर0डी0जी0 को बंद किया गया है, क्या यह झूठ है? ... (व्यवधान) 17 हों या 18 राज्य हों लेकिन सबसे पहले आपको यह बात जाननी पड़ेगी कि वर्ष 1952 से लेकर आज तक आर0डी0जी0 बंद नहीं हुई थी। आप लोगों ने उसको बंद किया है। ... (व्यवधान)

क्या जो बाकी 17 राज्य थे, वे भी नहीं चला पा रहे थे? आपकी जहां सरकारें थीं, इसका मतलब तो यह है कि वे भी नहीं चला पा रहे थे।

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि जब राज्यपाल महोदय ने यह कहा और जब उन्होंने दो टिप्पणियां वहां पर कीं, एक तो जो मैंने पैराग्राफ 3 से 16 तक के बारे में कहा। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि पैरा संख्या 17 से ले कर आगे तक सरकार की अभी तक की उपलब्धियों का वर्णन है। यह आप सभी के लिए अच्छा होगा कि आप इन्हें पूरी तरह से पढ़ें। आप उनकी ये बात भी नहीं मानते। उन्होंने इसलिए आपको कहा क्योंकि कहीं परेशानी ना हो जाए। जब वे पूरा अभिभाषण पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि यह कैसे हो गया?

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी ---

20.03.2026/1550/av/yk/1

**श्री आशीष बुटेल -----जारी**

आपने हमारे लिए इतना मुश्किल काम कर दिया, आपने आर०डी०जी० बंद कर दी। केंद्र से पैसा आना बंद हो गया और उसके बावजूद प्रदेश सरकार यहां पर काम कर रही है। ... (व्यवधान) फिर उसके 20 दिनों के बाद यहां से राज्यपाल महोदय का स्थानांतरण भी हो गया। हम तो बहुत खुश हैं और अगर वे पूरे अभिभाषण को पढ़ देते तो शायद इससे भी बड़ी स्टेट मिल जाती। उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा इसीलिए उनको हमारे से थोड़ी-सी बड़ी स्टेट तेलंगाना मिली है। ... (व्यवधान) जी, काँग्रेस पार्टी की सरकार वाली स्टेट मिली। यहां पर जो आदरणीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में काम हुए वे सारे विपरीत परिस्थितियों में हुए हैं। ... (व्यवधान) हमारी सरकार आज भी कर रही है और आगे भी इसी प्रकार से करती रहेगी। मैं इसको विपरीत परिस्थितियां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने रोकने के लिए हर प्रकार की कोशिशें कर लीं। आपने केंद्र से पैसा देना बंद करवा दिया तथा आर०डी०जी० को बंद करवा दिया। हमारे लिए टैक्स की कम्पनसेशन बंद हो चुकी है। ... (व्यवधान) अब तो श्राप देना ही बचता है बाकी तो आप सब कुछ कर ही चुके हैं। आप ऑपरेशन लॉट्स तक करवा चुके हैं। ... (व्यवधान) हां, आप हमें भगवान के भरोसे भी छोड़

चुके हैं क्योंकि आप ऑपरेशन लॉट्स के दौरान यहां तक कह चुके हैं कि 'भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा पाएगी'। लेकिन मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि भगवान हमारे साथ हैं।

सभापति महोदय, यहां पर आपदा का आना एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा था। हमारी इस सरकार के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष आपदा आई है। हालांकि उस पर किसी का जोर नहीं था। उस पर न केंद्र सरकार का जोर था और न ही हिमाचल प्रदेश सरकार का था, जैसा होना था वैसा हुआ और उसमें हमारे सैंकड़ों लोग मारे गए। हम आज आपदा से प्रभावित विस्थापितों को दोबारा रीहैबिलिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उसमें भी आपको दर्द हो जाता है। अगर हम यह कहते हैं कि इस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आप हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलिए, आप लोग तब भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होते। आप लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है। लेकिन कहां कर रही है, आप मुझे यह बताइए? हिमाचल प्रदेश हमारे भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है।

**20.03.2026/1550/av/yk/1**

अगर केंद्र सरकार हमारी इतनी-सी भी मदद नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि वह हमारे से एक प्रकार से यह कह रही है कि तुम हमारा अंग ही नहीं हो।

सभापति महोदय, विपक्ष के लोग जो बार-बार इतरा रहे हैं कि केंद्र से इतना-इतना पैसा आ गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर जिस प्रकार की आपदा आई क्या उस हिसाब से पैसा आया? माननीय प्रधानमंत्री यहां पर 1500 करोड़ रुपये की अनाउंसमेंट करके जाते हैं परंतु हमें वह पैसा आज दिन तक नहीं मिला। उसमें किसका दोष है, यह आप खुद बताइए? फिर आप कहते हैं कि इस अभिभाषण में सारी स्कीम्ज भारत सरकार की हैं और हम भारत सरकार का धन्यवाद नहीं करते। क्या सब कुछ भारत सरकार ही कर रही है? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, भारत सरकार वहां से आपको स्कीम भेजती है परंतु उसका कुछ अंश हिमाचल प्रदेश की सरकार भी देती है तब जाकर यहां पर वह स्कीम लागू होती है। उसमें प्रदेश सरकार का चाहे 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत या 50 प्रतिशत हिस्सा हो परंतु प्रत्येक योजना के अंतर्गत हमारी राज्य सरकार पैसा देती है उसके बाद केंद्र

सरकार की स्कीम्ज को यहां पर लागू किया जाता है। वैसे भी बार-बार कौन धन्यवाद करता है, एक बार कर दिया तो हो गया। मेरे दिल में अपने पिताजी के लिए बहुत आदर है परंतु मैं उनको रोज़ इस बात का तो धन्यवाद नहीं करता कि मुझे प्रत्येक दिन दो चपाती मिल रही हैं। आप क्या हरेक बुरकी खाते हुए उनको धन्यवाद करते रहते हैं?

सभापति महोदय, मुझे यहां पर एक बात याद आ रही है और मैं आपकी अनुमति से उसको यहां पर कहना चाहता हूं। एक बार एक बहुत ही कंजूस पिता होता है। उसका बच्चा बोलता है कि आप जो ये सुखी रोटियां देते हैं इस पर थोड़ा घी लगाकर दिया कीजिए। उसका पिता घर में आधा किलोग्राम घी का डब्बा लाकर रख देता है। उसका बेटा रोज़ अपनी रोटियां उस घी को लगाकर खाता रहता। एक महीने के बाद वह घी का डब्बा खत्म हो गया।

### **टी सी द्वारा जारी**

20.03.2026/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

### **श्री आशीष बुटेल ... जारी**

उसने फिर पापा से कहा कि घी खत्म हो गया है। पापा ने कहा कि घी थोड़ा कम लगाया करो और यह एक महीने में ही खत्म नहीं होना चाहिए। अगली बार जब घी का डब्बा खत्म हुआ तो वह एक साल के बाद खत्म हुआ। तब भी पापा ने कहा कि यह तो तुमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अब यह घी का डब्बा अलमारी में रहेगा, तुम रोटी लेकर जाओ और दूर से ही देखकर वापस आ जाया करो। वह आज्ञाकारी पुत्र रोज़ रोटी लेकर डब्बे के पास जाता और दूर से देखकर वापस आ जाता था तथा समझ लेता था कि रोटी पर घी लग गया। एक दिन पिता पीछे से आया और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले कि एक दिन तो घी खाने से बगैर रहा करो जबकि वह केवल देखकर ही वापस आ जाता था।

सभापति महोदय, यही हाल हमारे विपक्ष और केंद्र सरकार का है। जो पैसा वहां से भेजा जाता है, वह हमें यहां दिखाई ही नहीं देता कि वह कहां पर पड़ा है। कल यह भी जगजाहिर हो गया कि आपने (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) ऑपरेशन लोटस यहां पर

ट्राई किया था। वह किस आदमी ने कहा जिसके 32 दांत हैं और वह जो कहेगा वही सही होगा। कभी कहते हैं कि जहां कांग्रेस के लोग जाएंगे, उन्हें जूतों की माला पहनाई जाएगी। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। यहां भी माननीय सदस्य कई बार हिंसक हो जाते हैं। वे अपने नाम से गांधी हटा दे या अहिंसा की तरफ ध्यान दें। मैं कहना चाहता हूं कि केवल नाम में गांधी लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाते।

आज माननीय नेता प्रतिपक्ष ने शून्य काल में चर्चा शुरू की जिसमें कहा गया कि चिट्टे की रोकथाम के लिए सरकार कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ ही पुलिस की बात की गई जो चिट्टे में संलिप्त पाए गए। आप आंकड़े निकालिए और तुलना कीजिए कि आपकी सरकार के समय में कितना चिट्टा पकड़ा गया, हमारी सरकार में कितना पकड़ा गया और इसकी रोकथाम के लिए कितना बजट लगाया गया? हमने कई युवाओं की जिंदगी बचाई है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मुझे बोलने दें।

**Chairman** : Please, let him complete. उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। प्लीज ... (व्यवधान)

20.03.2026/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

**श्री आशीष बुटेल** : सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उसके बाद ये अपनी बात रख लें। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि चिट्टे में कोई संलिप्त पाया गया है और इन तक यह खबर पहुंची है तो वह इसलिए पहुंची है कि हमारी सरकार और हमारी पुलिस ने उन 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ा है जो इसमें शामिल थे। यदि हम यह कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई समस्या नहीं है तो आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए कि सरकार द्वारा अनेक युवा लड़के-लड़कियां इस जहर से बचाए जा रहे हैं। यहां माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि हमारे काम केंद्र सरकार की मर्जी से हो रहे हैं।

लेकिन केंद्र सरकार क्या दे रही है? ऐसा पैसा जो यहां आता है और फिर वापस खींच लिया जाता है।

सभापति महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय में जब केंद्र सरकार का कोई पैसा आता था तो वह इनके अकाउंट्स में जाता था और वहां से कुछ समय बाद अन्य कार्यों जैसे कर्मचारियों की सैलरी या अन्य हैड में वापिस चला जाता था

**एन0एस0 द्वारा .... जारी**

20-3-2026/1600/NS-YK/1

श्री आशीष बुटेल -----जारी

अब केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रदेश सरकार को जो भी पैसा आएगा वह उसी हैड में खर्च होगा और कहीं पर भी खर्च नहीं होगा। अगर हमें चार दिन के बाद केंद्र सरकार से कोई मदद भी आनी होती है तो जिस मद के लिए आएगी उसी पर खर्च करना है क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आप यह क्यों नहीं देखते कि इसमें बहुत सारे लोग और आप 28 विधायक भी शामिल हैं। आप कहते हैं कि काम नहीं हुए, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, यहां से माननीय विपिन सिंह परमार जी उठ कर बाहर चले गए हैं और मैं परमार जी का खुले मन से धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे और माननीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे तब इन्होंने पालमपुर अस्पताल की बहुत मदद की लेकिन फिर भी वहां जो कमियां थीं उनको हमने पूरा किया है। अभी कहा जा रहा था कि वहां पर डॉक्टर की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पालमपुर अस्पताल में आज डॉक्टर की कमी नहीं है। वहां पर हरेक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। उन्होंने एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट की बात की है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एनेस्थीसिया की डॉक्टर मातृत्व अवकाश पर गई हैं और उनकी जगह पर एक रिप्लेसमेंट हमें शीघ्र ही मिलने जा रही है। अगर आपको छोटी-छोटी बातों

की दिक्कत है तो हम उनका क्या कर सकते हैं? मैं आप सबके साथ यह खुशी सांझा करना चाहूंगा कि पूरे भारत वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केवल तीन अस्पताल चुने गए हैं जिनके अंदर टी0बी0 की रोकथाम और इरेडिकेशन की बात की गई है तो उन तीन अस्पतालों में पालमपुर का सिविल अस्पताल भी शामिल है। आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं क्योंकि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है इसलिए हमारा नाम भारत वर्ष के अग्रणी हेल्थ इंस्टीच्यूशनज में लिया जा रहा है।

सभापति महोदय, आज मैं बिना कैलकुलेशन के बोल रहा हूं और बहुत कंजरवेटिवली मैं यह बात कर रहा हूं कि आज पालमपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर कम-से-कम 1200 करोड़ रुपये के अलग-अलग काम चले हुए हैं। ये कम नहीं हैं। अगर हम पानी की आपूर्ति के काम देखें तो लगभग 400 करोड़ रुपये के वहां काम चले हुए हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो आज लगभग 300 करोड़ रुपये की सड़कें पालमपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन सालों में हम लेकर आए हैं। मैं यह दावे के

20-3-2026/1600/NS-YK/2

साथ कहता हूं और इसमें किसी को बुरा मनाने की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर आप मेन रोड्ज को टैली करें तो पालमपुर की सड़कें आपको फिट दिखाई देंगी (\*\*\*)जैसे यहां एक बार पहले भी कहा गया था।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बड़ा हल्ला और भाजपा से प्रायोजित एक कार्यक्रम प्रदेश में चल रहा है और वह स्मार्ट मीटर्ज का कार्यक्रम है। मैंने स्मार्ट मीटर्ज के बारे में प्रश्न भी लगाया है और उसमें पूछूंगा। विपक्ष को यह जानकारी है लेकिन विपक्ष यह जानकारी लोगों से छुपा रहा है। विपक्ष के मित्र अपनी जानकारी लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। स्मार्ट मीटर्ज जिसकी वजह से लोग आज परेशान हो रहे हैं वे केंद्र सरकार की आर0डी0एस0एस0 (Revamped Distribution Sector Scheme) स्कीम का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि आर0डी0एस0एस0 स्कीम के लिए जो पैसा है उसको ग्रांट माना जाएगा अगर आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे और लोन माना जाएगा अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्ष के मित्र केंद्र

सरकार के पास जाकर बात करेंगे कि यह जो क्लॉज है उसको हटाया जाए? आज जिस तरह से आपके द्वारा प्रायोजित लोगों को हमारे पास भेजा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। मैं इस माननीय सदन में बताना चाहता हूँ कि असलियत यह है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मेन्डेट दिया है।

सभापति महोदय, चाहे नोटबंदी हुई, चाहे कोरोना आया तो इन्होंने सबको लाइन में लगाया। हमेशा लाइनें लगीं और लोगों की मौतें हुईं। आज एक नई चीज़ देखने को मिल रही है

(\*\*\*)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

आर०के०एस० द्वारा -----जारी

20.03.2026/1605/RKS/AG-1

श्री आशीष बुटेल... जारी

लोगों को गैस सिलेंडर के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ रहा है। Petroleum Ministry भारत सरकार के अंडर ही है। अगर भारत सरकार इसकी आपूर्ति करने में विफल होंगी तब भी यह दिक्कत हमारे ही राज्य को आने वाली है। आप इसके ऊपर भी चर्चा करते तो अच्छा होता। आपने मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है। आपने इस योजना को बी०बी०जी०- रामजी का नाम दे दिया। आपने अच्छा किया लेकिन जो मेरे गांव में काम होना है, क्या उसे वहां बैठे केंद्रीय मंत्री तय करेंगे कि मेरे गांव में क्या काम होगा? जिस तरह से ग्राम सभा काम तय करती थी क्या अब उस तरह से केंद्र सरकार काम तय करेगी? यह बात आप अपने केंद्र के लोगों से पूछिए। हम हर क्षेत्र और हर community के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वह कृषि का क्षेत्र है या कोई और हमने हर क्षेत्र में काम किया

है। हमने किसानों की फसलों के लिए MSP तय की है। हमने पहली बार दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। हमने हल्दी का रेट 90 रुपये प्रति किलो किया है। अभी पीछे भाषणों में यह कहा गया कि हल्दी में बस इतना सा ही पैसा बढ़ाया गया। ऑर्गेनिक हल्दी की खेती पिछले वर्ष ही तो शुरू हुई है। जब इसकी फसल 90 रुपये प्रति किलो बिकेगी और किसानों की जेब में यह पैसा जाएगा तो इससे आपको क्या तकलीफ है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जब मैं इनके साथ सी0पी0एस0 था तो उस समय इन्होंने 6 हज़ार के करीब पक्की नौकरियां दी। यह 58 साल वाली पक्की नौकरी थी। ये 6 हज़ार की अग्निवीर की नौकरी नहीं थी। महोदय, मैं बहुत ज्यादा न कहता हुआ आपका धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका पूरजोर समर्थन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विपक्ष के साथियों को थोड़ी सद्बुद्धि दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

20.03.2026/1605/RKS/AG-2

**सभापति :** अब माननीय नेता प्रतिपक्ष इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री जय राम ठाकुर :** माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी ने अपनी बात कही है उसे हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि आप तुलना कर लो कि आपके समय और हमारे समय में कितना-कितना चिट्टा पकड़ा गया। हमारे समय में प्रदेश के अंदर बहुत कम चिट्टा लेकिन आज किलो के हिसाब से चिट्टा आ रहा है। आप किस तरह यह तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर चिट्टे की मात्रा आ रही है स्वाभाविक रूप से वह ज्यादा पकड़ा जाएगा। क्या आप इसको उपलब्धि मान रहे हैं? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के समय बोर्डर के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों में बहुत कम चिट्टा पहुंच पाया था। हमने इस चीज को बहुत टाइट किया था लेकिन आज चिट्टा दूर-दराज के इलाकों में भी

पहुंच गया है। आज प्रदेश में चिट्टे की सप्लाई कई गुना बढ़ गई है इसलिए स्वाभाविक रूप से चिट्टा ज्यादा मात्रा में पकड़ा जा रहा है। अगर आप इसको उपलब्धि मान रहे हैं तो मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है। इसलिए इसकी तुलना इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने अंत में यह कहा कि मनरेगा योजना को बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनरेगा योजना का सिर्फ नाम बदला है। अब इस योजना का नाम बी0बी0जी0-रामजी रखा गया है। मुझे लगता है कि आपको इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने मनरेगा में 30 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान रखा है। क्योंकि आप लोगों ने जो विकास के कार्य किये हैं उनकी पेमेंट लंबित है। इसके अलावा बी0बी0जी0-रामजी योजना में 95 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 125 दिन तक रोजगार देने का प्रावधान है। यहां पर मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में बहुत कम बैठते हैं। उनके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स पड़े हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

20.03.2025/1610/बी.एस./ए.जी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

बहुत सारे असाइनमेंट है, शायद इनके आज कोई बड़े नेता आए हैं। उनको रिसीव करने के लिए चले गए हैं। जब जिस विषय पर इनको जवाब देना चाहिए, मुख्य मंत्री जी को हाउस नहीं छोड़ना चाहिए। कायदे से तो यही बनता था, लेकिन वे नहीं रहते हैं। अब जब नहीं रहते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं?

मैं जो बात कह रहा हूं कि कितनी योजनाएं बंद कर दी, आपने जनमंच बंद कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया, सरकार गांव के द्वारा, ऐसा कुछ नाम रख दिया। हमने कुछ नहीं बोला। चाचू जी, (कृषि मंत्री) आपकी उम्र के लिए यह सारी चीजें ठीक नहीं लगती है। मैं आपको एक बात कहूं, आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पहाड़

में इस शब्द को बहुत-बहुत बुरा मानते हैं। बहुत-बहुत बुरा मानते हैं। मेहरबानी करके मत बोलिए, क्योंकि मेरे पहाड़ के लोग भी सुन रहे हैं। इसलिए इस शब्द को बहुत बुरा मानते हैं। कुल्लू में, मण्डी में, हमारे ऊपर के इलाके में भी इसे बहुत बुरा माना जाता है। मैं जो बात कह रहा था कि केवल एक स्कीम का जिक्र किया है। सिर्फ एक स्कीम का नाम बदला। लेकिन यहां तो आपने कितनी योजनाएं बंद कर दी? मैंने जनमंच का तो एक जिक्र किया, आपने मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी जी के नाम पर कर दिया और उसके बाद बाकी हमारी हिम केयर योजना का हाल क्या किया है? सहारा योजना का क्या हाल क्या किया है? शगुन योजना का हाल क्या किया है? आप एक स्कीम के कारण इतने बिफर गए हैं, इतना शोर डाल रहे हैं। आपने हमारी दर्जनों स्कीमों को बंद कर दिया, बंद नहीं किया तो उनका नाम बदल दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्थिति जिक्र करने के लायक नहीं है।

20.03.2025/1610/बी.एस./ए.जी.-2

**सभापति :** अब माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री विक्रम सिंह :** माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण 16 फरवरी को दिया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। काफी दिनों से अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं और बार-बार यह विषय आ रहा है कि राज्यपाल जी ने बोला नहीं, राज्यपाल जी ने कम बोला, राज्यपाल जी ने बात बीच में छोड़ दी। उसको कोई किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। लेकिन जो बात आदरणीय सतपाल सिंह सती जी ने बोली है, इसमें पढ़ते तो क्या पढ़ते? आपने सचमुच में कोई चीज यहां ठीक नहीं लिखी है, सच्चाई कहीं नजर नहीं आ रही है। आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपकी पुराने बजट की किताब लेकर आया हूं, जो पिछली बार योजनाएं दी है कि हम यह योजना शुरू कर रहे हैं, हम यह योजना शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई भी योजना नजर नहीं आ रही है। आपके इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन योजनाओं का कोई पता नहीं चल रहा।

आपकी गारंटियां कहीं नजर नहीं आ रही। आपका वह शब्द व्यवस्था परिवर्तन कहीं नजर नहीं आ रहा। आपका वह शब्द कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा, वह कहीं नहीं मिल रहा। राज्य सबसे अमीर वर्ष 2032 में हो जाएगा, वह शब्द भी इसमें कहीं नहीं मिले। आपके वह शब्द कहां चले गए? जब भी मुख्य मंत्री जी खड़े होते हैं, मैं बदल दूंगा, अमीर कर दूंगा, आत्मनिर्भर हिमाचल, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। राज्यपाल जी के भाषण में ये सारे के सारे शब्द कहां चले गये? यह शब्द इसलिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो बोला गया है, ये जो शब्द बोले गए हैं ये कोई भी शब्द नजर नहीं आ रहे हैं। न आज हिमाचल आत्मनिर्भर हिमाचल बन रहा है, न हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, न हिमाचल प्रदेश अमीर बनने की दिशा में जा रहा है। आज तो सारे-का-सारा उल्टा-पुल्टा हो रहा है। इसमें बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं।

मैं भी हैलथ के बारे में बात करना चाहता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**20.03.2026/1615/DT/AS-1**

**श्री विक्रम सिंह जारी...**

इसमें बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। इस सदन में बार-बार आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की बात कहीं जाती रही है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ी हैरानी होती है और मैं सत्ता पक्ष के अपने साथियों को दाद भी देता हूं, ये लोग बड़े ही अच्छे तरीके से माननीय मुख्य मंत्री की तारीफ करते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इनको सामने खाई नजर आ रही है- इनको पता है हमनें डूब जाना है, फिर भी बड़े खुश हैं। ये लोग बड़े अच्छे तरीके से मुख्य मंत्री जी की तारीफ करते हैं। इन्हें उतनी तारीफ करनी चाहिए जितनी जरूरी है। जो बात गलत है उसे गलत बोलिए। जो झूठ मुख्य मंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है उसके बारे में उनको समझाइये

और कहिए कि आप सही दिशा में चलिए। लेकिन यह सब कह रहे हैं कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान सभी निर्वाचनों क्षेत्रों के अंदर अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। 134 प्रकार का प्रशिक्षण, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे, 6 विशेषज्ञ डाक्टर इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध करवाये गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र डाडासीबा में भी एक आदर्श

स्वास्थ्य संस्थान है। मैंने सोचा चलो उसकी स्थिति के बारे में पता करते हैं। मुझे वहां कि स्थिति सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर एम0ओ0 के कुल 12 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 5 पद भरे हुए हैं। अल्ट्रासाउंड वहां पर बंद है। कोई भी रेगुलर लैब-टेक्निशियन वहां पर नहीं है। वहां पर केवल टी0बी0 के टेस्ट हो रहे हैं। एक्स-रे मशीन को ऑप्रेट करने के लिए केवल तीन दिन के लिए एक्स-रे टेक्निशियन को वहां प्रतिनियुक्त किया जाता है। वहां पर पूर्व सरकार में आदरणीय जय राम ठाकुर जी के द्वारा भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपया दिया गया था। परंतु उस भवन का काम इस समय बंद है। अन्य क्षेत्रों में जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है उनमें से कई ऐसे हैं जहां पर एक्स-रे मशीन काम नहीं कर रही। डाक्टर वहां पर नहीं हैं। यह कैसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं, जरा हमें भी समझाइए? ठीक है, श्री आशीष बुटेल जी आपके पालमपुर अस्पताल में डाक्टर के सभी पद भरे हुए होंगे या कांग्रेस के जो हमारे अन्य विधायक हैं हो सकता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टर के पद भरे हुए होंगे। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हालत है? माननीय मुख्य मंत्री बार-बार रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। रोबोटिक सर्जरी की बात इस प्रकार होती है जैसे किसी को टेरामाइसिन देनी हो। आप के पास रोबोटिक सर्जरी के लिए पैसा है। रोबोटिक सर्जरी की मशीन सरकार 28 करोड़ की लागत से खरीद रही है जबकि खुले बाजार में

**20.03.2026/1615/DT/AS-2**

रोबोटिक सर्जरी की मशीन केवल 10 करोड़ रुपये की आती है और विपिन सिंह परमार जी ने उसका रेट और भी कम बताया है। क्या कारण है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल 28 करोड़ की मशीन की ही चर्चा हो रही है? क्या कारण है कि 10 करोड़ की मशीन 28 करोड़ में खरीदी जा रही है? एक टेंडर के ऊपर केवल 2 मशीन लेने की बात हुई थी। क्या कारण है उसी टेंडर में लगातार और मशीनें खरीदी जा रही हैं? कारण कोई नहीं है; कारण एक ही है? 10 करोड़ रुपये की चीज 28 करोड़ रुपये में खरीदी जा रही है। चलो मान लिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी को समझ नहीं आ रहा उनकी आंखों के आगे पर्दा पड़ गया है लेकिन सत्ता दल के अन्य सदस्यों को तो सारे-का-सारा नजर आ रहा है। प्रदेश की वित्तीय हालत कैसी है सभी को पता है। यहां पर फाइनेंशियल एमरजेंसी लग

रही है और सरकार 10 करोड़ रुपये की चीज 28 करोड़ रुपये में खरीद रही है। जो बेसिक चीजें उन संस्थान में चाहिए वे वहां पर नहीं हैं। अगर लैप्रोस्कोपी से सर्जरी करनी है तो उसमें कुल खर्चा 1.50 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक का है और अगर रोबोटिक सर्जरी करनी है तो 3.50 से 5.50 लाख रुपये खर्च होता है। इसी तरह पित्ताशय की पत्थरी का आप्रेशन जो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से होता है उसमें 40,000 से 90,000/-रुपये तक का खर्च आता है। इस मशीन को लेने में सरकार को क्या तकलीफ है? आपके पास इस प्रकार के उपकरण हस्पतालों में नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी की मशीन अब जोनल हस्पतालों में भी स्थापित करवाई जायेगी। मैं यह मानता हूं कि हम सभी को इन बातों के लिए इकट्ठा होना चाहिए। प्रदेश में जो यह भ्रष्टाचार हो रहा है यह केवल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मुद्दा नहीं है आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको इसी प्रकार का गोलमाल मिलेगा। सरेआम नजर आ रहा है कि एक मशीन खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के हैड-ऑफ- डिर्पार्टमेंट पर किस प्रकार के प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं, यह सब जानते हैं। आज किसी डाक्टर को ट्रांसफर करवानी हो तो उसे ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हेल्थ विभाग में छोटे से छोटे काम के लिए पैसा देना पड़ता है। माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ठीक बोल रहे थे कि मशीनों को खरीदने की होड़ लगी हुई है।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

20.03.2026/1620/ए.एस.-एन.जी./1

**श्री बिक्रम सिंह..... जारी**

मैं इस माननीय सदन में मांग करता हूं कि इनकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। अभी माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार काजल जी ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। (अखबार की कतरन दिखाते हुए) ये देखिए, क्या लिख रहे हैं, 'पंजाब केसरी' में लिखा है कि 'कितना टालोगे, जनवरी-फरवरी बीत गए, मार्च भी गुजरने वाला है, कब लिफ्ट की व्यवस्था होगी-टांडा मेडिकल कॉलेज?...'(व्यवधान) आपको

सुनते-सुनते 3 साल हो गए कि होटल बड़े अच्छे हो रहे हैं। मैं आपके होटलों पर भी आ रहा हूँ।

सभापति महोदय, जब भी यहां पर बात होती है या जब भी यहां विषय आता है तो कहते हैं कि हां जी, आ रहा है या इलेक्ट्रिकल बस चली हुई है। क्या उसे किसी ने रास्ते में पकड़ कर रखा है। क्या मान साहब ने पंजाब में या हरियाणा में किसी ने रोकी हुई हैं। भाई साहब, आपकी नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीयत खोटी है। सरकार की उस खोटी नीयत के कारण ही ये सारा-का-सारा विषय इस प्रकार से चल रहा है।...(व्यवधान) श्री आर० एस० बाली जी, आपको टांडा की चिंता करनी चाहिए, यह अच्छी बात है क्योंकि टांडा की हालत बहुत खराब है। उस हालत को ठीक करने के लिए हम सबको ठीक तरीके से सोचना चाहिए और अच्छे-अच्छे सुझाव मुख्य मंत्री जी को देने चाहिए। पिछले साल के बजट में बड़ी-बड़ी बातें की गईं। आदरणीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु जी ने जिस समय बजट पेश किया, उन्होंने बोला कि सात इको टूरिज्म साइट्स के ऑपरेटरों को चेंज किया जाएगा। इको टूरिज्म सोसाइटियां गठित की जाएंगी। यह तो हुआ नहीं और साल बीत गया। मुख्य मंत्री जी ने बोला था कि इस साल में होगा लेकिन अगला बजट आने वाला है। इसके उल्टे टूरिज्म के होटल बंद कर दिए गए। मैं बहुत खुले मन से बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे पास सबसे इंपोर्टेंट सेक्टर टूरिज्म है, जिसके अंदर हमें काम करना चाहिए।

**20.03.2026/1620/ए.एस.-एन.जी./2**

लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर कोई काम नहीं हो रहा। श्री आर० एस० बाली जी, आपके ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि टूरिज्म ट्रेड फेयर फरवरी-2025 में अहमदाबाद में लगा था और वहां पर आपके विभाग की जीरो रिप्रेजेंटेशन थी। इसी प्रकार फरवरी-2026 में टूरिज्म फेयर मुंबई में लगा था और वहां पर भी आपकी रिप्रेजेंटेशन जीरो है। आपका जो HPTDC है, उसने वहां कुछ किया ही नहीं और वहां पर गया भी नहीं

था। उसके बाद साउथ एशिया ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा और वहां पर जो हिमाचल होटल एसोसिएशन के लोग थे, उनकी डायरेक्टर टूरिज्म से फोन पर बात हुई। आजकल सब जानते हैं कि डायरेक्टर टूरिज्म कौन हैं। वे बड़े मशहूर आदमी हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में बैठते हैं। वे बड़े नामी-गिरामी व्यक्ति हैं। उनसे फोन पर बात हुई थी। वहां पर किस प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिए, किस प्रकार की शाबाशी देनी चाहिए, वहां पर किस प्रकार से पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहां पर हिमाचल प्रदेश का कोई-न-कोई नमूना दिखाना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के तीन इंसिडेंट बता रहा हूं और वहां पर आपके डिपार्टमेंट की जीरो प्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से टूरिज्म आगे कैसे बढ़ेगा? हम कह रहे हैं कि टूरिज्म को हमें आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन हम केवल यह देख रहे हैं कि टूरिस्ट होटलों के अंदर किस प्रकार से तालमेल बैठाकर, किसको कौन-सा होटल देना है। सरकार के लोग इसी काम में लगे हुए हैं। आप (माननीय सदस्य, श्री आर०एस० बाली की ओर देख कर कहा) पूरे हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन हैं। पहले आपके पास कैबिनेट रैंक था लेकिन अब हट गया है, नहीं तो मैंने कैबिनेट ही बोलना था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दुःख का विषय है और आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप होटलों के अंदर जाते हैं तो ऐसा काम कीजिए कि वहां ज्यादा-से-ज्यादा लोग आए। लेकिन आपने तो जो बाहर से टैक्सी आती है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए और आपने पानी के बिल भी बढ़ा दिए।

**20.03.2026/1620/ए.एस.-एन.जी./3**

श्री आर० एस० बाली जी, आप और माननीय मुख्य मंत्री बार-बार बोलते हैं कि कांगड़ा टूरिज्म कैपिटल है। मैं तो कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल तब मानता जब उसकी नोटिफिकेशन हुई होती। सभापति महोदय, केवल भाषण देकर सरकार द्वारा कांगड़ा के लोगों को खुश किया जा रहा है। सरकार के लोग कांगड़ा के लोगों को ठग रहे हैं। कांगड़ा के लोग इस बात को देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कांगड़ा में आने वाले दिन कांग्रेस

के लिए अच्छे नहीं होंगे और उसके लिए आपको कुछ करना होगा। पालमपुर विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक भाषण दे रहे थे और उनके अलावा भी सत्ता पक्ष के मेरे मित्र भी बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन लोटस किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि वह ऑपरेशन लोटस नहीं था, वे माननीय विधायक आप लोगों की नालायकी के कारण भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन विधायकों को माननीय मुख्य मंत्री अपने दफ्तर के बाहर चार-चार घंटे बिठाते थे

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

20.03.2026/1625/ए.पी./डी.सी./01

**श्री बिक्रम सिंह जारी .....**

माननीय मुख्य मंत्री उनके क्षेत्र के अंदर अनकंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज को खड़ा करते थे, जिस कारण उनके कहने पर काम नहीं होते थे। उनके क्षेत्र के अंदर विकास को रोका गया था और उनके क्षेत्र के अंदर अन्य लोगों को तवज्जो दी जाती थी। इस कारण से वे लोग आए थे। ऑपरेशन लोटस वगैरह कोई चीज नहीं है, अपनी मर्जी से वे लोग आए हैं। यहां कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। यहां ऑपरेशन लोटस किया ही नहीं है, बिना ऑपरेशन के यह गाड़ी चल रही है। मैं यह भी बता रहा हूँ कि पक्ष से भी बहुत से सदस्य अभी दुःखी हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि आप इधर आएँ क्योंकि हम पहले से ही ज्यादा फुल हो गए हैं, हमारे यहां पर हाउसफुल है। हम इसी के साथ अपना राजनैतिक सफर चलाएंगे। इसी प्रकार से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की इस किताब के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया कि हमें हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस प्रकार से काम हुआ था, उसी प्रकार से इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है। एक उदाहरण मैं बल्क ड्रग पार्क का देना चाहता हूँ। बल्क ड्रग पार्क के लिए 225 करोड़ रुपये भारत सरकार से आये हैं लेकिन आज तक बल्क ड्रग पार्क का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस पार्क को बनाने के लिए एक साल की एक्सटेंशन दी गई। बल्क ड्रग पार्क आज तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि यह पैसा लैप्स हो जाएगा, जिस तहर से काम चला हुआ है। मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से

निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि वह साल भी पूरा हो जाएगा। ... (व्यवधान) माननीय विधायक (श्री हरदीप सिंह बावा) को यह समस्या है कि इंडस्ट्री और बल्क ड्रग पार्क यहां क्यों आ रहा है। माननीय विधायक को यह समस्या है कि यहां पर नौजवान बच्चा अपने पैरों पर क्यों खड़ा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर दे दो भैया कि बंद कर दो, बोलिए कि इसके ऊपर काम न हो। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री ने स्वावलंबन योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। डेढ़ वर्ष से मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का पोर्टल बंद चल रहा है और लायबिलिटी हमारे नौजवानों की है। नौजवानों की खबरें आने वाली हैं, लोग आत्महत्या करेंगे। हमारे पास 150 करोड़ रुपये की लायबिलिटी है जो हमने नौजवानों को देनी है। मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, पोर्टल को खोला जाए और माननीय मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से जो योजनाएं

**20.03.2026/1625/ए.पी./डी.सी./02**

चल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। हमारे प्रदेश से तो अच्छा पंजाब है जिसने अभी कुछ दिन पहले नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है। आज दिन तक हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई। पंजाब सरकार जो नई पॉलिसी लाई है उसमें उन्होंने 16 प्रकार की पॉलिसी लाई हैं। एम0एस0एम0ई0, फूड के लिए अलग-अलग पॉलिसी लेकर आए हैं। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हमारे पास किसी प्रकार की कोई नई पॉलिसी नहीं है। नई पॉलिसी के अंदर पंजाब में बिजली सस्ती हो रही है। हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज को बिजली महंगी मिल रही है। आप बताइये कि हम किस तरफ जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दो दिन पहले कहा है कि 100 पार्क प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ भारतवर्ष के अंदर लगाए जाएंगे। एक-एक हेक्टेयर के लिए एक-एक करोड़ रुपये उसकी डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। क्या हमारी सरकार ऐसी पॉलिसी बना रही है? क्या इस तरफ सोच रही है कि हमें भी इस तरफ काम करना चाहिए? यह जो नये 100 पार्क आ रहा है उसमें हमें ज्यादा-से-ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो माननीय इंडस्ट्रीज महोदय को पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। उसमें हमने मेहनत की थी। वहां जाकर बहुत सारी इंडस्ट्री हमें जमीन पर देखने को मिली थी। उसके आपने कई उदाहरण भी देखे हैं और अभी आप देख भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरफ हम लोग किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे। माननीय

सभापति महोदय, आपके माध्यम से इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस समय हमारे प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी स्थिति है और प्रदेश को पैसों की जरूरत है। हम रोबोटिक्स सर्जरी की बात करते हैं। 28-28 करोड़ की मशीनें खरीद रहे हैं। यह जो हमारा सी0एस0आर0 फंड है क्या हम इसके लिए कोई पॉलिसी बना सकते हैं या क्या हम इस तरफ कोई काम कर रहे हैं? क्या हम सी0एस0आर0 पॉलिसी के माध्यम से जो महंगी-महंगी मशीनें लेकर आनी हैं, क्या वह सी0एस0आर0 के माध्यम से आ सकती हैं? हमने गरीब व्यक्ति को अस्पताल में दवाई देनी है तो क्या सी0एस0आर0 के पैसे से यह व्यवस्था हो सकती है? मेरा निवेदन रहेगा कि हम जो भी यहां पर विधायक माननीय बोलते हैं कि पैसे की बड़ी समस्या है। यह पैसे की समस्या को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण सुझाव है। इस तरफ ध्यान दें और मैं तो यह चाहूंगा।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

20.03.2026/1630 /AT/DC /01

**श्री बिक्रम सिंह जारी...**

यह पैसे की समस्या को ठीक करने के लिए मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है। इस तरफ ध्यान दें। मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री जब भी समय मिले पूरे सदन को यह बताएं कि CSR के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और उस CSR के पैसे से प्रदेश के लोगों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है। मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात की तरफ पूरा ध्यान देंगे ...(व्यवधान)

**सभापति:** प्लीज कंटिन्यू। ...(व्यवधान) प्लीज बाहर के स्पीकर को चैक करें।

**श्री बिक्रम सिंह:** सभापति महोदय, यहां बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन यह कहा जा रहा है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है। मेरे भाई कह रहे हैं कि (\*\*\*) हैं। ऐसी बातें की जा रही हैं। हमारे इलाके में जाकर देखिए पिछले सवा तीन साल में एक भी रोड पर पैच वर्क नहीं लगा। हमने तो दो-दो SDM के ऑफिस खुलवाए थे लेकिन इस सरकार ने आकर दोनों SDM ऑफिस को बंद कर दिए। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री

जी ने एक नया SDM दफ्तर खोलने के लिए गये थे लेकिन आज तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी दो SDM के ऑफिस आपने बंद कर दिए एक की घोषणा की है, उसे नोटिफाई तो करो, उसे कैबिनेट में लेकर आओ। ऐसे क्यों सबको मूर्ख बना रहे हो? हमने कोटला-बेड़ के अंदर XEN का ऑफिस खोला है। वहां पर बिल्डिंग बननी है, जमीन किसी ने दान दी हुई है। लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने बजट होने के बावजूद उस बिल्डिंग को नहीं बनने दे रही है। यह स्थिति है मैंने मुख्य मंत्री जी आपसे तीन-चार रिक्वेस्ट कर ली है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट का आप पर कोई असर हो रहा है। जमीन दी हुई है, बजट आया हुआ है, टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को टेंडर मिल गया है आज से दो साल पहले लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वह सभी का ध्यान रख रही है और सभी विधान सभा क्षेत्रों के अंदर अच्छा काम हो रहा है। कौशल विकास निगम द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी हुई है। आदरणीय धर्माणी जी पता नहीं कौशल विकास किसके पास चला गया। मुझे तो लगता है कि वह आपके पास होना चाहिए। बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसमें कोई काम नहीं है, कोई दफ्तर

**20.03.2026/1630 /AT/DC /02**

नहीं है ... (व्यवधान) सियूल खड्डु के अंदर और मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला है लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि उसमें स्टाफ दीजिए लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। ... (व्यवधान) खड्डु में नहीं है जगह का नाम सियूल खड्डु है, भाई मजाक नहीं करते किसी के एरिया के साथ मान लिया आप प्लेन इलाके में पैदा हुए हैं, ऐसे मजाक मत करो, नहीं तो आप कहीं हमारी तरफ आएंगे तो घेराव हो जाएगा।

माननीय जयराम ठाकुर जी ने डाडा शिवा में मिनी सचिवालय बनाया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि उस मिनी सचिवालय के अंदर सारे-के-सारे दफ्तर जो अभी घरों में चल रहे हैं या किराए पर चल रहे हैं, उन्हें मिनी सचिवालय में शिफ्ट किया जाए। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डाडा शिवा के अंदर अभी भी JE (इलेक्ट्रिकल) का ऑफिस अभी भी प्राइवेट में चल रहा है, पुलिस स्टेशन प्राइवेट में

चल रहा है और आंगनवाड़ी का ऑफिस पहले एक सराय में चल रहा था। उसकी तकलीफ हो गई। वह अब दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर में चल रहा है। पहले यह ऑफिस सराय पर चल रहे थे। फायर ब्रिगेड के ऑफिस भी इसी प्रकार से किसी के घर में चल रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति है पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर। लेकिन आप बार-बार कहते हैं कि इन्हें पैसा बड़ा मिला। हमें पैसा मिला ...(व्यवधान) नमस्कार, नमस्कार जी पहले आ जाते, अब तो गर्मी खत्म हो गई। ...(व्यवधान)

**सभापति:** प्लीज कंटिन्यू।

**श्री विक्रम सिंह:** अभी यह विषय आया था माननीय मुख्य मंत्री महोदय और अन्य मित्र कहते हैं कि उन्हें बहुत RDG मिली। हमें RDG मिली तो हमने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जब आपको जितने समय RDG मिली आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप लोगों ने संस्थानों को बंद करने का काम किया। आपने आम आदमी के ऊपर सेस लगाने का काम किया। आप लोगों ने आम व्यक्ति को टैक्स लगाने का काम किया। आप लोगों ने महिलाओं की HRTC की सुविधा को बंद करने की बात की। आप लोगों ने आने वाले समय में भी इसी प्रकार के कट लगाने की बात की। लेकिन जब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार यहां थी। उस समय मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसका पोर्टल डेढ़ साल से बंद है और 150 करोड़ रुपये की सब्सिडी अभी तक

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....**

**20.03.2026/1635/केएस/एचके/1**

**श्री विक्रम सिंह जारी ---**

आपने देनी है। नौजवान रो रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हमने सहारा योजना शुरू की थी, हिमकेयर योजना शुरू की, ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट की जिसकी हमने बात की है। मैंने बल्क ड्रग पार्क की बात की है जिसमें 225 करोड़ रुपये भारत सरकार से आए हैं।

**सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

**श्री विक्रम सिंह** : सभापति महोदय, केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ग्लोबल इंवेस्टर्ज मीट में 225 करोड़ रुपये आए हैं और आपको बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए एक साल की एक्सटेंशन दी है। आपका पैसा लैप्स हो जाएगा अतः मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर काम करें। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हम आर0डी0जी0 का शोर मचाते हैं, मेरा निवेदन है, वैसे मुख्य मंत्री जी, आप मानते नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको कोई बात अच्छी लग जाए। कल आपको हमारी बात अच्छी लग गई तो आपने वह कर दिया किसानों के लिए फायदा किया है। जो यह एक्सटेंशन पर दुनिया चल रही है, ये जो रिटायरीज़ हैं और आपके चीफ सैक्रेटरी, एक्स चीफ सैक्रेटरी टोटल पक्ष ले रहे हैं। आपके प्रिंसिपल एडवाइज़र को भी पूरा पैसा मिल रहा है। आपके एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी पालमपुर के प्रिंसिपल को बार-बार एक्सटेंशन मिल रही है। मैडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रिंसिपल को बार-बार एक्सटेंशन क्यों देनी पड़ रही है? यह जो एक्सटेंशन का विषय है और जिस प्रकार से ओ0एस0डीज़0 का विषय है, जिस प्रकार से रिटायरी लोगों को एक्सटेंड करने का विषय है, इन सब बातों के ऊपर इंडिपेंडेंटली सोचकर आत्मचिंतन और मनन करना पड़ेगा। आपने कहा कि मैंने अपने साथियों का कैबिनेट का दर्जा विद्द्रॉ कर लिया है। यह बात ठीक है कि बाली जी का जो बाहर फट्टा लगा था, वह हट गया होगा लेकिन बाली जी तो वहीं कोठी में हैं और स्टाफ इनके साथ में है। गाड़ियां चार-चार चल रहीं हैं। इन गाड़ियों को कम करो। मुख्य मंत्री जी, कई बार आपके मन में आता है कि मैं सोमवार को गाड़ियां बंद कर देता हूं लेकिन बंद करने से कुछ नहीं होगा, गाड़ियां कम करो। कल-परसों भी मैंने आपका काफ़िला देखा। उसमें लगभग 25 गाड़ियां चली हुई थीं। उसको कम करो। अगर आप इन सारी चीजों को ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि

**20.03.2026/1635/केएस/एचके/2**

निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का फायदा होगा। मुख्य मंत्री जी, जो मैंने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है कि आप उनके ऊपर गौर करेंगे ताकि आने वाले दिन हिमाचल के लिए अच्छे आएँ और यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, इसमें कोई भी तर्कसंगत

बात नहीं लगी इसलिए हम इसका समर्थन करने में असमर्थ हैं। सभापति महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।

**20.03.2026/1635/केएस/एचके/3**

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री:** सभापति महोदय, बिक्रम सिंह जी ने जो तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बात कही, इनके पास विभाग रहा है तो पोलिटैक्निक में तो कुछ स्टाफ लगा दिया है और जैसे-जैसे इसमें बैचिज़ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर ही है, वैसे उसमें और भी नियुक्तियां की जाएंगी। दूसरा, जो आपने कौशल विकास निगम की बात कही, इसमें जो आपने मॉडल बनाया वह सही नहीं बना। HPKVN का जो मॉडल था, ए0डी0बी0 से पैसा मिला और 600 करोड़ रुपये में से लगभग पौने चार सौ करोड़ रुपये बिल्डिंग पर खर्च हो गए। अब बिल्डिंग का यूज़ क्या करना है, उस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि उसका उपयोग कैसे करना है। HPKVN कैसे सस्टेन करे, उसके ऊपर कोई नीति नहीं बनाई गई। कुछेक जगह जैसे रैहन पॉलिटैक्निक में आपने पैसा लगाया, वह ठीक इन्वैस्टमेंट हुई लेकिन ऐसे एक-दो केसिज़ हैं। बाकी जगह पर जैसे मॉडल करियर सेंटर बने, वे हट फिर कर जो हमारे एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनको शिफ्ट कर दिया। अपने आप वे कैसे मॉडल करियर सेंटर के तौर पर फंक्शन करे उसके ऊपर कोई विचार नहीं था। इसी तरीके से जो सिटी लाइवलीहुड सेंटर और रूरल लाइवलीहुड सेंटर की बिल्डिंग बनाई गई, उनका उपयोग कैसे करेंगे, उसको कौन चलाएगा? HPKVN के पास तो उस तरह से रिसोर्सिज़ हैं ही नहीं तो इसमें भी साइलेंट रहे। जो वाकनाघाट में लगभग 100 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी है। आज एक बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई हम उसको आउटसोर्स करना चाहते हैं। आपने भी लैमन ट्री को किया लेकिन वह मॉडल भी सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट के ऊपर लगभग 10 लाख रुपये पे किया गया। लेकिन अब क्योंकि ए0डी0बी0 का प्रोजैक्ट वाइंड अप हो गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

20.03.2026/1640/av/hk/1

### नगर एवं ग्राम योजना मंत्री-----जारी

अभी उसके बारे में हमने माननीय मुख्य मंत्री से बात की है कि उसको किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जाए। उस बिल्डिंग में डिजाइन के हिसाब से 15 रुम्ज बनाए गए। आपको पता है कि 15 रुम्ज से कोई होटल नहीं चलेगा यानी उसके लिए कोई बड़ा ग्रुप नहीं आएगा। आइडिया ठीक था कि कोई बड़ा ग्रुप आए और हमारे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिले। परंतु उसमें प्रैक्टिकैलटी नहीं देखी गई। इस तरह से ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट का एक बहुत बड़ा मिसयूज हुआ। केवल एच0पी0के0वी0एन0 ही नहीं इसके अलावा जायका के पैसे आए या ए0डी0बी0 के दूसरी जगह पर आए; इसको बड़ा सीरियस थॉट देने की जरूरत है। यहां पर एक्सटर्नल एडिड के तहत जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्ज बनें वे सस्तेनेबल हो। आज हम देखते हैं जायका के अंतर्गत बिल्डिंग बनी है परंतु उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। मिड हिमालयन प्रोजैक्ट, आई0डी0पी0 और जायका में कई सिंचाई की स्कीम्ज बनी हैं। लेकिन आज उनमें से 99 प्रतिशत स्कीम्ज डिफंक्ट पड़ी हैं। एच0पी0के0वी0एन0 को हमने थोड़ा रेशनेलाइज किया है। एम0डी0 की पावर निदेशक (तकनीकी शिक्षा) को दे दी। उसी तरीके से हम यह सोच रहे हैं कि एच0पी0के0वी0एन0 का पूरा काम निदेशक(तकनीकी शिक्षा) ही देखें और हमने उसको स्ट्रैन्थन किया है। वहां पर उप-निदेशक को इन्टरप्रिन्योरशिप डवलपमेंट के लिए अलग से तैनात किया है। हमने निर्णय लिया है कि इण्डस्ट्री का काम भी अलग से एक उप-निदेशक देखेगा। धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

20.03.2026/1640/av/hk/2

### लोक निर्माण मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

**अध्यक्ष :** माननीय लोक निर्माण मंत्री, आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

**लोक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने वैसे तो काफी विषयों के बारे में बात की है। लेकिन इन्होंने यहां पर विशेषकर जो सड़कों के पैच वर्क और

नई सड़कों के निर्माण के बारे में बात की है, मैं आपको उस बारे में क्लीयर बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में हर जगह वह चाहे ए0एम0पी0 के कार्य हैं। हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष हर डिवीजन्स और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बराबर किलोमीटर्स देते हैं। इसके अतिरिक्त जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्ट्स हैं, पिछले वर्ष that is the closing financial year of 2025-2026 हमने स्टेट बजट से लगभग 224 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें पुल, सड़कें और अपग्रेडेशन के कार्य प्रदेश के अंदर किए हैं तथा आने वाले समय में भी हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम हिमाचल के प्रत्येक एरिया में समानता और पारदर्शिता के साथ काम करवा रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार 15 अप्रैल से 1500 किलोमीटर्स का कार्य एक साथ शुरू होने जा रहा है। This is a big achievement for Himachal Pradesh. ...(व्यवधान) जिसका भी है परंतु प्रदेश हमारा है और हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि यह हिमाचल की अचीवमेंट है। यह मुख्य मंत्री जी, मेरी या किसी अकेले व्यक्ति की अचीवमेंट नहीं है अपितु यह प्रदेश के लगभग 75 लाख लोगों और यहां बैठे सभी 68 विधायकों की एक कॉलैक्टिव अचीवमेंट है। ठीक है, आपने यहां पर अपनी डिवीजन से संबंधित विषय रखे हैं और उनको हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप हमें स्पेसिफिक बताएं, आपने हमारे सामने जब भी कोई बात रखी तो हमने हमेशा ही पोजिटिव तरीके से आपका सहयोग करने का प्रयास किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहां तक हमारे विभाग से संबंधित कार्य हैं हम उनको भविष्य में भी पूरी मजबूती से करेंगे। वे चाहे सी0आर0एफ0, पी0एम0जी0एस0वाई0, नाबार्ड, स्टेट हैड या ए0एम0पी0 के हैं; जो भी हों हम आपको पूरा समर्थन देने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश हित से संबंधित मैटर्स में हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।

20.03.2026/1640/av/hk/3

अध्यक्ष : माननीय बिक्रम सिंह द्वारा यहां सड़कों के रेफ्रेंस में माननीय लोक सभा सांसद (\*\*\*) का जिक्र किया गया है। वह रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेगा। ...(व्यवधान) She is an old lady now. Whosoever have said it, it will not be a part of the record.

Moreover, she is Hon'ble MP. ...(व्यवधान) मैंने सभी बका निकाल दिया क्योंकि वे अब माननीय सांसद हैं।

अब माननीय सदस्य आर०एस० बाली चर्चा में भाग लेंगे।

अगला वक्ता टी सी द्वारा जारी

20.03.2026/1645/टी०सी०वी०/वाई०के०-1

**श्री आर०एस० बाली :** अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे एक सीनियर कलीग विक्रम सिंह जी ने जब सदन में अपनी बात रखी तो इन्होंने कुछ विशेष बातें कही। वैसे तो ये सीनियर और अनुभवी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। मेरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की इनसे अपेक्षा रहती है कि जब भी ये कोई बात रखें तो वह तथ्यों पर आधारित हो और उसके पीछे प्रॉपर होमवर्क हो। बिना होमवर्क के बगैर कोई टीका-टिप्पणी करना तर्कसंगत नहीं है।

इन्होंने कहा कि एच०पी०टी०डी०सी० जिसका मैं चेयरमैन हूँ उसने किसी भी ट्रैवल और टूर से संबंधित जो एक्सपोजीशन होते हैं, जैसे इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, आई० (आई०टी०एम०) या टी०टी०एफ० (ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर) उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं ऑन रिकॉर्ड यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन्होंने इसके बारे में काफी लम्बी चर्चा की और इन्होंने जो बातें की वे तथ्यों से परे हैं। इन्होंने प्रत्येक विभाग के बारे में चर्चा की क्योंकि इनको बोलने के लिए काफी समय मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ और आज उत्तर देना आवश्यक है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं आपको वैसे ही समय दे देता हूँ। If you want to speak in favour of the Motion, I will allow you.

**श्री आर० एस० बाली :** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। वर्ष 2023 से पूर्व भी एच०पी०टी०डी०सी० ने लगातार इन सभी ट्रैवल फेयर में भाग लिया। मेरे से पूर्व कई पूर्व मुख्य मंत्री और श्री जय राम ठाकुर जी भी इसके अध्यक्ष रहे और इन सभी अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया होगा। जब से

में इसका अध्यक्ष बना हूं यानी 2023 से 2025 तक आईआईटीएम, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, जो बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, जयपुर और अहमदाबाद में आयोजित हुआ, उसमें एचपीटीडीसी ने भाग लिया।

इसी प्रकार टीटीएफ (ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर) अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, रायपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, वाराणसी, विशाखापट्टनम, पुणे, मदुराई, लखनऊ, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर, मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), पणजी, गोवा और

### 20.03.2026/1645/टीसीवी/वाईके-2

भोपाल में आयोजित हुआ, उसमें भी एचपीटीडीसी ने सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया। वर्ष 2024 में भी गांधीनगर, कोयंबटूर, भोपाल, कोल्हापुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई और भुवनेश्वर जैसे स्थानों पर आयोजित मेलों में भी एचपीटीडीसी की भागीदारी रही।

इसलिए यह कहना कि एचपीटीडीसी ने पिछले सालों में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, यह पूरी तरह से गलत और तथ्यों से परे है। इन सभी आयोजनों में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम और डीजीएम स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने सीनियर कुलीक से अपेक्षा है कि आप पहले मुझे बोलने दें। उसके बाद आप चाहे जो मर्जी बोलिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात प्राइवेट ऑपरेटर्स की भागीदारी को लेकर थी। यह सही है कि ट्रेवल शो में प्राइवेट ऑपरेटर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। उनके लिए कंसेशन और सब्सिडी दी जाती है ताकि वे अपने होटल और सेवाओं का प्रमोशन कर सकें। वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में प्राइवेट ऑपरेटर्स ने इन आयोजनों में भाग लिया और उन्हें यह सुविधा दी गई। वर्ष 2025 में कुछ कारणों से प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए यह संभव नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने भरसक प्रयास किए और स्वयं मुख्य मंत्री जी से भी इस विषय में

चर्चा की। मैंने अपने विभाग में कई बार इस संदर्भ में बात की और मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाया। इसके बावजूद भी किसी कारणवश

एन0एस0 द्वारा .... जारी

20-3-2026/1650/NS-YK/1

श्री आर0एस0 बाली-----जारी

पिछले वर्ष यह प्राइवेट ऑपरेटर्ज के लिए नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह प्राइवेट ऑपरेटर्ज के लिए भी होना जरूरी है। इसकी लाखों रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है और यह देनी भी चाहिए। यह विचार बहुत अच्छा है और इसको मैं पॉजिटिव नोट में लेता हूँ। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी भी इसके ऊपर विचार करेंगे और अगली बार हमें इसको करने के लिए जरूर प्रोत्साहन करेंगे। दूसरी बात इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कही है। इन्होंने कहा कि बाली साहब इसके चेयरमैन हैं और पहले कैबिनेट मिनिस्टर रैंक थे तथा इनको कैबिनेट रैंक मिली थी, सरकार ने दी थी। मुझे यह मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से, अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद से और कैबिनेट के सारे मंत्रियों के आशीर्वाद तथा माननीय सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन सबके आशीर्वाद से यह मिली। मैंने बतौर चेयरमैन दिन-रात काम किया। हम काम तो एज से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन करते हैं तो यह हमें एक इज्जत, रिस्पेक्ट और दर्जा मिलता है। जब आर0डी0जी0 की बात हुई तो मुख्य मंत्री जी ने सी0एल0पी0 में विधायक दल की बैठक में इसकी बात रखी, माननीय भवानी सिंह पठानिया जी भी उस मीटिंग में थे, हम सब भी उसमें थे और जब विचार-विमर्श के उपरांत यह बात आई कि स्टेट के अंदर एक परसेप्शन है और स्टेट पर पैसे का लोड पड़ रहा है। उसमें सबने कहा कि हम आपको ऑथोराइज करते हैं जिसमें मैंने और श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने भी कहा कि हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर रैंक है और हम आपको ऑथोराइज करते हैं कि आप इसके ऊपर निर्णय लें। अगर हमें अपने प्रदेश के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा तो हम अपना दर्जा छोड़ देंगे क्योंकि हमने तो सेवक के रूप में काम करना है, अगर लोगों ने विधायक बना कर भेजा है तो विधायक के रूप में काम करना

है। हम मुख्य मंत्री जी और आप सबके आशीर्वाद से, अपनी पार्टी के आशीर्वाद से उस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बने हैं जिसको हमेशा मुख्य मंत्री ने हैड किया है। जो दर्जा दिया था तो हमने इनको कहा कि आपको लगता है कि निर्णय लोगों के बीच में जाना है और पॉजिटिव वे से जाए तो सबसे पहले अपने प्रदेश के लिए हम यह त्याग करना चाहेंगे। कुछ अच्छा करने के लिए अगर सीनियर लोग यह बात बोलें तो दुःख होता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि जब मैंने

20-3-2026/1650/NS-YK/2

एच0पी0टी0डी0सी0 का कार्यालय संभाला तो उस समय एच0पी0टी0डी0सी0 का हाइएस्ट टर्नओवर 78 करोड़ रुपये था। हम इसको 78 करोड़ रुपये से 109 करोड़ रुपये तक लेकर गए। पहले वर्ष में हमने लगभग 110 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष में 105 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और अपने खर्चे खुद निकाले। पहले सरकार से एच0पी0टी0डी0सी0 को चलाने के लिए सैंकड़ों करोड़ों रुपये मिलते थे, ग्रांट मिलती थी और अलग-अलग मदों से पैसे से मदद की जाती थी तो हमने वह ग्रांट नहीं ली तथा खुद से चलाया। 50 करोड़ रुपये से ऊपर की देनदारियां खुद पैसे कमा कर वापिस कीं। मैं मुख्य मंत्री जी के पास बार-बार गया कि होटलों को आगे बढ़ाना है तो रेनोवेट करना पड़ेगा और हमें रेनोवेशन के लिए कुछ फंड चाहिए तभी हम काम कर पाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जितना साधन था, जितनी हमारे अंदर क्षमता थी और जब मैंने ज्वाइन किया था तो 78 करोड़ रुपये उन्हीं होटलों के साथ जो पिछली सरकार ने दिए थे उन्हीं होटलों के साथ हमारे कर्मचारियों ने मेहनत करके 110 करोड़ रुपये के प्रोफिट में पहुंचाया और आज तक हमने अपने खर्चे पूरे किए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एच0पी0टी0डी0सी0 आज भी अपने खर्चे खुद निकाल रही है लेकिन यह किस तरह से हमारे ऊपर लोड आया इसको मैं एक लाइन में कन्कलूड करूंगा। पिछली सरकार की आखिरी बी0ओ0डी0 हुई और मैं श्री जय राम ठाकुर जी का बड़ा आदर करता हूं, ये सीनियर नेता हैं और पूर्व में मुख्य मंत्री रहे हैं तथा यही एच0पी0टी0डी0सी0 के चेयरमैन थे, उस कुर्सी पर बैठते थे जहां पर हमारी सरकार व आप लोगों ने मुझे बिठाया है। इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम रिवीजन ऑफ पे

स्केल को स्वीकार करते हैं। यह इनकी आखिरी बी०ओ०डी० थी और उसके बाद इलैक्शन अनाउंस हो गए। जैसे ही इन्होंने रिवीजन ऑफ पे स्केल को अडॉप्ट किया 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च एच०पी०टी०डी०सी० के ऊपर आ गया। जैसे ही मैं चेयरमैन बना मेरे ऊपर

आर०के०एस० द्वारा -----जारी

20.03.2026/1655/RKS/AG-1

श्री आर०एस०बाली... जारी

जैसे ही मैं चेयरमैन बना, मेरे ऊपर सौ करोड़ रुपए से ऊपर देनदारियां खड़ी थी। हमने खुद पैसे कमाए। हमने सरकार से एक रुपया भी ग्रांट नहीं ली। हमने बहुत बार ग्रांट मांगी लेकिन हमें नहीं मिली। एक बार मैंने आपदा के समय सी०एम० साहब को फोन किया कि हमें पहली बार पैसों की जरूरत पड़ी है इसलिए इस बार आप मना मत करिएगा। इन्होंने एकदम हमें पांच करोड़ रुपये अपने साधनों के हिसाब से दिए। हमने यह पैसा उस आपदा के समय इनसे लिया था। हमें इन संस्थानों को चलाने की जरूरत थी इसलिए आपदा के समय हमने यह पैसा लिया। उसके बाद हमने कुछ नहीं लिया। हमारे ऊपर सौ करोड़ रुपए से ऊपर की देनदारियां खड़ी हो गई थीं। हमने इन तीन सालों में पचास करोड़ रुपये से ऊपर कमाकर आज की नहीं बल्कि पहले की देनदारियों को वापिस किया। मुझे लगता है कि यहां मेरे सभी वरिष्ठ बैठे हैं। आप लोगों ने कई विभाग चलाए हैं। जो पुरानी देनदारियां हैं उन्हें HPTDC के पुराने होटलों से कमाई करके भरा जा रहा है। मैंने सी०एम० साहब से कहा था कि हमें रेनोवेशन के लिए कुछ पैसे दीजिए ताकि हम होटलों को अच्छा बना सके। होटल रेनोवेशन के बगैर नहीं चल सकते। अगर होटलों की रेनोवेशन नहीं हुई तो वहां कोई नहीं रहेगा। उनकी दयनीय हालत हो जाएगी। इसलिए मैं इनके पीछे पड़ा हूं कि हमें कुछ पैसे दिए जाएं ताकि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हमें आप लोगों का

भी आशीर्वाद चाहिए। हम यहां काम करने आए हैं और आपके आशीर्वाद से हम अच्छा काम कर रहे हैं। जो सरकार ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाये हैं वे बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ त्याग कर रहे हैं तो आप उसके लिए अच्छा कहिए। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहना चाहिए। अगर बुरा करें तो आप हमें समझाइए। मुझे लगता है कि we should be like minded, always talk in a positive note. अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

20.03.2026/1655/RKS/AG-2

**अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

**मुख्य मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं इनकी बात अपने चैम्बर में सुन रहा था। ये बिना ब्रेक की गाड़ी है। ये गाड़ी रुकती ही नहीं है। इनका एक्सिडेंट का बहुत खतरा रहता है। ...(व्यवधान) मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं आपका विरोध में नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी हमारी फिल्म शुरू हुई ही है लेकिन आपने हमारी फिल्म को बीच में ही समाप्त कर दिया। हमें जो RDG का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमने कैसे करनी है, वह वित्त मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। अगर आपके विधान सभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है तो मैं आपके साथ जाकर वहां हर पंचायत में बैठकर काम करवाऊंगा। अगर आप हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे परंतु आप नहीं भी बुलाएंगे तब भी हम वहां जाकर काम करवाएंगे। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी ख्वाब ले लेते हैं। आप बड़े-बड़े सपने जल्दी सोच लेते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि अभी बहुत समय है। अभी तो यह युद्ध की शुरुआत है। आप निश्चित रहिए। जो सत्तापक्ष में बैठे हुए विधायक हैं उनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी आरोप लगाना हो तो उसके तथ्य होने चाहिए। कल श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि 10 करोड़ रुपये की रोबोटिक सर्जरी मिल रही है। अगर 10

करोड़ रुपये की रोबोटिक सर्जरी मिल रही है तो आप हमें उसे दिला दीजिए। हमने अभी दो और रोबोटिक सर्जरी खरीदनी है। फिर हम इसके टेंडर क्यों करें? अगर कहीं 30 करोड़ रुपये से कम राशि की रोबोटिक सर्जरी मिल रही है तो आप हमें दिला दीजिए। जो लोग आपको यह खबर देते हैं, उन्हें आप यह कहें कि वे इसके कागज लाएं। ... (व्यवधान) मैं विधान सभा में यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई 10 करोड़ रुपये की Da Vinci मशीन आती है तो बिक्रम ठाकुर जी जिसको बोलेंगे हम उसे आज ही मशीन का ऑर्डर दे देंगे लेकिन ऐसी बातें करना कि हम इसके कागज दे देंगे यह सत्य नहीं है। क्या आप 10 करोड़ रुपये की मशीन खरीदने के कागज दे सकते हैं? ... (व्यवधान)

श्री बी०एस० द्वारा जारी.....

20.03.2025/1700/बी.एस./ए.जी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कब तक कागज देंगे? आप कागज कब तक देंगे?

**श्री बिक्रम सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं कागज ले करके आऊंगा और दे दूंगा।... (व्यवधान)...

**मुख्य मंत्री:** नहीं, कब तक देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत बन गई है। कागज की वेरिफिकेशन करते नहीं हैं और कागज की बात बोलते हैं, एम्स दिल्ली तो झूठ नहीं हो सकता न? कृपया मेरी बात सुनो, आप दिल्ली जाइए। ... (व्यवधान) ... अच्छे कामों की जहां आपको प्रशंसा करनी चाहिए उसके बदले आप ऐसी बातें बोल रहे हैं।

**अध्यक्ष:** मुख्य मंत्री जी, कृपया बैठ जाइए हाउस का समय बढ़ाना पड़ेगा। अभी माननीय सदस्य त्रिलोक जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने चर्चा का उत्तर देना है। मैं इस माननीय सदन की बैठक 6:30 बजे अपराह्न तक बढ़ाता हूं। मुख्य मंत्री महोदय अपनी बात रखेंगे।

**मुख्य मंत्री :** ये जो कह रहे हैं, अभी कागज दे देंगे, मैं इनको कल तक का समय देता हूँ, सेशन तक का समय देता हूँ। ये खुश रहें, सेशन का समय देता हूँ। अगर कागज नहीं देंगे, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि इनकी सदस्य रद्द होनी चाहिए। क्योंकि ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह इनकी आदत है। पेखूबेला-पेखूबेला, सी0बी0आई0 जांच कर रही। आप दो कागज, कब देंगे? आप कागज कब देंगे। ये बातें ये ही लाए था न, इसलिए मैंने इनको कहा।

**श्री विक्रम सिंह :** आपको पेखूबेला की याद आ रही है उसे दुनिया जानती है।...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष :** जो मशीन 30 करोड़ रुपये की है आप उसे 18 करोड़ रुपये में देना चाहते हैं आप उसके कागज दे दीजिए।...(व्यवधान)

20.03.2025/1700/बी.एस./ए.जी.-2

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख तक ये कागज लेकर आएंगे। 25 तारीख तक आज लेकर आएंगे और हम चाहेंगे कि उन्होंने 10 करोड़ की डेबेंसी की मशीन बोली है, किसकी? जो वर्ल्ड क्लास की मशीन है। जो एम्स में 28 करोड़ की खरीदी है और हमने एक करोड़ सस्ते में खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, हम आपको लिख कर देंगे।

**अध्यक्ष :** यह सब बाद की बातें हैं, अब काफी हो गया।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, दीप राज जी बोल रहे थे, जादूगर है। (\*\*\*) अगर हम जादूगर हैं तो (\*\*\*) ये कर रहे हैं, डमरू बजाकर। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि उनको तमीज होनी चाहिए बात करने की।

**अध्यक्ष :** मैंने कार्यवाही से ये सारे शब्द निकाल दिए हैं।

**मुख्य मंत्री :** माननीय सदस्य, आप पहली बार चुन कर आए हैं। आगे का भविष्य अंधकार में ही लगता है।...(व्यवधान)... आपको बताएंगे, आपका भविष्य अंधकार में लगता है।...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं अगली बार का नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा भविष्य

अंधकार में है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम के विधायक भी जब शब्दों का इस्तेमाल करें, तो थोड़ा अच्छी तरह से करें।

**श्री जय राम ठाकुर** : मुख्य मंत्री जी, कृपया अपनी तरफ भी ये बातें बोल दीजिए।  
...(व्यवधान)

**मुख्य मंत्री** : वे आपके लिए ठीक कर रहे हैं उन्होंने आपके लिए कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आपका स्तर भी नीचे गिर गया। आपको मेरे को बोलना नहीं चाहिए। आपका स्तर गिर गया नीचे। ...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, इनके सीनियर साथियों ने इस सदन में क्या-क्या बोला है वह रिकार्ड में है। ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है।

(\*\*\*)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

20.03.2025/1700/बी.एस./ए.जी.-3

**मुख्य मंत्री** : ठीक है, फिर इनको बोलों कि अपने शब्दों का इस्तेमाल ठीक करें। मैं समझा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई सदस्य इस सभापटल पर अपनी बात रखते हैं तो फैक्ट्स के साथ रखें, तथ्य के साथ रखें हम उसको स्वीकार करेंगे और जहां एक्शन लेने की बात होगी, हमारी सरकार उसी पारदर्शिता से एक्शन लेगी। जिस पारदर्शिता से हमारी सरकार सवा तीन साल में काम करती आई है।

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी बोलेंगे और सारा जवाब दे देंगे। आदरणीय बिक्रम जी आपने अब क्या क्लेफिकेशन देनी है। आपने मशीन कागज देने हैं और आर्डर आ जाएगा। कृपया, बैठ जाइए नहीं तो इसी तरह से चलता रहेगा।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.03.2026/1705/DT/AS-1

अध्यक्ष जारी...

...(व्यवधान) अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी।  
...(व्यवधान) शुरू में सभी नये होते हैं। ...(व्यवधान) चलिए-चलिए, ...(व्यवधान)  
श्री बिक्रम सिंह जी कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान) अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य  
श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

**श्री त्रिलोक जम्वाल :** अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है, मैं इसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम पिछले दो दिनों से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हो रही चर्चा को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उस अभिभाषण के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार के कार्यों का आइना होता है। वह सरकार की पॉलिसीज का, उन पॉलिसीज की एग्ज्युकेशन का आइना होता है। यह जो दस्तावेज हमारी केबिनेट ने तैयार किया था, उसके ऊपर माननीय राज्यपाल जी ने दो मिनट और 53 सैकंड में ही पूरा प्रकाश डाल दिया। उन्होंने अपने अभिभाषण के पैरा-16 तक जो टिप्पणी की उस टिप्पणी पर इस सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैरा-16 तक जो कुछ लिखा गया है वह संघीय ढांचे के खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर, जिसकी बात सत्ता पक्ष हमेशा करता रहता है, यह दस्तावेज उसके खिलाफ था इसलिए इसको माननीय राज्यपाल ने उसे पढ़ना उचित नहीं समझा। मेरी जानकारी के अनुसार जब भी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण तैयार होता है तो केबिनेट माननीय राज्यपाल जी से कंसल्ट करती है और कंसल्ट करने के बाद एक कॉमन डाक्यूमेंट बनता है जिसको इन सदन के अंदर माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ते हैं। यह सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इतना बड़ा डिफेंस, जो प्रदेश के मुख्या हैं, जिनके नाम से हर नोटिफिकेशन निकलती है, अगर सरकार उनको विश्वास में न लेकर किसी भी कार्य को करती है और उसको माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में छाप देती है और राज्यपाल उस दस्तावेज को नहीं पढ़ते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी सरकार का नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आप स्मरण कीजिए जब वर्तमान सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष का एक कार्यक्रम मंडी में हो रहा था वहां पर कांग्रेसकी सीनियर लिडरशिप ने जो भाषण दिया, उनका वह भाषण सोशल-मीडिया में खुब वायरल हुआ। क्या कारण है कि उप-मुख्य मंत्री महोदय खुले मंच से कहते हैं कि

**20.03.2026/1705/DT/AS-2**

"माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हो जाइए और जो अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे उनको रात के अंधेरे में निपटा दीजिए"। इसका मतलब यह है कि केबिनेट के सदस्यों में कोई बातचीत नहीं होती। इसका मतलब प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बंद कमरे में कोई बात नहीं होती। इसका मतलब सरकार के मंत्रियों में कॉर्डिनेशन नहीं है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं तो वे अपने भाषण में कहते हैं कि हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध की तरह लड़ेंगे। लेकिन यह पता नहीं है कि वह लड़ेंगे किसके साथ? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भाषण देते हैं वे कहते हैं कि महफिल की सारी चकाचौंध तो उप-मुख्यमंत्री जी ने लूट ली। उप-मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि मुख्य मंत्री जी अब पिटारा खोल दीजिए, जिन लोगों को चेयरमेन-वाइस चेयरमेन के पदों पर नियुक्तियां देनी हैं श्री एन0जी0द्वारा जारी....

**20.03.2026/1710/ए.एस.-एन.जी./1**

**श्री त्रिलोक जम्वाल..... जारी**

उनको नियुक्तियां दे दीजिए। जिनके दर्जे बढ़ाने हैं, उनके दर्जे बढ़ा दीजिए। लेकिन उसके विपरीत हो गया और विधान सभा लगने से पहले उनके कैबिनेट रैंक वापस ले लिए गए। यह कैसा तालमेल है? तालमेल इतना ही खराब नहीं है बल्कि माननीय मंत्रियों की प्रदेश में कोई नहीं सुन रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्रिगण स्वयं कह रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री, श्री यादविंद्र गोमा जी को डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना पड़ा। माननीय सीनियर मंत्री, डॉ० (कर्नल) धनी राम शांडिल जी ने भी कहा है कि हम मीटिंग बुलाते हैं लेकिन ऑफिसर मीटिंग में नहीं आते। पिछले कल माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा जी यहां भाषण दे रहे थे और (\*\*\*) टोल टैक्स का किराया 70 रुपये से 170 रुपये हो गया। उन्होंने आपका (अध्यक्ष महोदय के लिए कहा) संरक्षण मांगा। इसका मतलब तो यही है कि सरकार में उनकी कोई नहीं सुन रहा है।...(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह बावा : ऐसा नहीं है, मैंने अपनी बात रखी थी और अपनी बात रखना गलत नहीं है। (बिना अनुमति के अपने स्थान से बैठे-बैठे कहा)

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले (\*\*\*) मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी ने ठीक किया जो अभिभाषण नहीं पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, एंट्री टैक्स 70 रुपये से 170 रुपये हुआ और उससे हमारी सरकार की क्या इमेज बनी? हिमाचल प्रदेश सरकार की चर्चा पंजाब की विधान सभा में हुई और वहाँ पर इंडी गठबंधन (INDI Alliance) की सरकार है। आम आदमी पार्टी, इनकी (कांग्रेस) पार्टी की सहयोगी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पर प्रदेश सरकार की जो धज्जियां उड़ाई हैं, वह निंदनीय है।

20.03.2026/1710/ए.एस.-एन.जी./2

लेकिन प्रदेश सरकार को सोचना भी पड़ेगा कि पब्लिक में हमारी रिफ्लेक्शन क्या है, हम कहां खड़े हैं।...(व्यवधान) उपचुनावों की बात तो दूर की बात है। स्मरण कीजिए कि हमने उपचुनाव भी लड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथियों ने उपचुनाव की बात की है तो उसको भी सुन लें। कई-कई बार इस बात का जिक्र हुआ और पिछले कल भी सेशन में बात आई थी कि इस बार भाजपा वालों ने कैंडिडेट नहीं दिया। पिछली बार दिया था तो क्या हुआ? उस समय आपकी सरकार कहां थी? आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आपकी इनपुट कहां थी? उस समय हमने राज्यसभा की सीट भी जीती और हम 25 विधायकों से 28 विधायक भी हुए।

अध्यक्ष महोदय, (\*\*\*)हमने पिछली बार कैंडिडेट दिया था, उसको सपोर्ट भी किया था और उसको 25 विधायकों से जीत कर भी आए थे। यह भी मैं इस हाउस के अंदर

कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) हम देंगे, जब टाइम आएगा तो हम कैंडिडेट भी देंगे और जीत कर भी दिखाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सरकार कैसे चल रही है और उसके संदर्भ में मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों में हमारी सरकार की क्या रिफ्लेक्शन है, इस चीज को दर्शाता है। ए0आई0 समिति में जिन्होंने राष्ट्र के खिलाफ साजिश रची, 'waging a war against the State' जिनके खिलाफ यह एलिगेशन था, उन लोगों को हमारी सरकार ने दिल्ली के हिमाचल सदन में रखा। वी0आई0पी0 ट्रीटमेंट में उनको वहां से लाया गया और यहां पर रोहडू में रखा गया। वे हमारी स्टेट के नहीं थे और किसी अन्य स्टेट से रहने वाले थे।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन लगा है और यह सेक्शन मैंने नहीं लगाया।...(व्यवधान)

(\*\*\*)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**20.03.2026/1710/ए.एस.-एन.जी./3**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। ऐसा है, आप यहां पर जितने एग्जाम्पल कोट कर रहे हो, विधान सभा का क्वेश्चन ऑवर, विधान सभा का ज़ीरो ऑवर, विधान सभा का कैलेंडर; this you are discussing here? विधान सभा द्वारा सभी माननीय सदस्यों को प्रदेश हित की बात रखने का अवसर दिया जाता है। उसमें कोई पार्टी की बंदिश नहीं है। क्वेश्चन ऑवर में भी

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**20.03.2026/1715/ए.पी./डी.सी./01**

**अध्यक्ष जारी ....**

विधान सभा सभी माननीय सदस्यों को अवसर देती है प्रदेश हित की बात रखने की उसमें किसी पार्टी की कोई बंदिश नहीं है। इसके अलावा शून्य काल में भी जो इशू है pertaining to the State, whether those are being raised by the Ruling party or by the Opposition, I provide an opportunity. What examples you are giving here? विधान सभा की कार्यवाही के अंदर इसी माननीय सदन का सदस्य होने के नाते आप यहां की कारगुजारी को डिस्कस कर रहे हैं। What discussion you are doing? I fail to understand. If you want to attack the Government then attack properly. You are citing the examples from Vidhan Sabha only. आप पॉलिसी के ऊपर बोलो। What do you want to say?

**श्री त्रिलोक जम्वाल :** अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)

**Speaker:** That part will not be included in the record. The Question Hour, Zero Hour of Vidhan Sabha and the questions that are being raised in Vidhan Sabha will not be part of the record.

**श्री त्रिलोक जम्वाल :** अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि कोऑर्डिनेशन सरकार में नहीं है।

**Speaker :** This is not an example of coordination. प्रश्न काल के दौरान कोई भी माननीय सदस्य किसी भी माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में जानकारी हांसिल कर सकता है। शून्य काल के दौरान वह प्रदेश से संबंधित सूचना ले सकता है। How can you give the examples like this?

**श्री त्रिलोक जम्वाल :** अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि देखिये सरकार में कितना कोऑर्डिनेशन है।

**20.03.2026/1715/ए.पी./डी.सी./02**

**Speaker :** Whatever you are saying that is already the part of the record. ये सारी बातें माननीय सदस्यों द्वारा बोल दी गई हैं। कोई नया प्वाइंट है तो बोलिए।

**श्री त्रिलोक जम्वाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो यह एफ0आई0आर0 दिल्ली में हुई है न तो वह हमारे नागरिक थे, न ही हिमाचल के रहने वाले थे।

**Speaker :** This part has already come on record. ...( Interruption). I am expecting the new points. ...(Interruption). यह विधान सभा का प्रश्न काल या शून्य काल नहीं है जो यह सदन में डिसकस होगा। वह इश्यू डिसकस नहीं होंगे जो विधान सभा के प्रश्न काल और शून्य काल में डिसकस हुए हैं। अब सभी का अधिकार क्षेत्र है। आप भी इश्यू रेज़ कर सकते हैं या कोई भी रेज़ कर सकता है। आप यह बोल सकते हो कि सरकार ने टोल टैक्स बढ़ा दिया, proportionate ज्यादा बढ़ा दी है, आप ऐसी बातें बोलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। यहां सत्ता पक्ष की ओर से कितने ऐसे माननीय सदस्यों ने बहुत ज्यादा मद्दे से बाहर बोला है। जोकि राज्यपाल अभिभाषण का हिस्सा ही नहीं था। न जाने कहां-कहां से बातें बोली गई हैं और वे सारी बातें इस रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप माननीय सदस्यों को बोलने से रोक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर टिप्पणी है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप इतना कह सकते हैं कि जो बातें बोल दी गई हैं, उससे अगल बात करें। आप यह भी कह सकते हैं कि आप राज्यपाल के अभिभाषण पर खुद को केंद्रित रख के बोलें, ऐसी बात भी समझ में आती है। लेकिन इस तरह से एक सदस्य को टारगेट करना और अन्य सदस्यों ने भी अभिभाषण पर हर कुछ बोला है और वे सब इस सदन का पार्ट है। अगर आपने शुरूआत ही इस तरह से की होती तो हम आपकी बात का स्वागत करते। आपने जो बात कही है आप बहुत ज्यादा गुस्सा न करें।

20.03.2026/1715/ए.पी./डी.सी./03

**अध्यक्ष :** मैं बताता हूँ आपको। ...(व्यवधान) न -न कोई गुस्सा नहीं है। विधान सभा के प्रोसीजर को न डिसकस करें।

**श्री जय राम ठाकुर :** प्रोसीजर एक आदमी तक कन्फाइंड नहीं हो सकता।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब ऐसा है कि यहां से भी जिन माननीय सदस्यों ने अप-शब्दों का प्रयोग किया है, वे हमने कार्यवाही से निकाल दिये हैं। Non-decorous words have been removed from the record of the Vidhan Sabha. I have already done that. ...( Interruption). मेरे पास इस सदन की कार्यवाही का एक-एक कागज़ आता है जिसे मैं अभी निकाल कर आया हूँ। जो माननीय कृषि मंत्री जी ने भी ऐसे शब्दों को बोला है वे भी मैंने कार्यवाही से निकाल दिए हैं।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी बहुत टिप्पणियां हुई हैं और सीनियर सदस्यों की तरफ से टिप्पणियां की गई हैं।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब जो undesirable टिप्पणियां हुई है वह मैंने निकाल दी हैं। That is not part of the record.

**श्री जय राम ठाकुर:** मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई सदस्य बोल रहा है और वह रिधम में बोल रहा है तो आप उनको बोलने दीजिए।

**अध्यक्ष :** माननीय त्रिलोक जम्वाल जी।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

20.03.2026/1720 /AT/DC /01

**अध्यक्ष:** बोलिए श्री त्रिलोक जम्वाल जी... (व्यवधान) आप बैठिए त्रिलोक जी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

**मुख्य मंत्री:** अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता बार-बार उठ जाते हैं। जब कोई सदस्य बोल रहा होता है ये बीच में उठ जाते हैं। इसके लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम बोलते हैं तो ये बीच में उठ जाते हैं... (व्यवधान) बोलने की परमिशन लेंगे...

आपको कौन... (व्यवधान) आप फिर उठ गए। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम बोलकर हटें... (व्यवधान)

**अध्यक्ष:** बैठिए, बैठिए।

**मुख्य मंत्री:** हम बोलकर उठें... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए माननीय अध्यक्ष जी। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात खत्म करूँ उसके बाद आप उठिए हाथ खड़ा करिए आपको बोलने का समय मिलेगा। बीच में उठ जाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप अभी फिर उठ गए। मैं कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता बीच में न उठें। बात खत्म होने के बाद उठें तो अच्छा रहेगा। यही परंपरा है। आप इन्हें बार-बार उठने का मौका देते रहे हैं इसलिए इन्हें बीच में उठने की आदत पड़ गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब मैं राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पेश करूँ तो बीच में किसी को बोलने के लिए कोई समय मत देना।

**अध्यक्ष:** माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी....(व्यवधान) अब जब बात आएगी तब देखेंगे। The Hon'ble Chief Minister has expressed himself. ...(Interruption).आपकी आवाज को कौन बंद कर सकता है? प्लीज बैठिए। श्री त्रिलोक जम्वाल जी... (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूँ कि विधानसभा के रूल और प्रोसीजर... (व्यवधान) प्लीज बैठिए। चलिए, त्रिलोक जम्वाल जी।

**श्री त्रिलोक जम्वाल:** मैं कह रहा था कि सरकार के हालात को माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कैसे डिस्कस किया गया है। लेकिन सरकार को कुछ बातें पिंच हुई होंगी, जो मैंने कही होंगी, इसलिए बीच में इंटरप्शन हो गई। लेकिन तथ्य तो तथ्य रहेंगे, तथ्य

20.03.2026/1720 /AT/DC /02

कभी बदल नहीं सकते। सरकार अगर किसी तथ्य को छुपाना चाहे तो वह छुपेगा नहीं वह देर सबेर बाहर आएगा ही।

**अध्यक्ष:** आप निकालो, सारे तथ्य निकालो।

**श्री त्रिलोक जम्वाल:** अध्यक्ष महोदय, इसलिए जहां तक बात प्रदेश सरकार की है और उसके एक्शन की है इनहोंने पैरा 84-85 में जी पर सुबह भी चर्चा हुई थी चिट्ठे के विषय पर सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखा रही है। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे बिलासपुर में कुछ समय पहले शायद यह आपके ध्यान में होगा कि वहां घटनाएं हुईं, गोलियां चलीं लेकिन दिसंबर महीने में माननीय मुख्य मंत्री जी बिलासपुर आए। पुलिस ने स्कूल के बच्चों को लेकर एक बड़ी मैराथन करवाई यह अच्छा कदम है मैं उसकी वारे में नहीं कहूंगा। लेकिन उसमें हुआ क्या बच्चों ने जो नारे लगाए वे सोशल मीडिया पर हैं मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। उसी बिलासपुर में जिस दिन यह रैली होनी थी उससे एक दिन पहले, वहां की महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने गांव में पहरा दे रही थीं। उन महिलाओं पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। यह FIR किसके कहने पर दर्ज की गई? एक छोटा सा झगड़ा हुआ, जिसमें चिट्ठा सप्लायर शामिल थे। उसके बाद महिलाओं सुबह 10 बजे पुलिस को सूचना देती है, लेकिन शाम को हमारी पुलिस ने उन्हीं महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करती है जब इस FIR के खिलाफ पूरा बिलासपुर सदर विधान सभा क्षेत्र इकट्ठा हुआ तो 30 तारीख को मैंने रैली निकाली। उस दौरान मैंने सरकार को चेताया कि आपने बिल्कुल गलत किया है। जिन महिलाओं ने सूचना दी, उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गईं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इधर-उधर घूम रही है। जिस व्यक्ति के कहने पर FIR दर्ज हुई उसे पुलिस घर से बुलाकर लाई थी और उसके खिलाफ पहले से 10 ग्राम चिट्ठे का केस दर्ज है।

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....**

**20.03.2026/1725/केएस/एचके/1**

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी ..

उसके ऊपर 10 ग्राम चिट्टे का केस पहले रजिस्टर है और उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे ऊपर चिट्टे का केस रजिस्टर है और मैं 9 महीने रिहैबिलिटेशन सेंटर में रह कर आया हूँ। उसके कहने पर गांव की भोली-भाली औरतों के ऊपर इस सरकार ने केस रजिस्टर किया। मेरे पास एफ0आई0आर0 की कॉपी है। जब हमने हो-हल्ला किया, पुलिस स्टेशन का घेराव किया, उसके बाद अब सरकार कह रही है कि हमसे गलती हो गई, हम इसको विद्‌ड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इस सरकार के दो मुख हैं। मैंने उस दौरान पूछा था कि किस कांग्रेस के नेता के प्रभाव में, किस कांग्रेस के नेता के टैलीफोन के ऊपर आपने एफ0आई0आर0 रजिस्टर की और क्यों की? अगर आपकी एफ0आई0आर0 ठीक थी तो आप विद्‌ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। इतना ही नहीं, मेरे बिलासपुर में जो गोलियां चलीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उन गोलियों में प्रदेश सरकार के नुमाइंदों को, जिनको इस सरकार का संरक्षण प्राप्त है, पूर्व विधायक का बेटा ढाई महीने जेल के अंदर रहा और इस सरकार ने उनको एक नहीं दो-दो पी0एस0ओ0 दिए। इसके अलावा जब दूसरी बार गोली चली, उसके बाद 6 पुलिस काँस्टेबल लगाए। आपकी कोई ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें लिखा है कि एक नहीं, दो नहीं, छः चाहिए ताकि वह जा कर रेलवे में गुराही कर सके। पुलिस स्टेशन में जा कर लोगों को धमका सके। इतना ही नहीं 6 पुलिस काँस्टेबल देने के बाद, जिस पूर्व विधायक बम्बर सिंह ठाकुर के ऊपर 30 से ज्यादा केस हैं, 30 से ज्यादा एफ0आई0आर0 हैं,

**Speaker** : Shri Trilok Jamwal Ji, you cannot refer to (\*\*\*) here because he is not in a position to reply for him. ...(Interruption) You cannot refer a person one who is not a Member of the House. क्योंकि यहां आप उसी का रेफरेंस दे सकते हैं जो जवाब दे सके। आप इनडायरेक्टली बोलिए, स्थानीय नेता कहें लेकिन नाम ना लें।

**श्री त्रिलोक जम्वाल** : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद प्रदेश सरकार ने उस गोलीकांड के मैटर को 24 अक्टूबर, 2024 को सी0बी0आई0 को हैंडओवर किया। लेकिन उसके बाद 6 पुलिस वाले दिए। मैं कह रहा हूँ कि 6 नहीं, 10 या 15 दो लेकिन यह मत कहो कि रेलवे में

20.03.2026/1725/केएस/एचके/2

गुराही करने जाए, पुलिस के साथ फोरलेन में गुराही करने के लिए जाए और इतना ही नहीं, यहां तो ये कहते हैं कि एक केस है तो आपको आम्बु का लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपने 30 केस वाले को जिसके परिवार के ऊपर आम्बु एक्ट में केस है, उसको गन का लाइसेंस दे दिया, यह इस प्रदेश सरकार ने अभी किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या लिखा है कि विधायक को नहीं चाहिए, जो गुराही करने वाले हैं, उनको चाहिए। यह पता नहीं ज्वाइंट या कौन सी कमेटी है उसमें यह लिखा है। इतना ही नहीं, शर्म की बात तो इससे आगे है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का और क्या हो सकता है? मेरे बिलासपुर के एस0पी0 क्या लिख रहे हैं? वे लिख रहे हैं कि साहब मुझसे इस व्यक्ति ने मार-पीट की और मेरी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए और उस एफ0आई0आर0 में लिखा कि मेरी छाती में, अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुना रहा हूं जो कि बड़ा इंट्रस्टिंग है। प्रदेश सरकार जो कह रही है कि हम लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर सीरियस हैं, यह एफ0आई0आर0 167/2025 है। मैं इस एफ0आई0आर0 का रिलेवेंट कंटेंट पढ़ रहा हूं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर, मैं शिव चौधरी अपने अंगरक्षक व चालक सहित थाना तरीफ में हुए जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की एक शिकायत पत्र संख्या सो एण्ड सो के बारे (\*\*\*) द्वारा सरकारी कर्तव्य के पालन में उत्पन्न गाली-गलौच, धमकी देना, अपराधिक बल का प्रयोग करने से सम्बन्धित अभियोग को पंजीकृत करने बारे। इन्होंने लिखा है कि इस दिन एस0पी0 महोदय छुट्टी पर हैं और मैं और एस0डी0एम0 दोनों वहां गए थे जहां इन्होंने हमारे साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। आगे रिलेवेंट पैरा लिखा है कि don't push me कहने के बावजूद धक्के दिए, सरकारी कर्तव्य के पालन में बाधा उत्पन्न की और वहां बैठकर मेरे साथ ये-ये किया।

(\*\*\*)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.03.2026/1730/av/hk/1

### श्री त्रिलोक जम्वाल-----जारी

के बावजूद धक्के दिए और सरकारी कर्तव्य के पालन में बाधा उत्पन्न की तथा वहां बैठकर मेरे साथ ये-ये किया। पूर्व विधायक (\*\*\*) ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मेरी छाती में दर्द है, मेरा मेडिकल करवाया जाए और एफ0आई0आर0 भी दर्ज की जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस प्रकार की है कि जिस व्यक्ति ने गोलियां चलवाईं और जिसका बेटा अंदर रहा उसको आर्म्ज दे दिए तथा जब पुलिस अधीक्षक कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और मेरा मेडिकल करवाइए तो वह एफ0आई0 आर0 करवा रहा है। यहां अगर कोई व्यक्ति झगड़ा भी करता है और उसके पास अगर आर्म्ज हैं तो उस आर्म्ज को सरेंडर करवा लिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। इस बार होली के दिन उस रिवाॅल्वर को ओपनली लहराया जा रहा था, किसको बताने के लिए लहराया जा रहा था? हिमाचल एक पहाड़ी और शांति प्रिय प्रदेश है और इसको देवभूमि कहा जाता है। उस प्रदेश में एक व्यक्ति के साथ दस पुलिस वाले और वह व्यक्ति हवा में रिवाॅल्वर लहरा रहा है; आप हमें बताइए कि यह कहां की संस्कृति है? जिन व्यक्तियों ने प्रदेश में काॅट्रैक्ट किलिंग का काम शुरू करवाया तथा सुपारी देने का काम किया उनको मेरी प्रदेश सरकार लाइसेंस इश्यू कर रही है कि एस0पी0 से लड़ना है तो हाथापाई नहीं करनी अपितु गोली का इस्तेमाल कीजिए। फिर यह सरकार कानून-व्यवस्था की बात करती है।

राज्यपाल महोदय ने ठीक किया जो इस अभिभाषण को नहीं पढ़ा। वैसे तो वे पढ़कर आए थे और शर्मसार भी हुए होंगे। यह सरकार जो कानून-व्यवस्था की बात करती है इनके कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। यह तो एक उदाहरण हैं परंतु पूरे प्रदेश में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जैसे यहां पर माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती भी कह रहे थे। ऐसा क्या हो गया है कि हमारी सरकार कुछ लोगों के अधीन रहकर कार्य कर रही है, इस सरकार की ऐसी कौन-सी कमजोरी है? मैं 'कमजोरी' इसलिए कह रहा हूं कि सी0बी0आई0 को लिखा गया कि आप केस रजिस्टर कीजिए। जब चिट्ठी गई और बाद में क्लेरीफिकेशन आई तो उसको प्रदेश सरकार द्वारा नहीं भेजा गया। मैं मुख्य मंत्री जी का

धन्यवादी हूँ कि इन्होंने पहले तो भेज दी परंतु ठीक है, बाद में ऊपर से कोई दबाव पड़ा होगा तो उसके बाद नहीं

20.03.2026/1730/av/hk/2

भेजी। लेकिन सरकार की इंटेंशन तो तभी क्लीयर हो गई थी जब इन्होंने भेजी और ये मानते हैं कि कल्प्रिट हैं, ये लोग चिट्टे को बढ़ावा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अपराध बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता और जब भ्रष्टाचार चरम पर है तो अपराध हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर गैंग वार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आय दिन शूट आउट की घटनाएं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यह मानना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ नहीं है। ...(व्यवधान) इस पर धन्यवाद प्रस्ताव तो आया है परंतु जिसको राज्यपाल महोदय ने पढ़ा ही नहीं मैं उसका समर्थन कैसे कर सकता हूँ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह अभिभाषण एक क्रोरा कागज और झूठ का पुलिन्दा है इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूँ। धन्यवाद।

20.03.2026/1730/av/hk/3

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से उत्तर देंगे। उसके उपरांत इस प्रस्ताव पर इस माननीय सदन के अंदर वोटिंग भी होगी। इसलिए मेरा सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठे रहें क्योंकि I will put this Motion to the vote after the reply from the Hon'ble Chief Minister.

मुख्य मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जिसका अनुसमर्थन श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने किया, उस पर लगभग 35 सदस्यों ने भाग लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ और मैं माननीय सदन की गौरवशाली परम्पराओं के

अनुरूप सदस्यों से यह भी अनुरोध करूंगा कि भविष्य में रचनात्मक चर्चाओं में अवश्य हिस्सा लें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए राज्यपाल महोदय ने इसको लगभग दो मिनट्स में पढ़कर समाप्त किया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे पहले ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बीच में मत बोलना। आपने बाद में जितना मर्जी बोलना होगा, बोल लेना। अगर आप बीच में बोलते हैं तो मेरी बोलने की दिशा कुछ भटक जाती है और फिर हम बहस करने लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुरोध मैं आपसे ही कर सकता हूँ क्योंकि इनको तो हम बोल नहीं पाएंगे।

**टी सी द्वारा जारी**

20.03.2026/1735/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

**मुख्य मंत्री ... जारी**

अध्यक्ष महोदय, जब सच्चाई सामने आती है तो थोड़ी पीड़ा होती है।

**अध्यक्ष :** पीड़ा तो सहन करनी पड़ती है।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, यह बात आपने बिल्कुल करेक्ट कही और जो सत्ता की कुर्सी पर रह चुके होते हैं उन्हें ज्यादा पीड़ा होती है। आप (विपक्ष) भी सत्ता में रह चुके हैं इसलिए आपको ज्यादा पीड़ा होगी लेकिन आपने इसको सहन करना। अन्यथा इनको पानी का गिलास आइसक्यू के साथ दे देना। ... (व्यवधान) आप फिर उठ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने 2 मिनट 37 सेकंड में अपना अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं का पालन किया और उसी अनुसार किसी भी सरकार की एक वर्ष की कार्यप्रणाली को बजट सेशन के प्रारंभ में अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह सही है कि उन्होंने कम समय में अभिभाषण पढ़ा लेकिन उसकी प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई थीं और सभी सदस्यों ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। इसलिए जब विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे तो उनके पास बोलने के लिए ठोस मुद्दे नहीं थे। वे विषय से भटक गए थे। पूर्व मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके तहत किसने कितनी खरीद की? मैं रूरल इकॉनमी की बात करना चाहता हूं। हमने अपने पहले बजट में यह निर्णय लिया कि रूरल इकॉनमी को मजबूत किया जाएगा। हमने इसका अध्ययन किया कि गांवों में लोगों का जीवन-यापन किस प्रकार का हो रहा है। हम स्वयं किसान परिवार से आते हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर शिक्षा प्राप्त कर शहरों में रह रहे हैं लेकिन आज भी लगभग 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। आज गांव में भी शहरों जैसे सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 75 लाख परिवार हैं जिनके 2 घर हैं। एक शहर में जहां वे नौकरी-पैशा करते हैं और दूसरा गांव में। हम सब लोग एक संस्कृति में पले हैं।

### 20.03.2026/1735/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

हमने पहले बजट में घोषणा की कि हम रूरल इकॉनमी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और हमने दूध के मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की। कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, हमने योजना बनाई और उसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले 6 महीने में प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कांगड़ा के डगवार में शुरू हो जाएगा। यह 1.50 लाख लीटर क्षमता का प्लांट होगा। इसमें घी, मोजरेला, पनीर और दही का उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एन0डी0डी0बी0 कंपनी के साथ समझौता किया गया है जो अमूल के प्रोडक्ट्स को भी बनाती है। वही इस प्रोजेक्ट को संचालित करेगी और उसकी क्वालिटी को एंशोर करेगी। यह रूरल इकॉनमी को सुदृढ़ करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है जिसका विपक्ष ने कोई जिक्र नहीं किया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला अग्रणी राज्य बना जो दूध पर

सबसे ज्यादा एम0एस0पी0 दे रहा है। इससे सीधे गांव के किसानों और दूध उत्पादकों के हाथ में इन्कम पहुंची है। यह एक सोच थी कि गांव के लोगों की आय कैसे बढ़ाई जाए। उस सोच को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धरातल पर उतारा है।

इसके बाद हल्दी के विषय में कहा गया कि केवल 64 लोगों से हल्दी खरीदी गई। वर्ष 2025-26 के बजट में पहली बार कच्ची हल्दी पर एम0एस0पी0 देने की घोषणा की गई और जब यह घोषणा की गई तब किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी कि सरकार उनको एम0एस0पी0 देने जा रही है। फिर भी कुछ किसानों

एन0एस0 द्वारा .... जारी

20-3-2026/1740/NS-YK/1

मुख्य मंत्री -----जारी

को खुशी हुई और वे मुझे मिले तथा कहा कि हमें खुशी है कि आप गांव के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं लेकर आए। आप कह रहे हैं कि 150 से 200 लोगों से खरीदी जिसका आपने व्याख्यान किया। इस वित्तीय वर्ष में दस गुणा लोग बढ़ गए हैं और हमें प्राकृतिक खेती का बीज नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में जिस तरह शिमला में सेब होता है तो हल्दी की खेती से लोगों की आय बढ़ेगी और सरकार उस हल्दी को खरीदेगी। आप उस दृष्टिकोण से देखिए कि अगर इतनी सारी हल्दी की पैदावार होगी तो हम कहां बेचेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है। Spice Board of India भारत सरकार का एक उपक्रम है। श्री आनन्द शर्मा जी कॉमर्स मिनिस्टर होते थे तो मैंने Spice Board of India से यह प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया था। हमने इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि उसकी प्रोसेसिंग और जो उसका करक्यूमिन होता है वह बैस्ट क्वालिटी का मिले। हम यह भी देख रहे हैं कि किस हल्दी के बीज में सबसे ज्यादा करक्यूमिन होगा? लॉकडॉग में एक हल्दी है और यह नॉर्थ ईस्ट में होती है तो हम उसको भी यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े। यह क्यों सोचा गया? यह किसानों ने नहीं सोचा। इसको सरकारों को सोचना चाहिए। जो सरकारें

सोचती हैं और किसानों का भला करती हैं उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज है जिसको बंदर नहीं खाते हैं। किसानों ने अनाज उगाना छोड़ दिया, नीलगाय और बंदर उनको तंग कर रहे हैं। इसलिए किसानों ने बोला कि हमें डिपुओं के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो आटा मिल रहा है और 3 रुपये प्रति किलो चावल मिल रहा है तथा 200 रुपये में पूरे घर का खाना मिल रहा है तो कौन बंदरों व नीलगाय को भगाता रहेगा? हल्दी एक ऐसी चीज है जिसको बंदर भी नहीं उखाड़ सकता, जिसको नीलगाय भी नहीं खा सकती और किसानों के हाथ में आय का साधन भी बन जाएगा। हमारी सरकार ने इस सोच के साथ सवा तीन साल में यह कार्य किया। अभी 3 वर्ष 3 महीने 9 दिन हुए हैं और कल में 10वें दिन बजट पेश करने जा रहा हूँ। हम एक-एक दिन सोच कर प्रदेश-हित में कार्य कर रहे हैं। एक-एक दिन सोच कर मैं हर विभाग के बारे में बात करता हूँ। मैं प्रातः अधिकारियों को फोन करता हूँ और मेरा एक स्वभाव है कि मैं जे0ई0 को भी फोन कर देता हूँ कि क्या काम चल रहा है तथा मैं उनसे रिपोर्ट

20-3-2026/1740/NS-YK/2

ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे 20 प्रोजेक्ट्स प्रदेश-हित के होंगे जहां से प्रदेश की आय होगी और उन प्रोजेक्ट्स को देखकर आप भी कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपको विरोध इसलिए करना पड़ता है कि आप विपक्ष में हैं। आप विरोध खुल कर कीजिए, कागज लाइए, तथ्य लाइए, जहां भ्रष्टाचार हुआ है वे कागज बताएं। हम किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बर्खेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूँ क्योंकि इस प्रदेश की संपदा को न तो हमारी सरकार लुटने देगी और न ही लुटाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर गेहूं की बात की गई। हमने 60 रुपये प्रति किलो प्राकृतिक खेती से गेहूं खरीदा। गेहूं का एम0एस0पी0 25 रुपये प्रति किलो केंद्र सरकार दे रही है जबकि हम 60 रुपये प्रति किलो किसानों से खरीद रहे हैं। हमने मक्की खरीदी। श्री लोकेन्दर कुमार जी अच्छा काम करते हैं और वहां के लोगों द्वारा बेचे गए दूध के पैसे के लिए आवाज भी उठाते हैं। आनी के लोगों की दूध से काफी आय हुई है। मैं नाचन क्षेत्र में गया और वहां पर

बुजुर्ग महिलाएं आईं और कहा कि पहले हमें 32 रुपये प्रति लीटर दूध का रेट मिलता था लेकिन अब हम महीने का 10,000 रुपये कमा रही हैं। सिराज में भी लोग दूध मिल्क प्लांट में बेच रहे हैं। अब हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस वर्ष हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। इसके लिए मेरी कृषि मंत्री जी व एन0डी0डी0बी0 से बात हुई थी तो हम नालागढ़ व सभी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है तो आने वाले समय में हम इनको बढ़ावा देंगे। हमारी सरकार दुग्ध इण्डस्ट्री को बढ़ावा देने जा रही है। यह व्यवस्था परिवर्तन का ही नतीजा है कि हम गांव के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और एक सोच का बदलाव कर रहे हैं। हमने कभी भी संपदा को नहीं लुटाया। अब संपदा को भारतीय जनता पार्टी की पिछले पांच वर्षों की सरकार ने कैसे लुटाया? मैं लुटाने का उदाहरण देना चाहता हूं और आप लोग बुरा मत मानना। ...(व्यवधान) मैं बिल्कुल सही बोलूंगा

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

20.03.2026/1745/RKS/AG-1

मुख्य मंत्री जारी.....

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने SJVNL के साथ समझौता किया। इन पर दिल्ली का दबाव था लेकिन मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। दिल्ली के दबाव में इन्होंने SJVNL वालों से धोलासिद्ध, सुन्नी और लूहरी प्रोजेक्ट्स का समझौता कर दिया। प्रदेश की इन संपदाओं को लुटाने का इनका तरीका देखिए। इन्होंने कहा कि हम इन परियोजनाओं से न तो रॉयल्टी लेंगे और न ही इन प्रोजेक्ट्स को वापिस लेंगे। हिमाचल प्रदेश के पास सबसे बड़ी संपदा पानी है जो बहता हुआ सोना है। माननीय शांता कुमार जी ने भी पहले यह बात कही थी। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। माननीय शांता कुमार जी ने कहा था कि यह बहता हुआ पानी हमारा सोना है, यह हमारी बहती हुई संपदा है। मैंने केन्द्रीय मंत्री जी से इस संबंध में बात की थी। उस समय आर0 के0 सिंह केंद्रीय मंत्री थे और आज श्री मनोहर लाल खट्टर जी केंद्र में मंत्री हैं। मैंने कहा कि हमें इन प्रोजेक्टों से 12

प्रतिशत रॉयल्टी और 1 प्रतिशत लाडा में पैसा दिया जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। हमने हौंसला दिखाया और कहा कि हम इन प्रोजेक्टों को टेक-ओवर करेंगे। जिस प्रदेश की आर्थिकी को ये कंगाल करके चले गए थे उस संपदा को हमने बिकने से बचाया। हमने उनको चिट्ठी लिखी और हमें उस चिट्ठी का उत्तर भी आया। यह राज्य के प्रति हमारी कमिटमेंट है। आज क्या हुआ? ...(व्यवधान) हुआ यह कि केंद्र सरकार से हमें एक चिट्ठी आई। ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आपने पूछा कि हुआ क्या तो मैं आपकी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। आप पूर्व मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपके साथ बैठे हैं ये आपका आदर करना भूल रहे हैं। ...(व्यवधान) हमने उनको बोल कि क्या आप हमें 12 प्रतिशत रॉयल्टी देंगे? उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। मैंने कहा अगर आप हमें रॉयल्टी नहीं देंगे तो हम आपको इन परियोजनाओं को चलाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप परियोजनाओं को चलाने नहीं देंगे तो फिर आप इन परियोजनाओं का क्या करेंगे? मैंने कहा कि हम इन प्रोजेक्टों को टेक-ओवर करेंगे। उन्होंने कहा कि आप इन

20.03.2026/1745/RKS/AG-2

परियोजनाओं को कैसे टेक-ओवर कर सकते हैं? मैंने उन्हें कहा कि यह प्रदेश की 75 लाख जनता की संपदा है। हम इस पानी को आगे नहीं जाने देंगे। ...(व्यवधान) हुआ क्या पर ही तो मैं पहुंच रहा हूं। मैंने पहले भी बोला कि इसमें सस्पेंस रखना चाहिए। उसके बाद फिर उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। हम ऑफिसरज के साथ वहां गए। उन्होंने कहा कि आपको हमें ये प्रोजैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने पड़ेंगे। हम इनकी कोई रॉयल्टी नहीं देंगे। मैंने बोला कि यह बिल्कुल नहीं होगा। हमारे अधिकारियों ने कहा कि हम कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैंने बोला हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास पैसे कहां से आएगा? आपका खजाना तो खाली है। मैंने बोला कि इस खजाने को खाली करके कौन गया? उन्होंने कहा कि इस खजाने को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाली

करके गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय 70 हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 और जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में आए थे। मैंने कहा इतने पैसे मिलने के बाद उन्होंने कैसे संपदा लुटा दी? ...(व्यवधान) मैंने पूछा कि सत्तर हजार करोड़ कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि यह राशि 5 वर्ष की आर0डी0जी0 के रूप में मिली थी और तेरह-चौदह हजार करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन था। मैंने कहा इतना पैसा मिलने के बाद भी पूर्व सरकार ने कोई प्रोजैक्ट क्यों नहीं बनवाया। उन्होंने कहा कि नहीं बनाया। मैंने कहा कि जो पिछली सरकार के समय 48 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था उसमें क्या कुछ कर्ज वापिस किया? उन्होंने कहा कि कुछ कर्ज वापिस नहीं किया। मेरे पास कुछ अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ सोचना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैंने यह सब सोच लिया है। मैं इन्हें कई बार बोलता हूँ लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। मैंने उन्हें बोला कि मैं इस प्रदेश की संपदा को बिकने नहीं दूंगा। ...(व्यवधान)

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

20.03.2025/1750/बी.एस./ए.जी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

मैंने बोला कि क्या सोचा? मैंने बोला कि मैं प्रदेश की संपदा को बिकने नहीं दूंगा। जब मैंने यह कहा कि मैं प्रदेश की है, उस संपदा को बिकने नहीं दूंगा।

**श्री जय राम ठाकुर :** लेकिन हुआ क्या?

**मुख्य मंत्री :** मैंने फिर कहा आप एक बार और मीटिंग करिए और जा कर यह बताइए कि यह जो प्रोजैक्ट है धोलासिद्ध, सुन्नी और लुहरी इनको सरकार ले लेगी। वे फिर गए आदरणीय राकेश कंवर जी पावर सचिव थे और अधिकारी सारे गए, मुख्य सचिव भी थे ये सब गए। वे हमारे अधिकारियों को मना रहे थे परंतु मैं नहीं मान रहा हूँ और जब मैं मान नहीं रहा था तो होगा क्या? अब क्वेश्चन है क्या होगा? मैंने कहा होगा वही जो प्रदेश में कांग्रेस का मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा और सरकार डिसाइड करेगी। फिर सरकार ने कहा

कि नहीं यह तो प्रदेश के संपदा लुटाई जा रही है इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने स्टैंड ले लिया कि हम आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे, यह हुआ। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि ऐसे-ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं, मैंने पूछा कैसे-कैसे हैं? अधिकारी ने मुझे उनकी एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि आप इनको टेकओवर करने के लिए तैयार है? हमने उस चिट्ठी का रिप्लाई दिया कि हम उनको टेकओवर करने के लिए तैयार हैं। उनकी चिट्ठी आ गई कि हम देने के लिए तैयार हैं। यह पहला पार्ट हुआ।

अब मैं दूसरा पार्ट और बताता हूँ क्या हुआ, फिर यह हुआ कि हमने बोला आप जाकर टेकओवर की तैयारी करो, फिर क्या हुआ? वे हाईकोर्ट चले गए, कहां गए? हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने बोला कि हम प्रोजेक्टों के बारे में विचार कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। हम सारे पैसे देने को तैयार हैं और हम टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। अब वे आनाकानी कर रहे हैं। अब कह रहे की 12 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी ले लो 13 प्रतिशत ले लो। मैंने कहा नहीं चलेगा और अब जब हाईकोर्ट में अगली पेशी होगी उन्होंने कहा कि इवेलुएटर लगाओ हमने कहा इन्हीं से लगवाओ वे कहते हैं कि आप लगाओ हमने खर्चा कुछ ज्यादा कर दिया। हम इवेलुएटर भी लगाएंगे जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन होगी और उन प्रोजेक्टों को टेकओवर भी

20.03.2025/1750/बी.एस./ए.जी.-2

करेंगे, यह हुआ। हमको जो प्रोजेक्ट्स देना नहीं चाह रहे थे अब हमारे पास प्रोजेक्ट लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, यह भी हुआ।

**श्री जय राम ठाकुर :** वे 5 हजार करोड़ रुपये मांग रहे हैं।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, वे 5 हजार करोड़ रुपये मांग रहे, आप ठीक कह रहे हैं। परंतु हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ता हूँ और मुझे लड़ने में बड़ा मजा आता है। आपके साथ बड़ा प्यार है, आप प्यार से बोलते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे नरमी से बोलता

हूं। हम लेंगे 5 हजार करोड़ रुपये के लिए प्रदेश का 50 हजार करोड़ रुपये नहीं बहने देंगे। अभी आपको बोलने के लिए आगे बहुत सारी बातें आएंगी।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

20.03.2026/1755/DT/AS-1

**मुख्य मंत्री जारी...**

...(व्यवधान) मैं सतपाल सिंह सत्ती जी की बात का बुरा नहीं मानता। ...(व्यवधान) नहीं- नहीं चिट्ठी लिखने का अपना कार्यक्रम नहीं था। ...(व्यवधान) श्री सतपाल सिंह सत्ती जी और मैं विश्वविद्यालय में एक साथ थे। विश्वविद्यालय में चार-पांच साल इन्होंने भी बिताए और चार-पांच साल मैंने भी बिताए।

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि गत तीन सालों में हुआ क्या? ...(व्यवधान) आज तीन साल, तीन महिने और 9 दिन सरकार को बने हुए हो गये हैं और कल यानी दसवें दिन बजट प्रस्तुत किया जायेगा। गत तीन सालों में क्या हुआ मैं यह भी बता देना चाहता हूं। पिछले तीन सालों में इस प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं को सहन किया। वर्ष 2025-2026 में हमने एक बड़ी आपदा का सामना किया। वर्ष 2023-2024 में भी आपदा आई और उससे बड़ी आपदा वर्ष 2025-2026 में आई। वर्ष 2024-2025 में रामपुर के समेज ने सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना किया। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं आईं। उस आपदा के समय में भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक रोटियां सेख रही थी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि विधान सभा का विशेष सत्र बुलाइये। आपदा के समय प्रदेश के सभी अधिकारी, कर्मचारी आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता में लगे थे। ...(व्यवधान) अगर आपने वॉक-आउट करना है तो मैं अपनी बातों को थोड़ा हल्का कर देता हूं ...(व्यवधान) पुलिस के जवान अपनी जान में खेल कर प्रभावित लोगों की जान बचा रहे थे। माननीय सदस्य श्री सुंदर सिंह जी रोप-वे में फंसे परिवार के साथ थे। ...(व्यवधान) हमारे मंत्री मंडल के सदस्य, हमारे उप-मुख्य मंत्री अन्य सभी मंत्री कुल्लू पहुंचे और तीन दिन तक कुल्लू में रहे और वहां पर फंसे 75000 पर्यटकों को बचाया। पीने की पानी की पाइपस जो टूट गई थी उनको 48 घंटे के भीतर रिस्टोर करके लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया। बिजली के खंबों को फिर से खड़ा करके बिजली की सप्लाई को रिस्टोर किया। जो सड़के टूट गई थी, वे चाहे कच्ची थी या पक्की

थी, सभी को रिपेयर करवाया गया। पिछले तीन सालों में हमने आपदा का सामना किया और उससे हुए नुकसान को सहन भी किया और वहन भी किया। कल बजट प्रस्तुत होने के बाद कोई और स्थिति होगी इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस आपदा को सहन करने के बाद मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया। मुझे अधिकारी बोलते थे कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केवल 1 लाख 30 हजार रुपये ही दिया जा सकता है और प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 20 हजार रुपये अंश दिया जा सकता

**20.03.2026/1755/DT/AS-2**

है। 1 लाख 50 हजार में किसी का घर नहीं बनता। प्रभावित परिवार रो रहे थे-विलग रहे थे। बच्चों के स्कूल कि किताबें बाढ़ में बह गई थी। सरकाघाट के क्षेत्र में एक परिवार ने रात को खाना खाया और उसके एक घंटे के बाद उस क्षेत्र में पूरा पहाड़ नीचे आ गया और वहां पर रह रहे लोगों के द्वारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई गई लेकिन वह अपने घरों को नहीं बचा सके। हिमाचल प्रदेश में व्यक्ति पाई-पाई जोड़ कर अपना घर बनाता है। प्राकृतिक आपदा में प्रभावित परिवारों के 23000 घरों में कुछ पक्के घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये और कुछ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। लोगों का पशुधन बह गया। ऐसे आपदा प्रभावित परिवारों के साथ प्रदेश की सरकार खड़ी रही। हमने सितम्बर माह में सत्र बुलवाया। भाजपा ने नियम-67 के अंतर्गत दो दिन तक उसमें चर्चा की। विपक्ष के द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया। मैंने कहा कि विपक्ष के लोग तो बड़े गंभीर हैं। काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सब लोगों ने उस चर्चा में भाग लिया। मैंने कहा कि हम आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल देंगे। जहां भी आपदा आई हमने आवश्यकता अनुसार कानून व नियम बदल दिए। वर्ष 2023-2024 में

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**20.03.2026/1800/ए.एस.-एन.जी./1**

**मुख्य मंत्री..... जारी**

वर्ष 2023-24 में 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। जहां 5000/- रुपये आंशिक नुकसान होने पर मिलते थे, वहां हमारी सरकार ने एक लाख रुपये दिए। एक गाय के मरने पर 35000/- रुपये मिलते थे, हमारी सरकार ने 55000/- रुपये दिए। यह सब हमने अपनी सम्पदा से दिया और इसके लिए हमें पूरे देशवासियों से मदद मिली। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे थे। आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय, ये लोग यहां पर खड़े हो कर नारे लगा रहे थे।...(व्यवधान) आप लोग नारे लगा रहे थे।...(व्यवधान)

(विपक्ष के कुछेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर शोरगुल करने लगे।)

मैंने बोला कि पूरे देश से मदद मिली।...(व्यवधान) आप लगे होंगे। बैठ जाइए।...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी, बैठ जाइए।...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि एक गुट लगा होगा।...(व्यवधान) आपने वॉकआउट नहीं किया।...(व्यवधान)

**Speaker** : Please, order in the House.

**मुख्य मंत्री** : इसके बाद नए भाषण आएंगे क्योंकि कल बजट पेश होगा।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, यह समझ नहीं आ रहा?...(व्यवधान) बैठ जाइए।...(व्यवधान) जाना है तो चले जाइए लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर शोरगुल करने लगे।)

20.03.2026/1800/ए.एस.-एन.जी./2

**Speaker** : Please take your seats. ...(व्यवधान) बैठ जाइए।...(व्यवधान)

**मुख्य मंत्री :** आप लोगों ने क्या किया है, बता दीजिए?... (व्यवधान)

**अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी अंदर की बात कर रहे हैं (विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहा)। ... (व्यवधान) आप लोगों ने फील्ड में तो काम किया होगा। ... (व्यवधान) जब यहां पर चर्चा हो रही थी, तब क्या किया?... (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी विधान सभा के अंदर की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप अपने शब्द वापिस ले लीजिए। ... (व्यवधान)

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष के नेता को बोलने दीजिए, मैं बैठ जाता हूं। ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष :** आप सभी बैठ तो जाइए। ... (व्यवधान) Please take your seats. श्री त्रिलोक जम्वाल जी, बैठ जाइए। ... (व्यवधान) एक मिनट, बैठ जाइए। ... (व्यवधान) मैं आपको मौका दे रहा हूं। माइक ऑन होने दीजिए। ... (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री यील्ड कर गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह जिम्मेवारी है कि यदि प्रदेश के ऊपर आपदा आती है तो उस घड़ी में प्रदेश के लोगों की मदद की जाए। सरकार के मुखिया होने के नाते आपने (मुख्य मंत्री जी को कहा) आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठाए, उसका जिक्र आप यहां पर कर सकते हैं। लेकिन हम पर बार-बार आरोप लगाना और यहां तक बोलना कि हमने (स्वयं के लिए कहा) आपदा प्रभावित परिवारों की मदद नहीं की, विरोध करते रहे, आपने ये किया-वो किया, अरे, आपने (मुख्य मंत्री जी के लिए कहा) तो आपदा प्रभावित परिवारों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज की हैं और उसको कोई भूल नहीं सकता। सरकार ने तीन-तीन मामले/एफ0आई0आर0 दर्ज किए हैं।

20.03.2026/1800/ए.एस.-एन.जी./3

जिन परिवारों के सदस्य बाढ़ में बह कर चले गए, उनकी जिंदगी चली गई और उनकी लाश भी नहीं मिली, प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का यह आरोप बहुत पीड़ा देने वाला है। आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, यह बर्दाशत के योग्य नहीं है। मुख्य मंत्री जी के आरोपों को हम सीरे से खारिज करते हैं और इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए माननीय सदन से बहिर्गमन कर गए।)

(सत्ता पक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर विपक्ष के माननीय सदस्यों के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री.....श्री ए०पी० द्वारा.....जारी

20.03.2026/1805/ए०पी०/डी०सी/०१

**मुख्य मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी थोड़ा-सा बोलना शुरू किया और वे पांच बार बोले की हुआ क्या। ... (व्यवधान) मुझे याद है कि सितंबर में सत्र हुआ था, उसमें चर्चा हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय सदन से वॉकआउट किया। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पहला भाग तीन साल पहले शुरू हुआ था। उसके बाद दूसरा भाग शुरू हुआ, जोकि राज्य सभा चुनाव के समय शुरू हुआ। उस चुनाव

में हमारे कुछ विधायकों को या ऐसा कहूं कि लोकतंत्र को खरीद लिया गया। जिन्होंने लोकतंत्र को खरीदा वे दोनों आज चुप बैठे थे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, आप विधि के ज्ञाता रहे हैं, कानून पढ़ा है, प्रैक्टिस की है और राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा विधायक के रूप में हुई है। उस दौरान नो विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डाला और वोट डालने के बाद वे सभी सीधे भागकर पहले डेस्टिनेशन पर लंच किया और वहां से भाग गये। जबकि यहां बजट पर चर्चा हो रही थी। यह सारा सवा तीन साल का हिसाब है क्योंकि आगे हमारा दो, सवा दो साल में नया सिस्टम है, उसमें हम बात करेंगे। जब हमारी विधान सभा में बजट को लेकर चर्चा हो रही थी तो उस समय ये पंचकूला के होटल में पहुंच गए, वहां उनके लिए टूरिज्म का होटल बूक किया हुआ था। इसके बाद अगले दिन उन्हें यहां आना था, क्योंकि अगले दिन कट-मोशन थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कट-मोशन में काफी लंबा विस्तृत बयान दिया और साथ में ही वोटिंग भी हो रही थी। लेकिन वे कट-मोशन से पहले ही चले गये। Whip जारी था और अध्यक्ष महोदय आपको इसकी जानकारी भी थी। हमने इन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये अनाडेल में हेलीकॉप्टर के रास्ते पंचकूला पहुंचा दिए गए। आपने Whip जारी होने का नोटिस भी दिया। श्री सतपाल जैन जी भी यहां आए। आपने हियरिंग की और उसके बाद प्रदेश का बजट पास हुआ। आपने कानून के दायरे में जो किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया। जिससे 6 विधायकों की सदस्यता गई। इतिहास में पहली बार छः विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई। साथ-ही आज्ञाद उम्मीदवार विधान सभा के प्रांगण में बैठे और इस्तीफा देने की बात करने लगे और स्पीकर साहब को कहा कि हमारा इस्तीफा मंजूर करें। स्पीकर साहब ने उन्हें समझाया कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी का

**20.03.2026/1805/ए.पी./डी0सी/02**

समर्थन नहीं करना है तो इस्तीफा मत दो, भाजपा के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन वे हड़ताल पर बैठ गए और दिल्ली से हेलीकॉप्टर से उड़कर आए और इस्तीफा दिया। आपने उन्हें इन्कार किया और राज्य सरकार ने भी इन्कार किया लेकिन वे नहीं माने। यह प्रदेश की जनता है जो न तो अपना सम्मान को बिकने देती है, न ही अपनी ईमानदारी को बिकने देती है और न ही अपनी नैतिकता को बिकने देती है। उसी प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र की मर्यादा को जीवित रखा। एक समय में एक व्यक्ति ने दो वोट डाले, एक सांसद का और

एक विधायक को। देवी-देवताओं और जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। जनता ने लोकतंत्र में आस्था और विश्वास दिखाया। भाजपा ने लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें धूल चटाई। वे कल्पना कर रहे थे कि जीत जाएंगे, सरकार चलेगी। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी 7:30 बजे राज्यपाल जी के पास चले गये, दर्जी को मॉलरोड से बुलाया और कोट पेंट भी सिलवाया। हमारी विधायक दल की मीटिंग चली थी। हम सभी विधायक इक्वेटे वुडविला पेलेस से आए। मुझे फोन आय कि माननीय जय राम जी के घर दर्जी गया है और नाप ले रहा है। मैंने सोचा कि यह नाप क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि शायद शपथ हो जाएगी। मैंने माननीय नेगी जी को बोला कि माननीय स्पीकर साहब सिंसील में बैठे होंगे। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मनु सिंघवी जी कुछ और कह रहे थे, हमारे वकील कुछ ओर बोल रहे थे। आप आए और आपने इन्हें ऐसा रास्ता दिखाया कि वह पूरे हिन्दुस्तान में एक इतिहास बन गया। इसके अलावा एक और इतिहास बना कि आजाद उम्मीदवार इस्तीफा देने के लिए हड़ताल पर बैठे।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

**20.03.2026/1810/AT/DC /01**

**मुख्य मंत्री जारी...**

ऐसा इतिहास शायद पूरे विश्व में नहीं होगा। इतना अतिविश्वास था कि आजाद उम्मीदवार भी इस्तीफा दे रहे थे और यहां तो भगवान को भी चुनौती दे दी। हमने वह भी सहन किया और जनता के आशीर्वाद से दोबारा जीतकर आए।

तीसरी बात हमारे प्रदेश में हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आप अंदाज़ा लगाइए जिनको वर्ष-2017 से वर्ष-2022 तक 47,000 करोड़ रुपये से लेकर 54,000 करोड़ रुपये की RDG मिली हो जिनको 1 जून 2022 तक जी0एस0टी0 कम्पनसेशन मिला हो 5 साल में करीब 13,000 करोड़ रुपये और कुल मिलाकर लगभग 70,000 करोड़ रुपये मिले हों फिर भी वह प्रदेश की संपदा को लूटा रहे थे।

फिर भी महिलाओं के बारे में जो बात कही जा रही है कि 50 प्रतिशत सुविधा काट दी ऐसा नहीं है। हमने कहा कि कार्ड बनाए जाएं ताकि बाहर की महिलाएं इसका फायदा न उठा सकें और हिमाचल की महिलाओं को लाभ मिले। आज भी हम 50 प्रतिशत सब्सिडी महिलाओं को दे रहे हैं।

आज भी हम 125 यूनिट बिजली हर परिवार के मीटर पर दे रहे हैं। लेकिन कई परिवारों ने मुझसे कहा कि हमें एक ही मीटर पर सब्सिडी दी जाए। हम उसको करने जा रहे हैं हम एक या दो मीटर पर सब्सिडी दें इसकी हम जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। मैं यह विधान सभा के पटल पर कहना चाहता हूँ कि यह जनता की मांग है। जब जनता खुद मांग करती है तो यह व्यवस्था परिवर्तन जो आपके दुखों को सुन कर आती है। आर्थिक चुनौती आज भी है और कल भी रहेगी लेकिन हमें विकास की बात करनी चाहिए। यह भी एक इतिहास बनने जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण आपके सामने रखा गया है। जब हम नियमों में परिवर्तन करते हैं कानून बदलते हैं अच्छे के लिए कानून बदलते हैं हिमाचल की Per Capita Income में पहली बार पिछले 10 सालों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक Per Capita Income में 1,26,883

### **20.03.2026/1810/AT/DC /02**

रुपये की वृद्धि हुई थी और यह 1,73,565 रुपये तक पहुंची थी पिछले कुछ सालों में। हमारे 3 साल में Per Capita Income 2,73,626 रुपये तक पहुंच गई है। हम जी0एस0टी0 और जी0डी0पी0 में 10 प्रतिशत की ग्रोथ लेकर चल रहे हैं। रियल टाइम ग्रोथ 6.4 प्रतिशत के आसपास आ रही है। इसलिए जहां आर्थिक तंगी की बात की जा रही है हम उससे नहीं जूझ रहे बल्कि अपने रिफॉर्म्स के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। हमें 17,000 करोड़ रुपये की RDG मिली है। आज सभी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहें हैं ताकि गरीब और आम आदमी को बार-बार टेस्ट न करवाने पड़ें। पहले मरीज जोनल अस्पताल में एक्स-रे करवाता है, फिर जिला अस्पताल में, फिर

IGMC में हर जगह पैसे देता है और अंत में बीमारी का पता PGI या प्राइवेट अस्पताल में चलता है क्योंकि 19 साल पुरानी MRI मशीनों हैं तो इस पर डॉक्टर भी क्या करेंगे। IGMC, जो हमारा प्रीमियम संस्थान है हमें डॉक्टरों को भी करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ करना है। हमने यही परिवर्तन किया है जो हमें 17000 करोड़ रुपये की RDG मिली है उस से 70,000 करोड़ रुपये की तुलना में 17,000 करोड़ रुपये तीन गुना कम हैं लेकिन हमने फिर भी काम किया। अज मैं एक और बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय इस मंच के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह-सुबह आते हैं लेकिन ये कई गुटों में बंटे हुए हैं। एक की बात दूसरा नहीं सुनता। जय राम जी बोलते हैं तो पांच सदस्य खड़े हो जाते हैं। उनका कंट्रोल नहीं रहा है। मेरी सहानुभूति जय राम जी के साथ हमेशा रही है और अभी भी बार-बार उठ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था ठीक हुआ कि यह चलेगे है। उनकी सरकार के समय जितना प्रदेश का धन लूटा गया उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज कस्टमाइज्ड पैकेज की बात हो जो यह कर रहे थे और बोल रहे थे कि 10 करोड़ रुपये की रोबोटिक सर्जरी की लाएंगे। क्या यह लेकर आए हैं? 25 तारीख को कार्रवाई कर लेना बाकी आपकी डिस्क्रेशनरी पावर है।

**श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....**

**20.03.2026/1815/केएस/एचके/1**

**मुख्य मंत्री जारी -**

आप किसी को भी लेते हैं, ले आना। मैं तो बड़ा खुश हूंगा। उसको कहना कि एजेंसी ही तू ले ले। हम तो अभी दो और देने जा रहे हैं। हम इनसे कस्टमाइज्ड पैकेज के बारे में पूछना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब प्रदेश की सम्पदा को लूटा दिया जाता है। एक रुपये में पांच हजार बीघा जमीन को बिना रजिस्ट्री फीस माफ करके यानी की पांच हजार बीघा जमीन को इन्होंने एक करोड़ रुपये में दिया। कहा कि यहां उद्योग आएंगे। उद्योग कहां आए? तीन रुपये यूनिट बिजली देंगे और कहा कि यहां जितनी सड़कें बनेंगी वह सरकार

बनाएगी। और यह भी कहा कि आप इनके लिए जो बनाएंगे उसके लिए इनको रखने की स्टोरज भी आप करेंगे। हमें ऐसी चीजें चाहिए ही नहीं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारी पॉलिसी से आगे बढ़ रही है। हम कोई उद्योगपतियों को लाकर नहीं आए। उद्योग तो आए लेकिन कौन से उद्योग आने चाहिए, यह पहली बार किसी सरकार ने चिन्तित किया कि हमारे पास डेयरी बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, फिशरी बेस्ड उद्योग होने चाहिए। हमारे पास टूरिज्म होना चाहिए, हाइड्रो होना चाहिए, जियो थर्मल में हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं और आने वाले समय में बायोचार का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। नई-नई चीजें ला रहे हैं। सोच बदल रहे हैं और सोच बदल कर ही प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, पहले क्या होता था कि वाइल्ड फ्लावर हॉल में सरकारी वकील भी उनका और प्राइवेट वकील भी उनका होता था। उनकी कोई नहीं सुनता था। हमने टॉप क्लास के वकील खड़े किए, केस भी जीते और 401 करोड़ रुपये हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से लिए। जे0एस0डब्ल्यू0 से, मैंने पूछा कि तुमने रिट क्यों नहीं की? हाई कोर्ट ने अवार्ड उनकी फेवर में कर दिया कि इनको आप 12 परसेंट पर ही ले लो। मैंने कहा कि यह गलत बात है। कुछ अधिकारी/ कर्मचारी मेरे पास आए कि 12 परसेंट पर ही रहने दो हमारे पास नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की, कोर्ट ने माना और 18 परसेंट से जे0एस0डब्ल्यू0 से हमें हर साल डेढ़ सौ करोड़ रुपये का फायदा हो रहा है। हमने सम्पदा को नहीं लूटा, हमने बनाया है और प्रदेश के हित में जो नीतियां ले कर आए हैं, उनको कोई बदल नहीं

**20.03.2026/1815/केएस/एचके/2**

पाएगा। आत्मनिर्भरता की यही निशानी होती है। यह सोच इनमें एक भी नहीं है। जब मैं शुरू में नारा देता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक उड़ाते थे और कुछ अधिकारी लोग भी मजाक उड़ाते थे। बजट कल आएगा और उसमें हमारी एक झलक दिखेगी। हमें किस प्रकार निचोड़ने की कोशिश की है, हम उन सभी चीजों पर नहीं जाना चाहते लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कालिया जी ने तो किसी और संदर्भ में मामला उठाया था परंतु अभी मुझे खबर मिली की एयरपोर्ट के पास गरीब लोगों से कितने लोगों ने जगह खरीदी है। अब हम वह सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर

हम सही दिशा में, नीतिगत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे तो हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा। बेशक इन्होंने हमारी आर०डी०जी० काट दी है, 2032 में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। ये सेंट्रल स्कूल की डिमांड करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रदेश में 150 सी०बी०एस०ई० स्कूल खोल दिए जाएंगे। दो महीने के अंदर वहां शिक्षक भी दे दिए जाएंगे और उसका प्रभाव देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों में ज्यादा बच्चे आने लग गए हैं। अगर वहां ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो हमें उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी है, उसके लिए भी हमने शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां होनी चाहिए। दो महीने के भीतर सबसे बैस्ट टीचर राज्य चयन आयोग द्वारा चुनकर वहां लगा दिए जाएंगे। अभी राज्य चयन आयोग में परीक्षाएं चल रही हैं। उसमें प्री नर्सरी से ले कर प्लस टू तक बच्चों को म्यूजिक पढ़ाया जाएगा क्योंकि बच्चों का उसमें शौक होता है। किसी का ड्रॉइंग में तो किसी का योगा में शौक है। सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी और वहां हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हैल्थ सेक्टर में कोई नहीं सोच सकता था कि पी०जी० होगी। जब मैंने निचले स्तर पर अध्ययन किया कि हमारे मेडिकल कॉलेजों में हो क्या रहा है?

श्रीमती अ०व० द्वारा ---

20.03.2026/1820/av/hk/1

**मुख्य मंत्री-----जारी**

हैल्थ सेक्टर में कोई नहीं सोच सकता था परंतु मैंने जब मेडिकल कॉलेज के निचले स्तर पर अध्ययन किया कि हमारे मेडिकल कॉलेजों में हो क्या रहा है और हम क्या लोगों को महज ऐसे ही सपने दिखाते रहेंगे। पी०जी० वे डॉक्टर होते हैं जो एम०बी०बी०एस० के बाद एम०डी० करते हैं। यहां पर 275 सीट्स पी०जी० की हैं। मैंने कहा कि इस वर्ष 275 सीट्स पी०जी० की और लेनी हैं और चम्बा, नेरचौक व हमीरपुर के मेडिकल कॉलेजों चलाने हैं तभी ये होस्पिटल्स चलेंगे वरना डॉक्टर स्थानांतरण में ही रह जाएंगे। हमारे पास उनके लिए बहुत पैसा है। हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सड़कों और पानी के लिए भी पैसा है। हमारे पास सभी चीजों के लिए पैसा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली जाते रहे और यहां पर उप-मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि आप हमें चिट्ठी तो दिखाइए कि आपने आर०डी०जी० की बात की है। आज के बाद अगर वे चिट्ठी दिखाएंगे तो वह फेक चिट्ठी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये दिल्ली गए मगर हमें साथ लेकर नहीं गए। हम चीख-चीख कर कह रहे थे और अगर मुझे साथ लेकर नहीं जाना था तो एक मंत्री को ही साथ ले जाते। हमारे माननीय राजस्व मंत्री को ही ले जाते। ये लोग एक ही गाड़ी में जाते तो इनके बीच में प्यार-मोहब्बत भी बढ़ता। इनको नहीं तो हमारे उप-मुख्य मंत्री जी या माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) को ही ले जाते। फिर हम विश्वास तो करते लेकिन अब आर०डी०जी० बंद हो गई तो प्रदेश के लोगों का अधिकार भी बंद हो गया। ये लोग सोचते हैं कि हम इनको तंग करेंगे तो सरकार ओ०पी०एस० वापिस ले लेगी। हमारी सरकार ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला किया कि हम ओ०पी०एस० को लागू करेंगे और काँग्रेस पार्टी की सरकार कभी भी ओ०पी०एस० को वापिस नहीं लेगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह हमने राजनैतिक लाभ के लिए नहीं किया। अगर हमें राजनैतिक लाभ लेना होता तो हम इसको वर्ष 2027 में करते और मैं इस बात को बार-बार बोलता हूँ। हमने ओ०पी०एस० इसलिए दी क्योंकि यहां पर रोजगार के साधन नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में पेंशन देते हैं तो उसका अगला परिवार भी पल जाता है और बच्चे भी पढ़ जाते हैं जोकि पढ़कर बाहर निकलते हैं। यहां कोई इण्डस्ट्री थोड़ी न है, पांवटा और काला

**20.03.2026/1820/av/hk/2**

अम्ब में कुछ जगह पर हमारी इण्डस्ट्री लगी है बीच में तो कोई इण्डस्ट्री नहीं लगी है। बाकी जगह तो कुछ लोग हमारे होम स्टे, होटल इत्यादि से पैसा कमा रहे हैं और हमारे लोग छोटा-मोटा गुजारा करके संतुष्ट हैं। हम उस संतुष्टि को भी बनाए रखना चाहते हैं। इन सब चीजों के बाद हमने जब तर्क रखें और हमने यह तर्क भी रखा कि पंजाब में कोई नदी नहीं बहती है। पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से ऑर्जिनेट होती हैं। आज पंजाब फूड बाउल ऑफ इण्डिया बना है क्योंकि उनको हिमाचल से पानी जाता है और हम उनको पानी देते

भी रहेंगे। हम पानी देने को मना नहीं कर रहे हैं। हम लंग्ज ऑफ द नॉर्दन इण्डिया है। हमारी 60 प्रतिशत फॉरैस्ट लैण्ड है। हम साफ व ताजी हवा पूरे नॉर्थ इण्डिया को दे रहे हैं। अगर हमारे अधिकार छिनने की कोशिश की जाएगी तो प्रदेश का हर बच्चा उठेगा और अगर आज नहीं तो कल उठेगा। हमारे जो प्रोजैक्ट्स अपनी लागत पूरी करके कर्ज मुक्त हो चुके हैं तथा काफी लाभ कमा चुका हैं उनसे कम-से-कम 50 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी तो दीजिए क्योंकि रॉ-मेटेरियल तो वॉटर है। यहां पर भगवान जितना पानी बरसायेगा उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा होगी। फिनिश्ट गुड्ज इलैक्ट्रिसिटी है परंतु उसका भी पैसा देने को तैयार नहीं है। मैंने यह बात काफी ऊंचे स्तर पर उठाई है और इस बारे में चिट्ठी लिखी है। उसके बाद हमारे पास सारे दरवाजे खुले हैं। आज नहीं तो कल जीतेंगे, कल नहीं तो पांच वर्षों के बाद जीतेंगे या दस वर्षों के बाद जीतेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सरकार में हैं तभी लड़ेंगे। हमारा मतलब यह है कि हम अगर सरकार में हैं तो उसकी सम्पदा को जिन्दा रखें और उसकी लड़ाई कोई आने वाले समय में भी लड़े। हम इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। हमने नीड बेस्ड पंचायतों का गठन किया। पंचायतों के गठन के पीछे हमारा यह मकसद है कि पंचायतों में दूरी बहुत ज्यादा न हो। पता लगा कि कोई पंचायत 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूर से कोई व्यक्ति कब आएगा और ग्राम सभा की मीटिंग अटेण्ड करेगा क्योंकि

**टी सी द्वारा जारी**

**20.03.2026/1825/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**मुख्य मंत्री ... जारी**

हमारी जो जियोग्राफी है, वह बहुत विस्तृत है, उसी के अनुसार हमने यह कार्य किया। हमारी सरकार की तत्परता देखिए, गरीब आदमी को उसका अधिकार मिलना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में 27,000 परिवार ऐसे हैं जो बी०पी०एल० परिवार से संबंध रखते हैं और वे कच्चे घरों में रह रहे हैं। हमने सर्वे करवाया और उनको आई०आर०डी०पी० की कोई भी सुविधा बंद नहीं की।

हमने विस्तृत सर्वे करवाया और निर्देश दिए कि बी०डी०ओ० और एस०डी०एम० इसकी जांच करेंगे। लगभग 85,000 परिवार ऐसे पाए गए जिनकी स्थिति का आकलन किया गया और वे पात्र पाए गए। अभी छट्टे चरण का भी सर्वे होगा क्योंकि उन परिवारों का भी इस सम्पदा पर अधिकार है। आज हमने अनाथ और विधवा महिलाओं के लिए बिल लाया है। लगभग 6,000 बच्चे अनाथ हैं। हमारी सरकार ने उनके लिए काम शुरू किया। बच्चा अनाथ हो गया, माता-पिता नहीं रहे, कोई चाचा या बुआ के पास रह रहे हैं। वे उनकी दया पर निर्भर हैं। उसके मन में डर बना रहता है कि उसने कहीं जाना है और पता नहीं चाचा जी पैसे देंगे या नहीं। हमने उस डर को दूर करने का प्रयास किया और मुख्य मंत्री सुखाश्रय कानून बनाया। इसके तहत 27 वर्ष तक बच्चों का ध्यान सरकार रखेगी। जन्म लेने वाले बच्चे को भी नर्स की सुविधा मिलेगी और 2,500 रुपये उसके अकाउंट में दिए जाएंगे। हमने 6,000 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया है। बिलासपुर की एक बेटी को 2 लाख रुपये कार्य शुरू करने के लिए दिए गए। घर बनाने के लिए प्लॉट दिया और घर बनाने के लिए हम पैसे भी दे रहे हैं ताकि वह आत्मसम्मान से जीवन जी सके।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी 30 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। इसमें खर्च का कोई मुद्दा नहीं है, अगर 300 करोड़ भी खर्च होंगे तो वह भी सरकार करेगी। जितने बच्चे जरूरतमंद होंगे उन्हें सहायता दी जाएगी। विधवा बहनों के लिए भी हमने कार्य किया है। यदि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या NIT में पढ़ रहे हैं तो उनकी पूरी फीस और हॉस्टल का खर्चा भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत सरकार दे रही है।

20.03.2026/1825/टी०सी०वी०/वाई०के०-2

जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है ऐसे बच्चों के लिए 30 लाख रुपये तक का लोन डॉक्टर, इंजीनियर या NIA की पढ़ाई के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

हमने आर0डी0जी0 की सुविधा न होने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को 7 प्रतिशत डी0ए0 दिया जिसके लिए हमने ट्रेजरी की एडजस्टमेंट की। हमने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। हमने 70 वर्ष से ऊपर के सभी कर्मचारियों का एरियर दे दिया है। क्लास फोर्थ के जो कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 तक के थे उनका 70 प्रतिशत एरियर भी दे दिया गया है।

**अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी आप कितना समय लेंगे?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, 10-15 और लूंगा।

**अध्यक्ष :** अब इस माननीय सदन की बैठक 6.45 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

**मुख्य मंत्री :** हमने प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखते हुए कार्य किया। हमने सबसे अधिक भर्तियां की। पुलिस में भर्तियों का दौर शुरू किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि अभी पुलिस में 1,000 भर्तियां की जा रही हैं और उसके बाद 1000 भर्तियां और की जाएंगी। कई बार माननीय सदस्य नौकरियों के बारे में जानकारी मांगते हैं। सभी माननीय सदस्यों को दिसम्बर में इन नौकरियों का पूरा हिसाब उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि, कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर कभी सरकार के खिलाफ और कभी मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रचार करते हैं। उनका एक प्रचारक है जो दीप कमल में बैठा होता है और वहीं से अपना प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करता रहता है यानी ये सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं।

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

20-3-2026/1830/NS-YK/1

मुख्य मंत्री ----जारी

यहां वॉकआउट करके नीचे संबोधित करना चाह रहे हैं। इनसे पूछना तो यह चाहिए कि आप आज तक इन सवा तीन वर्षों में कोई फैक्ट्स लाए हैं। यहां वे मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं जिनके ऊपर आज तक सवा तीन वर्षों में एक भी आरोप नहीं लगा। सी0बी0आई0 और ई0डी0 इनकी हैं, जो मर्जी करना है एफिडेविट दो और इन्क्वायरी करवा लो। आपको कौन रोक रहा है? हमने चिट्टे के खिलाफ आंदोलन किया। श्री जय राम ठाकुर जी का मुझे यह नहीं समझ आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप मैराथन में हाथ हिला रहे हैं। अब बच्चे छोटे हैं, अपने मुख्य मंत्री को हाथ हिला रहे हैं तो मैं उनको हाथ न हिलाऊं तो और क्या करूं? फिर कहते हैं कि हमें भी बुला लिया करें। अब समझ नहीं आ रहा है कि आप आना चाह रहे हैं। ये कई बार आते भी नहीं हैं। धर्मशाला में सभी माननीय सदस्यों को इन्विटेशन दिया गया कि आप इस मैराथन में आइए। ये आए ही नहीं और कहा कि इसमें आपकी फोटो लगी है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति सुखविन्द्र सिंह सुख्खु हो सकता है लेकिन मुख्य मंत्री के तौर पर भावना होती है कि हम चिट्टे के खिलाफ आंदोलन करें। कौन मुख्य मंत्री चिट्टे के खिलाफ सड़कों पर चलता है? अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे मंत्रिमण्डल के सारे सदस्य सड़कों पर चले। पुलिस वालों को पुलिस वालों ने पकड़ा। अध्यक्ष महोदय, ये सवेरे नीचे लड़ कर आते हैं या इनको ऐसे लगता है कि दूसरे गुट के जो विधायक हैं वे आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि यह आज की अखबार है। अभी प्रश्नकाल शुरू भी नहीं हुआ होता है तो पहले ही आपसे समय मांगने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मैं आपको टाइम देता हूं लेकिन ये पढ़ने लग गए। इनको समझना चाहिए और ये प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। वर्ष 2027 में चुनाव होते हैं या नहीं, वह अलग बात है। आप किस दिशा में सोच कर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप वित्त मंत्री भी रहे हैं और आपको किसी ने बोल दिया कि 98,000 करोड़ रुपये का अनुदान बजट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी बजट बढ़ सकता है? जितने का बजट प्रेजेंट किया है यह कानूनी दस्तावेज होता है तो क्या कभी बढ़ सकता है? फिर बात की दिशा को बदलने की कोशिश करते हैं और कहने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक

और नई बात बोल दी कि हमारी सर्विलांस हो रही है। सर्विलांस उनकी होती है जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब किसकी सर्विलांस होती है वह तो

20-3-2026/1830/NS-YK/2

डी0जी0पी0 ने तय करना होता है। ऐसे ही कह देना ठीक बात नहीं है। क्या इनके पास कोई फैक्ट्स हैं या कोई प्रूफ है? हमेशा झूठ ही बोलना और आकर आरोप लगाना तथा जोर-जोर से चीखते हैं। अच्छी बात है, आप जोर से चीखिए। मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में आपस में ही मुकाबला है और श्री बिक्रम सिंह जी भी कुछ बनना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आसपास वाले जो चुप बैठे हैं उनमें ही कोई होगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है। इनका बुरा हाल है। हमारे खिलाड़ी वहां अच्छा खेल रहे हैं और 20 वर्षों तक कांग्रेस की राजनीति को खेलते आए हैं। वे जानते हैं कि किसको गोल करना है और किसको आउट करना है? कई लोग इनमें आउट होने हैं। हमने राज्यसभा के चुनाव में कहा कि किसी और को ले जाना है तो ले जाओ लेकिन कोई लेने नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, आपका इतना डर है कि वे आए ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय, हम रोज़गार के अवसर पैदा कर रहे हैं। हम सभी बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। यहां पर विपक्ष बैठा नहीं है और मुझे इनके सामने बोलने में आनन्द आता है। हमने लगभग 3800 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है और हमने एक ऐसा बिल भी पारित किया है जिससे विधवाएं और अनाथ बच्चे जीवन भर सुरक्षित रहेंगे। यह पैसा उनके लिए जाएगा और इस बिल के माध्यम से उनका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि इन बच्चों की माता-पिता सरकार ही है। हमारी सरकार इनको Children of the State का दर्जा देने जा रही है। उनका कानूनी अधिकार होगा कि सरकार उन पर पैसा खर्च करे और कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। हम उनका यह अधिकार सुनिश्चित करने जा रहे हैं। यही हमारी सरकार की मंशा है। जब सरकार जनता के दुःख को अपनाकर योजनाएं बनाती है, जब सरकार किसान की सोच को आगे बढ़ा कर योजनाएं बनाती है, जब सरकार मजदूर के अधिकारों की रक्षा के लिए योजनाएं बनाती है, महिलाओं के सम्मान के लिए योजनाएं बनाती है और अपने आपसे सोच कर जो योजनाएं

बनाती है उसको ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं तथा यह व्यवस्था परिवर्तन का ही स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ।

आर०के०एस० द्वारा---जारी

20.03.2026/1835/RKS/AG-1

### **मुख्य मंत्री जारी...**

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है जिस पर माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**अध्यक्ष :** अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूँ। तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का 16 फरवरी, 2026 को उन्हें संबोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

### **प्रस्ताव स्वीकार ।**

अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**दिनांक: 20 मार्च, 2026**  
**शिमला-171004.**

**यशपाल शर्मा**  
**सचिव।**

**Himachal Pradesh Vidhan Sabha Debates**

Uncorrected and unedited/Not for Publication

Dated: Friday, 20 March, 2026

---